nt>

14.46 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Internal Security in the country

Title: Discussion regarding matters relating to internal security in the country. (Not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion under rule 193 regarding matters relating to internal security in the country.

Shri Ramji Lal Suman.

श्री रामजीलाल सुमन ( ) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अधीन देश की आंतरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में यह सदन आज चर्चा कर रहा है। देश के सामने गम्भीर संकट है। विशेा रूप से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, उत्तर-पूर्व के राज्यों में उग्रवादी संगठनों की हरकतें और हिन्दुस्तान में तेजी से बढ़ता हुआ नक्सलवाद, देश की ये तीन प्रमुख बड़ी समस्याएं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कश्मीर की समस्या है, सदन में उस पर एक बार नहीं, अनेक बार चर्चा हो चुकी है। मेरे पास इस बात के आंकड़े उपलब्ध हैं कि किस वर्ा वहां कितने आतंकवादी मारे गए, कितने जवान शहीद हुए और कितने नागरिक मारे गए। लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। यह बात सही है कि अब भी हमारे देश में तेजी से घुसपैठ जारी है। हमने अभी-अभी अपनी सरहदों से फौजें हटाई हैं। सरकार के पास निश्चित जानकारी होगी, सम्भवतः ऐसे हालात बने होंगे, जिससे फौजों की वापसी जरूरी हुई होगी। लेकिन महमूद बट्ट साहब की पुत्रवधू ने हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों का प्रशिक्षण अब भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल विज का बयान कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में छपा है कि घुसपैठ बढ़ती जा रही है। उस परिस्थिति में जब आपने सरहदों से फौजें हटाई हैं, इसकी जरूर समीक्षा होनी चाहिए।

यह अजीबो-गरीब स्थिति है कि हमारी पाकिस्तान के साथ बराबर बातचीत भी होती रही है, हमारी कोशिश होती रही है कि तनाव कम हो, लेकिन मैं उस कारण को नहीं जानता जो मनोवैज्ञानिक दबाव और प्रभाव घुसपैठियों पर इस सरकार का बनना चाहिए, वह बनाने में हम अभी तक असफल रहे हैं। सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अन्य साथी भी अपनी-अपनी बातों का यहां जिक्र करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों खासतौर पर असम की भी समस्या है। हाल ही में उत्तर-पूर्वी राज्यों में जो स्थिति खराब हुई उनमें मणिपुर भी था। मणिपुर हमारी सीमावर्ती राज्य है। उसकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। पहले वह एक रियासत थी, जिसका 1949 में भारतीय संघ में विलय हुआ था। उस राज्य में 18 से लेकर 30 उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। यह बात सही है कि मणिपुर हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और हमें उस पर नाज़ है। वहां हालात और स्थिति कैसे बिगड़ी यह विचारणीय बात है लेकिन वहां बहुसंख्यक लोग अमन पसंद हैं। वहां की 70 प्रतिशत जनसंख्या मैथी लोगों की है जो स्वभाव से शांत है और शेा 30 प्रतिशत नागा और कूकी लोग हैं।

सभापति महोदय, वहां पर जुलाई-अगस्त में तनाव हुआ था। उसका कारण हमारे सुरक्षा बलों का वहां की एक मनोरमा नाम की महिला के साथ किया गया व्यवहार था। कहा यह गया कि उसके साथ बलात्कार हुआ और बाद में उसकी हत्या की गयी। वहां 1958 का एक एक्ट है जिसमें सन् 1972 में संशोधन हुआ था। यह बात सही है कि कभी-कभी हालात पर काबू पाने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है लेकिन यह भी सही है कि जब सुरक्षा बलों को ज्यादा शक्ति दे दी जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। सुरक्षा बलों को शक्ति देने के साथ यह भी देखने की आवश्यकता है कि वे उसका दुरुपयोग न करें। मणिपुर में हालात खराब होने के कारणों में लोगों की बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी और गरीबी भी है, जिसे नजर-अंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहां पर शिक्षित लड़के-लड़कियां बेरोजगार हैं। जब हम पूरे देश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं तो यह पाते हैं कि बेबसी, लाचारी, गरीबी और भुखमरी ने भी ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं कि आदमी हिंसक रास्ते को अख्तियार करने को मजबूर हो रहा है। मैं समझता हूं कि जब यह सरकार इस पर विचार करेगी तो निश्चित रूप से उन सब चीजों के बारे में भी विचार करेगी कि मणिपुर में इस तरह के हालात कैसे पैदा हुए? वहां जो कंगला किला था उसको आम लोगों के लिए खोलने की मांग होती रही थी, उस पर फौज का कब्जा था। वह किला आम जनता के लिए खुलवाया गया, जिससे आम लोगों में अच्छा संदेश गया। वहां के लोगों की शिकायत है कि सरकार जिस पैकेज की बात बजट और योजनाओं में करती है वह केवल बजट और योजनाओं में ही होकर रह जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उनके परम्परागत उद्योग जो खेती पर हैं, उन पर बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया है। वहां के लोगों को उनसे निजात दिलाने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी।

आज देश के सामने दूसरी जो समस्या है वह नक्सलवाद की समस्या है जो रात-दिन बढ़ रही है। बिहार और झारखंड के 150 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो नक्सलवाद की चपेट में हैं। अभी तक नक्सलवाद से केवल 11 राज्य प्रभावित थे इनका दायरा आंध्र प्रदेश, बिहार झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराट्र तक था। लेकिन अब नक्सलवाद से प्रावित राज्यों का दायरा बढ़ रहा है। सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि उत्तरांचल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक भी अब उग्र वाद से प्रभावित हैं। एक घटना कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में हुई है, जिससे साफ है कि नक्सलवाद बढ़ रहा है।

विश्व के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगले 5 वर्ाों में भूख से मरने वालों की संख्या 18 मिलियन होगी।

भारत में यह संख्या 200-222 लाख तक हो जायेगी। हमारे देश में 525 से ज्यादा जिले हैं जिनमें से 220 जिलों में हिंसा की वारदातें हुई हैं। पिछले दो दशकों में नक्सलवादियों की हिंसा से 64 हजार लोग मारे गये हैं। जहां अक्तूबर, 2003 में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 55 थी, वह वर्ा 2004 में बढ़कर 154-156 हो गई है। जब भी सदन में नक्सलवाद पर चर्चा होती है, तो मैंने उनके सारे सवाल और जवाब देखे हैं। भारत सरकार यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि यह राज्य सरकारों का विाय है और केन्द्र ने उन्हें दिशा-निर्देश दे दिये हैं। कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद राज्य सरकार का विाय नहीं है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर लोग बन्दूक से रिश्ता क्यों जोड़ लेते हैं? तमाम डिग्रियां हासिल कर लेने के बाद लोगों को रोजगार नही मिलता तो वह हिंसा की तरफ मुखातिब हो जाता है। बेकारी, बेबसी, लाचारी, क्षेत्रीय असंतुलन, िवकास का मार्ग अवरुद्ध होना -ये सब चीजें ऐसी हैं कि जब आदमी को इन्साफ नहीं मिलता तो वह हिंसा के रास्ते पर चलने के लिये बाध्य हो जाता है। दुखद पहलू और चिन्ता का विाय यह है कि लोगों का विश्वास इस व्यवस्था से हट रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि गरीब को इन्साफ नहीं मिल रहा है, इन्साफ बिक जाता है।

आम आदमी को उसका हक नहीं मिलता है। यही वे कारण हैं कि एक शान्तिप्रिय जिन्दगी जीने वाले आदमी को बन्दूक उठानी पड़ रही है। यह ठीक है कि कानून-व्य वस्था बनाये रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है लेकिन हमें इस बात के मूल में जाना होगा कि यह समस्या पैदा कैसे हुई। इसका निराकरण हम लोगों को ही करना पड़ेगा।। इसलिये इस ओर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यह राज्य का विाय नहीं बल्कि देश का विाय है। यह देश न टूटे, असतुलन पैदा न हो, हमारा जो घर है, वह घर न टूटे, जाति, भाा, धर्म और क्षेत्रीय असंतुलन के नाम पर तनाव न हो, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिये नक्सलवाद को राज्य का विाय कहकर इस मूल समस्या को टाला नहीं जा सकता, सरकार को अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में जब भी तनाव होता है, उससे निपटने के लिये बराबर पुलिस के आधुनिकीकरण की बात की जाती रही है। आज की पुलिस का ढांचा अंग्रेजों के जमाने का है। आज भी वहा सोच और वहीं मनोवृत्ति है। अंग्रेजों ने पुलिस बल की स्थापना हम लोगों पर राज करने के लिये बनाई थी। मैं समझता हूं कि आज पुलिस ढांचे में बदलाव करने की जरूरत है। दिनांक 5 अक्तूबर, 2001 को राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों का एक सम्मेलन हुआ था। इसी प्र ाकार का एक सम्मलेन मुख्यमंत्रियों का 17 नवम्बर, 2001 को हुआ था। इस सम्मलेन में गोआ और मेघालय के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। उसके बाद भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि राज्यों से सम्पर्क करके पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये एक हजार करोड़ रुपया दिया जायेगा। वह एक हजार करोड़ रुपया केन्द्र सरकार के पास है। अब यह सुनिश्चित किया गया है कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारें देंगी और 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र देगा।

15.00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, जो एक हजार करोड़ रुपये थे, उन एक हजार करोड़ रुपये में से वर्ा 2000-2001 के बीच 71.81 परसेन्ट पैसा खर्च हुआ और वर्ा 2001-2002 में सिर्फ 43.87 परसैन्ट पैसा खर्च हुआ। यह कहा गया कि राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है, राज्य यह खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं हैं और कुल मिलाकर पुलिस के आधुनिकीकरण के नाम पर, जैसे पुलिस के पास बेहतर हथियार हों, संचार उपकरण ठीक हों, अच्छे वाहन हों, कंप्यूटर आदि हों, राज्य सरकारों की माली हालत ठीक न होने के कारण भारत सरकार ने इस काम के लिए जो पैसा मंजूर किया था कि राज्यों के साथ मिलकर हम पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए एक कार्य योजना बनायेंगे, वह काम भी खटाई में पड़ गया। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए हमारे देश में राट्रीय पुलिस आयोग, धर्मवीर जी कमीशन्, रुस्तम जी कमीशन और पद्नाभन कमेटी आदि की संस्तुतियां हमारे पास हैं। ये जो विभिन्न कमीशनों और कमेटियों की संस्तुतियां पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आई हैं, मेरा अनुरोध है कि जब हम पुलिस के आधुनिकीकरण की कल्पना करें या आधुनिकीकरण करने का काम करें तो इन कमेटियों की सिफारिशों को भी हमें जरूर देखना चाहिए। क्योंकि भारत की पुलिस विकासशील देशों की तुलना में कहीं भी नहीं टिकती हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि विभिन्न अवसरों पर जो कमेटियां और आयोग बने हैं, उन पर भी हम लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए और उनकी संस्तुतियों को देखना चाहिए।

गृह मंत्री जी, गत माह देश के विभिन्न स्थानों पर जीवित सैल, बम पाये गये। यह आयात होकर हमारे देश में आये थे। हमारी सुरक्षा का काम, हमारी गुप्तचर एजेंसियों का काम कितना मजबूत है, उसका आकलन इससे किया जा सकता है। ये सुरक्षा व्यवस्था की खामियां हैं और मैं समझता हूं कि हमें इस पर ध्यान देने की आ वश्यकता है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि अभी श्री के.पी.एस. गिल का एक बयान छपा था कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमें एक बड़ी नीति अपनानी होगी जिसमें, आर्थिक नीति, प्रशासनिक सुधार, सुरक्षा व्यवस्था, विदेश नीति, आम आदमी की सुरक्षा एवं सहूलियत तथा आर्थिक विकास - इन सब चीजों को मिला करके हमें एक बड़ी नीति बनानी पड़ेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश में जो अलगाववादी शक्तियां, बढ़ती हुई हिंसा तथा जो अलगाववादी आंदोलन हैं, इनके मूल में बेबसी, लाचारी, गरीबी और बेरोजगारी है। दमन से या सरकारी सख्ती से इसके आंकड़े कुछ हद तक नीचे चले जाएं या ऊपर चले जाएँ, यह एक अलग सवाल है, लेकिन जब तक व्यवस्थित विकास नहीं होगा और हिंदुस्तान में जो उपेक्षित क्षेत्र रहे हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, इस समस्या से निजात नहीं मिल सकेगी। मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नक्सलवादी लोग हैं, वे कोई अमीर परिवारों से नहीं हैं, उनका संबंध किसी धनाढ्य परिवार से नहीं है। वे आदिवासी और गरीब इलाके के नौजवान हैं। जो कहीं रोजी-रोटी से मारे गये, कहीं भूख से मारे गये, कहीं प्यास से मारे गये। जब उन्हें लगता है कि हमारे लिए देश में कानून के दरवाजे बंद हैं, देश का संविधान हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, यह व्यवस्था हमें न्याय नहीं दे रही है। तब वे अलगाववाद का रास्ता अपनाते हैं। इसी वजह से आज देश की हालत खराब है। मेरा गृह मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि इन समस्याओं का कोई सतही इलाज नहीं है। यदि आपको समस्याओं का इलाज करना है तो आपको इनके मूल में जाना होगा।

हमें उन क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना होगा, हमें शिक्षित नौजवानों को रोज़ी-रोटी उपलब्ध करानी होगी, हमें उपेक्षित इलाकों का विकास करना पड़ेगा, तभी जाकर इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। यह देश बहुत बड़ा है और इस देश में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। कौन सा विाय राज्य का है और कौन सा विाय केन्द्र का है, इस संघीय ढांचे में जो बहस होती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हिन्दुस्तान एक घर है और इसको मज़बूत रखने की, इस घर में बँटवारा न हो, यह ज़िम्मेदारी भारत सरकार की है और उसी भावना से भारत सरकार को काम करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज की इस बहस के बाद निश्चित रूप से भारत सरकार कुछ सार्थक कदम उठाएगी जिसकी वजह से इस देश में आतंकवाद और खास तौर से इस देश की नक्सलवाद की जो समस्या है, उस पर हम लोग काबू पा सकेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, आज 13 दिसम्बर को हम अपनी आंतरिक सुरक्षा के विाय में इस सदन में बहस कर रहे हैं। 13 दिसम्बर को हमारी संसद पर हमला हुआ ता और
जो जवान इसकी रक्षा करते हुए मारे गए थे, उनको आज हमने श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

उपाध्यक्ष जी, भारतवर्ा सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित है और जो खतरे आज आंतरिक सुरक्षा को इस देश में हैं, शायद इससे पहले इतने अधिक खतरे कभी नहीं थे। अभी बहुत सी बातों का उल्लेख हुआ।

15.07 hrs. (Mr. Speaker in the Chair)

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है, नॉर्थ-ईस्ट में ज्वालामुखी भड़क रहा है, नक्सलवादी हिंसा सारे देश को ग्रसित कर रही है और उत्तर पूर्व के सातों राज्य जो विश व के सुन्दरतम प्रदेश हैं, वे सारे भी आतंकवादी हिंसा से ग्रसित हैं। वहां आई.एस.आई. के अड्डे चल रहे हैं और बहुत सी जगहों पर जेहादी मानसिकता को तैयार करने वाले मदरसों की बाढ़ सी आ रही है। ये सारे खतरे हैं और मेरा कहना यह नहीं है कि यूपीए सरकार जो केवल सात महीने पहले आई है, यह इन सारे खतरों को समाप्त कर देगी। न मुझे यह कहना है कि इन सात महीनों में ही ये खतरे पैदा हुए हैं, इससे पहले नहीं थे - यह भी मेरा तर्क नहीं है। परंतु यह मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर यूपीए सरकार चल रही है, जिस रास्ते पर यह सरकार आगे बढ़ रही है, जो कदम ये उठा रही है, जिस प्रकार से अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर किसी प्रकार से जेहादी मानसिकता के लोगों को खुश करके और मुस्लिम वोटों को लेने की अंधी दौड़ में शामिल हो रही है और जो कदम उसके लिए उठाए जा रहे हैं, वे बहुत ही गलत हैं। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please sit down. You will have ample opportunity to reply. Please let us have a structured discussion. You will have to have patience to listen to others views. You could controvert them with all the force when you get a chance.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, आज आतंकवाद के आगे घुटने टेके जा रहे हैं और आतंकवाद को समाप्त करने के बजाय, आंतरिक सुरक्षा के खतरों को नट करने के बजाय जो कदम उठाये जा रहे हैं, वे कदम उनको बढ़ावा देने वाले हैं। मैं यही कह रहा था कि इनका रास्ता गलत है, इनकी सोच गलत है। ये आपको खूबसूरत नजर आ रही हैं, पर ये राहें तबाही के घर जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं जिस समस्या का उल्लेख करना चाहता हूँ और यहां कई बार जिसको कहा गया, वह बंग्लादेश से घुसपैठ की है। बंग्लादेश से घुसपैठ के बारे में कई बयान आए। शिवराज पाटील जी का भी बयान आया। वे हमारे बहुत ही योग्य गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या घुसपैठ की उतनी नहीं है जितनी रोज़गार की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, असम के उस समय के गवर्नर और इस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर लैफ्टिनैन्ट जनरल रिटायर्ड एस.के.सिन्हा ने कुछ र्वा पूर्व एक पत्र राट्रपति जी को लिखा। वह इस सरकार के भी बहुत विश्वासपात्र हैं क्योंकि आज उनको जम्मू कश्मीर में गवर्नर बनाया हुआ है। वह पत्र बहुत लंबा है और मैं सब बातों का ज़िक्र नहीं करना चाहता, केवल दो-तीन बातें उस पत्र में से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : आप बहुत अच्छे ढंग से बोल रहे हैं, मगर गवर्नर राट्रपति जी को जो खत लिखते हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री को लिखते हैं या एक मंत्री की दूसरे मंत्री के साथ, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर के साथ बात होती है, ये सारे प्रीविलेज के अंडर आते हैं और इसे हम सदन में पेश नहीं करते हैं।â€¦ (व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, it is now in the website. It is a thing which is in the website. जिस वेबसाइट में पूरा का पूरा ब्यौरा आया है, जहां से लिया है, वह पब्लिक डाकूमेंट है। उन्होंने कुछ छिपा कर नहीं लिखा। It is an open letter. It is written there like this:

> "The unabated influx of illegal migrants from Bangladesh to Assam and the consequent perceptible change in the demographic pattern of the State has been a matter of grave concern."

MR. SPEAKER: On your statement that it is on the Internet, I am allowing you.

...(*Interruptions*)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Even if it is there on the website, it is a breach of privilege.....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Mr. Malhotra, you can refer to the substance instead of reading verbatim. You are able to do that. You can make paraphrasing instead of reading it word by word.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि बहुत से राजनीतिक दल इस बात को कम करके देखते हैं कि ये सारे परिवर्तन करके किस प्रकार से असम, बंगाल और उसके आस-पास बिहार आदि जिलों में पूरी की पूरी जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने इसके अंदर पूरा उल्लेख किया है। उन्होंने इन बातों का भी उल्लेख किया था कि इसके क्या-क्या खतरे हैं और क्या परिस्थिति पैदा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान टाइम्स में चार आर्टीकल राजेश्वर राव जी ने लिखे हैं। आपने उन्हें अभी यू.पी. का गवर्नर बनाया। उन्होंने चार आर्टीकल लिखे हैं और इन चारों आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने इसका उल्लेख किया है और यह जो इस सब-कांटीनेंट में पाकिस्तान, बंगलादेश के बाद तीसरी इस्लामिक कंट्री बनाने की साजिश है, उसका पूरा उल्लेख इन्होंने अपने चार आर्टिकल्स में किया है, जो मेरे पास हैं। राजेश्वर राव जी ने आपको जो खतरा बताया।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 1991-2001 के बीच में जनसंख्या के जो आंकड़े मेरे पास है, वे मैं आपको बताता हूं। धुबरी में मुस्लिम पापुलेशन 29.5 प्रतिशत, नॉन मुस्लिम 7.1 प्रतिशत है, गोलपाड़ा में 31.7 प्रतिशत, नॉन मुस्लिम 14.4 प्रतिशत, हैलाकांडी में मुस्लिम पापुलेशन 27.2 प्रतिशत, नॉन मुस्लिम 13,3 प्रतिशत, करीमगंज में 29.4 प्रतिशत, नॉन मुस्लिम 14.5 प्रतिशत, कछार में मुस्लिम 24.6 प्रतिशत, नॉन मुस्लिम 16.0 प्रतिशत है। ये बंगलादेश से आए हुए नहीं हैं, तो कौन लोग हैं। इन सारे जिलों में जो असम के जिले हैं, बार्डरिंग बंगलादेश, इनमें किस तरीके से पापुलेशन बढ़ रही है, किस तरह बंगलादेशी घूसपैठियों की पापुलेशन पढ़ रही है, वे इसे सिद्ध करता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद चार एरियाज़ असम के हैं - बारपेटा, नौगांव, मेरीगांव और दारंग, ये सब आंकड़े भी मैं सदन में प्रस्तुत कर देता हूं, सारे पढ़ने की मैं जरूरत नहीं समझता। Muslims as a percentage of the total population in the districts of Assam. इसके अंदर कितनी-कितनी वृद्धि हुई है, यह मैं आपको बताता हूं। धुबरी में 70.4 से बढ़ कर 74.3 प्रतिशत, गोलपाड़ा में 50.2 से बढ़ कर 53.6 प्रतिशत, हैलाकांडी में 54.8 से बढ़ कर 57.6 प्रतिशत, यानी सब में चार-चार प्रतिशत वृद्धि हुई है। ये सारी असम के डिस्ट्रिक्ट की टोटल पापुलेशन की स्थिति है। इसी तरह 1991-2000 के बीच में वेस्ट बंगाल के जो जिले हैं, जिनके बारे में श्री प्रणव दा ने भी चिन्ता प्रकट की थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने भी चिन्ता प्रकट की थी, बंगलादेश से जो जिले लग रहे हैं, उनके अंदर जो खतरे की परिस्थिति पैदा हो रही है, इनमें जहां साऊथ 24 परगनास में मुस्लिम पापुलेशन 34.2 प्रतिशत, नॉन मुस्लिम 11.5 प्रतिशत, नार्थ 24 परगनास में 23.0 प्रतिशत, नॉन मुस्लिम 22.6 प्रतिश, नादिया में 21.9 प्रतिशत, नॉन मुस्लिम 18.8 प्रतिशत, मुर्शीदाबाद में 28.4 प्रतिशत, नॉन मुस्लिम 16.4 प्रतिशत, यानी सब में 12-12 का फर्क है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ये आंक़ड़े इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अभी एक सवाल के जवाब में, हमारे यहां से जब प्रश्न पूछा गया तो उसमें श्री जायसवाल जी ने उसका उत्तर दिया। उसका उत्तर देते हुए पूरे आंकड़े ये बताए कि वहां कितने बंगलादेशी भारत में घुसपैठ करके आए हैं। उन आंकड़ों में उन्होंने बताया कि 1,20,53,950 बंगलादेशी घुसपैठ करके भारत में आए हैं।

परन्तु वहां तरुण गोगोई साहब ने एकदम से यह बयान दिया और यह कहा कि ये सारे आंकड़े गलत पेश किये जा रहे हैं, यहां तो बंगलादेशी घुसपैठ करने वाले नहीं हैं और उसके अगले दिन ही, मुझे आश्चर्य हुआ, जायसवाल जी ने, जिन्होंने यहां बयान दिया था, एक और बयान दे दिया और यह कहा कि ये जो मैंने आंकड़े दिये थे, ये सुनी-सुनाई बातों पर निर्भर करते हैं। ये आंकड़े ऐसे आंकड़े नहीं हैं, जो सिद्ध हो सकें। क्या पार्लियामेंट को इस तरीके से लिया जाता है, पार्लियामेंट में आप क्वश्चन के रिप्लाई सुनी-सुनाई बातों पर करते हैं और जो खतरे हैं, उनको मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सरकार गिर जायेगी, वहां पर उनका

वोट बैंक बंगलादेशी घुसपैठियों का है ही और उसके आधार पर उनको अपने साथ रखने के लिए उन्होंने यह कह दिया कि यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई बंगलादेशी इन्फिल्ट्रेशन नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का जजमेण्ट, डायरैक्शन, अभी तो परसों एक आया है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को भी नोटिस दिया है। उस नोटिस के साथ उससे पहले वाला जो सुप्रीम कोर्ट का डायरैक्शन, जो स्टेट्समैन अखबार में आया था:

> "The Supreme Court asked the Centre and four States, West Bengal, Assam, Tripura and Meghalaya to explain within four weeks the steps taken to stem the flow of Bangladeshi migrants into the country. They have also been asked to file a status report on the fencing of Bangladesh border. The Court passed the order after the Centre admitted that the population of Bangladeshi migrants has risen from one crore to nearly two crores in the last few years. "

हाई कोर्ट का यह आर्डर है और उसमें उन्होंने कहा है:

> "On September 24, the High Court has directed the Delhi Police and other authorities to take steps as per the action plan and submit a monthly progress report in the Court. It has also told the authorities to identify such illegal migrants totalling around 13 lakhs who had earlier been allotted alternative residential plots under welfare
>
> schemes for slum dwellers. The Court also issued notice to the Government on an application seeking a probe on reports of illegal Bangladeshi and Pakistani migrants joining the army. "

यह हाई कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। मैं यह कह रहा था कि बजाय यह कहने के कि हां यह चीज है, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि 200 व्यक्तियों को प्रतिदिन बंगलादेशियों को दिल्ली से बाहर निकाला जाये। वे 13 लाख हैं, आखिर यह सवाल एक बहुत बड़ी साजिश का तरीका है। यहां पर बंगलादेश के सारे आसपास के जिले जिस दिन मेजोरिटी के हो जायेंगे, उस दिन फिर से यह मांग एक अलग बंगलादेश बनाने की उठेगी और उसके अन्दर इन सब को ले जाने की बात होगी। बहुत-बड़ा आन्तरिक सुरक्षा का खतरा है, परन्तु उसकी जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि नही-नहीं, यह तो रोजगार के लिए चले आ रहे हैं या यह कहा जा रहा है कि यहां पर आकर कोई ज्यादा घुसपैठ नहीं है, तरुण गोगोई साहब कहें या दूसरे, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक वृत्ति है और इसलिए मैंने कहा था कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, बजाय इसके कि सुप्रीम और हाई कोर्ट के फैसले को मानें, आप उसको मिनिमाइज करके, कम दिखाकर या कोई खतरा नहीं है, इस बात को सिद्ध करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं।

जैसे कहते थे कि अरबों रुपये हमने खर्च कर दिये कि इस देश में जनसंख्या किसी तरह से कम हो जाये, परन्तु बंगलादेश से लोग आते चले जायें। अपने यहां आप 10 साल में एक, दो, 10, 15, 20, 25 या 30 लाख लोग कम करें और 10 साल में वहां से दो करोड़ और आ जायें। हम दो, हमारे दो, पर बंगलादेश से आने दो। वहां से लोग आते जायें, हम दो और हमारे दो का नारा हम लगाते रहें, परन्तु ये बंगलादेश से आयें। यह उनके यहां का सवाल हो सकता है, पर हमारे अपने लोग भी तो हैं, उनको भी तो 30-35 परसेंट गरीबी की रेखा के नीचे लोग रहते हैं, उनके रोजगार का क्या हो। ये लोग जो आते हैं, इनमें बहुत सी चीजों में लोग शामिल हैं, स्पाइनेज में शामिल हैं, आई.एस.आई. की एक्टिविटीज में शामिल हैं, यह भी एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूं कि इस खतरे की ओर जिस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए, वैसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

दूसरी बात मुझे जम्मू और कश्मीर के बारे में कहनी है। मैं ज्यादा आंकड़े आपके सामने नहीं देना चाहता, आंकड़े इसलिए नहीं देना चाहता कि प्रणव मुकर्जी साहब ने और पाटिल साहब ने, दोनों ने अलग-अलग तरह के कुछ आंकड़े दिये। उस दिन शिवराज पाटिल साहब ने बड़ी रोजी पिक्चर पेश की थी। परन्तु अगले ही दिन मुकर्जी साहब ने इस बात को मान लिया कि घुसपैठ बढ़ रही है और इन दिनों में, नवम्बर के महीनों में घुसपैठ बहुत बढ़ी है।

उन्होंने यह भी माना कि पाकिस्तान में 67 अड्डे चल रहे हैं, पाकिस्तान ने उन्हें खत्म नहीं किया। इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की तरफ से उनको सहायता जारी है। मैं सारी चीजों को पढ़कर सुनाऊं कि क्या-क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, पुलिस के कितने लोग मारे गए, सेना के कितने लोग मारे गए, ये अखबारों के आंकड़े हैं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जो वक्तव्य आए, वे आपत्तिजनक हैं। मैं उनका उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं। पहला बयान प्रधान मंत्री जी की तरफ से आया जिसे उन्होंने बाद में थोड़ा मॉडीफाई किया। यह कहा गया कि all options are open. जिस दिन यह बयान दिया गया, वह काफी खतरनाक बयान था। All options are open में सब कुछ आता है। जम्मू कश्मीर भी आता है, उसका जाना भी आता है। उनके मुंह से यह बयान कैसे निकल गया, मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब आजादी भी है, इसका मतलब सब कुछ है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि क्या बात हो गई तो उन्होंने उसे थोड़ा मॉडीफाई किया कि वह इंटरनैशनल सीमाओं को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। कौन्सटीट्यूशन में किसी को भी एक इंच भूमि देने का अधिकार नहीं है। परन्तु पहले दिन यह बयान दिया गया। फिर और बयान आया कि श्री मुशर्रफ ने जो बयान दिया, जिसमें कहा गया था कि इसके सात अलग-अलग रीजन कर दिए जाएं और सात रीजन बनाकर, हर रीजन के बारे में अलग-अलग बातचीत की जाए। हमारी सरकार की तरफ से बयान आया कि उन्होंने यह रोज़ा इफ्तार की पार्टी में कहा था, लेकिन अगर वे सीरियसली कहें तो हम कंसीडर करने को तैयार हैं - क्या कंसीडर करने को तैयार है? क्या जम्मू कश्मीर के सात अलग-अलग हिस्से बनेंगे? कोई मुस्लिम मेजॉरिटी है, कोई हिन्दू मेजॉरिटी है। जम्मू में हिन्दू मेजॉरिटी है, लद्दाख में बौद्ध मेज़ॉरिटी है, वैली में मुस्लिम मेजॉरिटी है।â€¦ (व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Prof. Malhotra, will you yield for a minute?

जो बताया जा रहा है, वह थोड़ा तथ्यो से परे है। श्री प्रणब मुखर्जी ने राज्य सभा में जो बयान दिया, वह था कि सितम्बर और अक्टूबर दो महीनों में क्या अंतर था। सितम्बर में जो इनफिल्ट्रेशन हुआ, उससे ज्यादा अक्टूबर में हुआ था। आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री और डिफैंस मिनिस्ट्री के बयान में अंतर है। यह दुरुस्त बात नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम किसी भी विाय पर बात कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हम किसी प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं। यह भी गलत है।â€¦ (व्यवधान)तीसरी बात,

आप कह रहे हैं कि हम श्री मुशर्रफ के बयान को कंसीडर करेंगे। सारी चीजें कही जाती हैं। आप बोल सकते हैं कि श्री मुशर्रफ ने जो कुछ कहा था, उस पर हमें कमैंट करने के लिए कहा गया। हम कहेंगे कि ऐसे कैसे कमैंट करेंगे।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you can give answer when you reply to the debate. Prof. Malhotra, subject to that, you speak.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उनके बयान, श्री मुखर्जी और प्रधान मंत्री जी के बयान, मणिपुर में कहां अलग-अलग है, जम्मू कश्मीर में कहां-कहां अलग है, we will place all the facts before you किसात हिस्से नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी वैली है। इसलिए उसके बारे में अलग विचार नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के संबंध में पार्लियामैंट के दोनों सदनों का यूनैनीमस रैजोल्यूशन है। Why did you not reject it outright? हम में से हरेक उससे बंधा हुआ है। Each one of us is bound by that. पार्लियामैंट के रैजोल्यूशन से बाहर नहीं जा सकता, भारत के संविधान से बाहर नहीं जा सकता, जम्मू कश्मीर कौन्सटीट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता। किसने किसे इस बात की अनुमति दी है कि आप पूरा कीजिए और हमें फार्मली भेज दें तो हम विचार करेंगे। यह कैसे हो सकता है कि जम्मू के बारे में अलग विचार होगा, वैली के बारे में अलग विचार होगा। मैंने तीन बातों का उल्लेख किया है।

मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहता हूं। आपने कहा, शिवराज जी बहुत योग्यता से खड़े होकर कहेंगे कि इसका यह अर्थ नहीं है। जम्मू-कश्मीर की आटोनामी में Sky is the limit. यह वक्तव्य भारत सरकार के एक मंत्री का ऑन रिकार्ड है।â€¦ (व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : यह किस मंत्री का वक्तव्य है ? â€¦ (व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह का वक्तव्य है।â€¦ (व्यवधान)

On this very point, I am prepared यहां पर अगर मैं पेश कर दूं कि यह उनका वक्तव्य है तो क्या आप सदन से माफी मांगेंगे ? â€¦ (व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं माफी तो मांग लूंगा, वह अलग बात है लेकिन आपके ऊपर प्रिविलेज हो जायेगा।â€¦ (व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Otherwise, I will come and apologise. He said that sky is the limit as far as autonomy is concerned.जम्मू आटोनॉमी नहीं मांग रहा। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: He has said that he would speak very aggressively in the House. You accept that.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जम्मू आटोनॉमी नहीं मांग रहा, लद्दाख आटोनॉमी नहीं मांग रहा सिर्फ कश्मीर वेली आटोनॉमी मांग रही है। कश्मीर वेली की आटोनॉमी में, स्काई इज दी लिमिट से क्या मतलब है ? जब आप कहते हैं कि स्काई इज दी लिमिट, मुस्लिम मैजोरिटी है इसलिए स्काई इज दी लिमिट। अगर हिन्दुस्तान में 13 करोड़ मुसलमान ठीक प्रकार से रह सकते हैं तो कश्मीर वेली के 40 लाख मुसलमान भारत में क्यों नहीं रह सकते ? उनके लिए आटोनॉमी क्यों अलग चाहिए ? क्यों उनके लिए आप कहते हैं कि स्काई इज दी लिमिट। सिर्फ इसलिए कि दो राट्रों के सिद्धांत की बात है। हिन्दु और मुसलमान की अलग-अलग कौमियत है और उनके अलग-अलग हित हैं। इस सिद्धांत के लिए आप उसके सामने सरेंडर करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि कश्मीर वेली को और आटोनॉमी चाहिए तो हम देंगे। कश्मीर वेली में क्या खास बात है जो आप पंजाब को नहीं देंगे, दिल्ली को नहीं देंगे, महाराट्र को नहीं देंगे। वह इसलिए कि वहां पर मुसलिम मैजोरिटी है। वहां मुस्लिम मैजोरिटी है इसलिए आप कहेंगे कि मुस्लिम मैजोरिटी कहीं पर होगी तो हम उनके लिए अलग से विचार करेंगे, यह थीकिंग और विचार बिल्कुल गलत है। यह विचार देश के लिए घातक है, यही बात मैं कहना चाहता हूं। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आपको वे जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : चौथी बात जिसे मैं बहुत आपत्तिजनक समझता हूं, वह भी श्री शिवराज पाटिल जी का ही बयान है। श्री शिवराज पाटिल जी ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, उनको हम भाई मानकर चलें। अगर आप कहें तो मैं इसे भी पढ़ दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि यह किसने कहा है। â€¦ (व्यवधान)

श्री शिवराज वी. पाटिल : हां,मैंने इसे कहा है। â€¦ (व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं आपके सामने तीन-चार चीजें पढ़ना चाहता हूं।â€¦ (व्यवधान) "Five of a family massacred in Rajouri." A retired soldier and four of his family members, including a three-year-old child and two women were shot dead by terrorists of Lashkar-e-Toiba outfit in Rajouri district today. शहनाज रोती रही और जेहादी अपनी हवस पूरी करते रहे। डर से कांपती शहनाज का जिस्म आतंकी रात भर नोचते रहे। वह रो-रो कर रहम की फरियाद करती रही। इंसानियत और इस्लाम के नाम पर दया की भीख मांगती रही तब भी जेहादियों ने उसे नहीं बक्शा। उन शब्दों को मैं पढ़ना नहीं चाहता कि सिगरेट से जलाते रहे। बलात्कार के बाद उसे लोहे की सलाखों से पीटा गया और गला काट कर मार दिया क्योंकि उसके पति और ससुर ने जंगे आजादी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। यह आगे बहुत लंबा है। आतंकवादियों ने महिलाओं के नाक, कान, जीभ काट डाले। ये सब मुसलमान हैं जिनके बारे में मैं पढ़ रहा हूं। लश्कर-ए-तोयबा उग्रवादियों ने एक ही परिवार के 40 लोगों को मार डाला, एक हजार महिलाओं का खून किया, 80 हजार लोगों को उन्होंने मार डाला और आप कहते है कि हम उन्हें भाई मानकर चल रहे हैं। ये लोग है जिनको आप भाई मानकर चल रहे हैं, अगर उनको हम भाई मानेंगे तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे ? आप उन आतंकवादियों को, नृशंस हत्यारों को, बलात्कारियों को, जो जेहादी मानसिकता के होते हैं, वे कोई ऐसे नहीं कि यहां से भटके हुए हैं, वे बहुत ही मोटीवेशन के साथ यहां आये हुए हैं। आप कहते हैं कि हम उनको भाई मानकर चल रहे हैं और उसे आप रिकार्ड पर कहते हैं। फिर कहते हैं कि हां, मैंने कहा था। ये लोग जो इस प्रकार के हैं, क्या ये हमारे भाई हो सकते हैं? अगर हमारे भाई हैं और सारे देश में मानवाधिकारी उनके मान वाधिकार की बात करते हुए चलते हैं तो ये जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके भी कोई मानवाधिकार हैं या नहीं ? उन बहनों के क्या कोई मानवाधिकार हैं, जिनके साथ बलात्कार होता है, जिनके अंग काट दिये जाते हैं, जिनके शरीर में से कलेजा निकाल दिया जाता है, दिल निकाल दिया जाता है, गला रेंत-रेंत कर मार दिया जाता है, डूबो-डूबो कर मारा जाता है ताकि वे किसी तरह से पाकिस्तान के साथ इस प्रकार की बातचीत न करें। उन्हें हम कैसे भाई मानकर चलें। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You should avoid such descriptions.

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष जी, हमें भी बोलना है।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी, आपका लिस्ट में नाम है। तब बोलिएगा।

â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Order in the House please.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ऐसी घटनाएं पहले भी हुईं थीं परंतु किसी गृह मंत्री ने यह नहीं कहा कि हम इनको भाई मानकर चल रहे हैं। इसलिए हम इनको रोजगार दे दें। क्या रोजगार देने से ऐसे लोग बदल जाएंगे ? इस प्रकार भाई मानकर हम कभी आतंकवाद या देश के खतरों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने पांच लाख पंडितों को शरणार्थी बना रखा है और ये एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। मैंने प्रणव दास का बयान देखा है। It is a proxy war. जो लोग प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, वे हमारे भाई कैसे हो सकते हैं ? देश को सबसे बड़ा खतरा तो इसी मनोवृत्ति से है कि हम उनको भाई मानें जो इस प्रकार का कांड कर रहे हैं।

मैंने नैक्सेलाइट हिंसा के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। मैं नैक्सेलाइट हिंसा के बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं और शिवराज जी का उसमें भी बयान है कि They are our children. उत्तर प्रदेश में नैक्सेलाइट हिंसा का यह कांड हुआ। वहां पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 31 पी.ए.सी. के पर्सनल जा रहे थे जब उनकी गाड़ी को उड़ाया गया और उस प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैंने इनको जब वहां पर देखा तो वहां 100, 150 थे। उनमें से कोई मरा नहीं था। एक की भी डैथ नहीं हुई थी परंतु वे लोग यह देखकर भागे और भागने के बाद नैक्सेलाइट हिंसा करने वाले जो लोग थे, उन्होंने वहां आकर सब घायलों को इकट्ठा किया। उनके सिरों में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इन लोगों का अपना कमिटमेंट है। उसके मुताबिक यह कार्रवाई हो रही है और यह कार्रवाई कहां से शुरू हुई? यह कार्रवाई नेपाल से शुरू होकर देश में फैलती जा रही है। सारे जिलों में फैलती जा रही हैं परंतु उसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं।

सबसे बड़ी बात आन्ध्र प्रदेश में इन्होंने यह कही कि आन्ध्र में कहा कि उनसे समझौता करो, उनसे बातचीत करो। वे हथियार छोड़ें या न छोड़ें, बिना हथियार छोड़ें बातचीत के लिए आएं, अपने हथियारों को लेकर आएं और उन्होंने वहां पर हथियारों का प्रदर्शन किया और आप सारे देश को कह रहे हैं कि जो आन्ध्र ने किया, वैसा ही तुम भी करो। स्पेशल पॉवर्स को समाप्त करो। इसी तरह से इन लोगों के ज्यादा हौसले बढ़ते हैं, उनके साधन बढ़ते हैं, उनको ज्यादा पैसा प्राप्त होता है चाहे वह आई.एस.आई. दे या दूसरा दे। इसलिए नैक्सेलाइट को रोजगार ज्यादा दें जिससे वे लोग न भटकें, परंतु नैक्सेलाइट हिंसा छुड़वाए बिना हथियारों समेत उनको निमंत्रण दें और हथियार रखने की खुली इजाजत दें, स्पेशल पॉवर्स भी खत्म कर दें और देश भर में जिस प्रकार से पिछले साल South Asia Intelligence Review Vol.III, No.19 में इन्होंने बताया कि पिछले साल नवम्बर के महीने में यहां पर 'Total, the dramatic expansion of Naxalite activities from just 55 districts across nine States in the country in November 2003 to as many as 156 districts in 13 States by September 2004.' एक साल में यहां पर आपकी नीतियों के कारण 55 जिले इनके प्रभाव में थे। 156 जिले उनके प्रभाव में आ गये और धीरे-धीरे बाकी जिले भी आ जाएं और वे जिले उनके प्रभाव में आ जाएं और नैक्सेलाइट हिंसा देश में बढ़ती रहे। उससे देश में क्या स्थिति बनेगी? इसलिए मैंने कहा कि जो रास्ता चुना है, वह रास्ता ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, नक्लवादी हिंसा के बाद मैं एकाध उल्लेख और कहना चाहूंगा, जिसमें मदरसों के बारे में प्रमुख है। मदरसों के बारे में उल्लेख होता है, तो कोशिश की जा रही है कि वहां फिजिक्स, कैमिस्ट्री और अन्य विाय पढ़ाए जाएंगे। वहां कोई इस तरह का वातावरण नहीं बनाया जाए, जिससे लगे कि कुछ अनुचित हो रहा है। सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। उस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वह गृह मंत्री जी के पास भी जरूर होगी। उसमें जो बातें कही गई हैं, उनमें से मैं दो-तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। टास्क फोर्स की जो पब्लिक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है :-

> "In several cases, considerable foreign funds have become available to these institutions through non-banking institutions. Efforts at Arabicization of Muslims and their education is a matter of concern which should not be dismissed light-heartedly. Bringing the educational curriculum of *madrasas* into the mainstream by the inclusion of subjects such as physics, chemistry, mathematics, information technology and so on is a major challenge which must be accepted in the long term interest of the country. â€¦.
>
> In *maktabs* and *madrasas*, young students are taught Urdu, Arabic and even Persian languages and imparted instruction in the teachings of Islam. Focus is on traditional religious teaching, and modern subjects are not there.
>
> There has been mushrooming and visible growth of mosques and *madrasas* all along our international borders. The intriguing thing is that these have come up where there is a very small or no population of the minority community â€.." ...(*Interruptions*)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I have to object to this. He is quoting from something. He has to authenticate it and put on the Table of the House. ...(*Interruptions*) Anything which is quoted has to be authenticated. ...(*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I will do it. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He has agreed.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, the Task Force has proceeded to provide specific figures about the way etc....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Whose Task Force?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : भारत सरकार ने कारगिल वार के बाद यह किया।

It further says:

> "On the Indo-Bangladesh border, growth of *madrasas/*mosques is taking place along with a shift in demographic composition due to illegal immigration of a large number of people from Bangladesh into the border districts in India. Increasing crowding out of economic opportunities for the local population and the shift towards Islamization â€¦ "

MD. SALIM (CALCUTTA − NORTH EAST): Sir, he is reading out the Report of the Task Force constituted by the Home Ministry. The Members are not privy to that Report. If he, as a special Member, is having this Report, he should place it with his authentication. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He has already undertaken to do that, Mr. Salim.

...(*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जितना पोर्शन मैंने पढ़ा है, वह मैं रख देता हूं।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I have to submit one thing. After the Kargil war, a Committee was constituted to look into the causes, and the Report was given by Shri Subramanian. That Report was examined by a Group of Ministers, and this Group of Ministers had constituted some Task Force and they had examined it. The Report given by the Task Force to the Government of India is a secret document. That is number one.

Secondly, what has been stated by the Ministers in the Group of Ministers is not secret but this Report is secret. Moreover, whether this forms part of that Report or not, one does not know. That is why, he has to authenticate it also. ...(*Interruptions*)

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : यहां पर जितना ऑब्जेक्शन हो रहा है, मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि ये जो मदरसे हैं, हालांकि सरकारी आंकड़ों में कहा गया हैâ€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You just refer to the gist and authenticate it.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, *madrasas* in some places are reported ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You have to apply your judgment also, Prof. Malhotra.

...(*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कहा गया है कि सभी मदरसों की स्थिति ऐसी है।

MR. SPEAKER: Kindly authenticate it. Otherwise, it will be deleted.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जितने भी मदरसे हैं, हम सभी चाहते हैं कि वहां अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी मदरसे के बारे में कहा जाए कि वहां कुछ अनुचित हो रहा है, उसकी जांच नहीं की जाए, यह नहीं देखा जाए कि वहां कैसे आईएसआई अपने पांव जमा रही है और लोगों को बहका रही है, इन सब चीजों को सरकार को देखना चाहिए।

मैं तीन-चार बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रणव साहब ने आज अमेरिका के बारे में जो कहा, वह ठीक कहा। भारत के अंदर जो आतंकवाद है, अमेरिका का रवैया उस संदर्भ में निहायत ही अफसोसनाक है। वह इसलिए कि अमेरिका ने दावा किया है कि वह विश्व में आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई का अगुवा है, अग्रणी है, वह दावा भी गलत साबित होता जा रहा है और वह केवल अब बयानबाजी ही रह गया है। यह एक तरह का ढोंग है, क्योंकि पाकिस्तान को एफ-16 विमान देना, पाकिस्तान को खरबों रुपए की सहायता देना उसके इस दावे को गलत सिद्ध करता है। वह जो खरबों रुपए की मदद पाकिस्तान को दे रहा है, आईएसआई के माध्यम से हिन्दुस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, इस काम के लिए वह रुपया दिया जा रहा है।

वह रुपया उनको दिया जा रहा है, उनको हथियार दिये जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। जम्मू-कश्मीर का जो पाकिस्तान की तरफ का हिस्सा है, उसके लिए अमरीका के मापदंड अलग हैं और हमारी तरफ का जो हिस्सा है उसके लिए मापदंड अलग हैं। इसकी हम निंदा करना चाहते हैं। अमरीका भी भारत में आतंक वाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को मदद कर रहा है और यह बहुत ही घातक और अफसोसनाक बात है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर पोटा को रिपील कर दिया गया। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सारी दुनिया के मुल्क आतंकवाद से निपटने के लिए कानून बना रहे हैं और भारत ऐसा पहला देश है जो पोटा

को रिपील कर रहा है। यूएनओ में आप गये थे और आपने उनसे वादा किया था। ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: It has already been discussed fully.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I know that. मैं जानता हूं सर, â€¦ (व्यवधान)देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या हम कुछ उल्लेख भी न करें। â€¦ (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : पोटा की बात खत्म हो गयीâ€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: That will be deleted.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: The speech of anybody who is speaking without my permission will be deleted.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सार्क सम्मेलन हो या दुनिया में कोई भी सम्मेलन हो, हम कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ चलो, आतंकवाद को रोकने के लिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए और अपने देश में पोटा जैसे कानून को रिपील करते हैं। बंगला देश को आमंत्रित करते हैं, आईएसआई की गतिविधियोंâ€¦ (व्यवधान)पर पर्दा डालते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बात में और जयचंदी मनोवृत्ति, मीरजाफरी मनोवृत्ति या क्विजलिंग्स के पीछे चलने में क्या अंतर हैâ€¦ (व्यवधान)इस तरह की मनोवृत्ति अगर आप रखेंगे तो देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती चली जाएगी। हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि इस रास्ते पर मत चलिये, यह रास्ता देश को बर्बाद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ियां आपको क्षमा नहीं करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाण समाप्त करता हूं।

* Not Recorded.

SHRI NIKHIL KUMAR (AURANGABAD, BIHAR): Sir, I begin by inviting the attention of the House to this very day three years ago to which hon. Prof. Vijay Kumar Malhotra had made a reference when 13 of our valiant security personnel of Parliament laid down their lives. They protected the House. They protected the symbol of democracy in this country. So, I begin by paying my homage to them, and I am sure the House will join me in paying the homage.

MR. SPEAKER: We have already done it in the morning.

SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, I am new to this House, but we have been watching how the political parties have functioned and how their Members in the House have functioned, and I am amazed both outside and now here itself. माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कहा कि जो डैमोग्राफिक परिस्थितियां थी वह असम और बंगाल के जिलों में बदल गयी। यह कहा गया कि यह पिछले 7 महीनों में हुआ है। यह पिछले सात महीनों में नहीं हुआ है, यह पिछले 10 सालों में हुआ है और उसमें 6 साल आपकी सरकार थी। गैरकानूनी माइग्रेशन को रोकने का जो सबसे कारगर तरीका है वह बार्डर पर फैंसिंग लगाना है। आप पंजाब, राजस्थान और गुजरात में फैंसिंग लगाइये। कश्मीर में फैंसिंग लगी है और उसकी वजह से इंडो-पाक बार्डर पर घुसपैठ नैगलिजिबल हो गयी है। मेरा कहना यह है कि फिर आपने बंगला देश बार्डर पर क्यों नहीं लगाई। पिछले 6 सालों से इसकी चर्चा हो रही है। इस चर्चा को सन् 1998 में पहली बार उठाया गया था और कहा गया था कि वहां फैंसिंग लगेगी। एक एजेंसी को लगाया गया और सर्वे हुआ। उसका एस्टीमेट बना और इसको लगाना तय हुआ।

जहां तक मुझे याद आता है, मई या जुलाई, 2003 तक फैन्सिंग बन जायेगी लेकिन अब यह डेट दिसम्बर, 2004 हो गयी है। मौजूदा सरकार ने फैंसिंग बनाने की पहल की है और इसे बनाने की तारीख मुकर्रर हो गई है। अगर हम लोग ओबे कर सकें तो अपने आप में यह एक उपलब्धि होगी। इससे इनफिल्ट्रेशन, इल्लीगल माइग्रेशन पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष जी, माननीय मल्होत्रा जी ने पोटा के विाय में सवाल उठाया। पोटा पर डिसकशन हो चुकी है और मैं भी इस विाय पर बोलने वाला था। चूंकि श्री मल्होत्रा जी ने बात उठायी है तो मैं समझता हूं कि उसका स्पटीकरण जरूरी है। मैं एक ऐसी बैकग्राउंड से आता हूं जो पोटा के सवाल को अच्छी तरह समझते रहे हैं।

Let us not forget that it was the Congress Government in 1985 which first thought of a special law to combat terrorism and it brought in TADA. TADA was brought into force in 1985. It was expected that it would be of great help to us in combating terrorism but in ten years' time two things happened. TADA was not able to prevent the assassination of Shri Rajiv Gandhi. Even though TADA had lapsed, its effect had been felt all over the country and especially in Punjab, where the then Chief Minister of Punjab was also assassinated. It was not because TADA was ineffective or it just had no teeth. It had to be implemented on the ground by security enforcement agencies, that is to say, the police and other paramilitary forces. If they were not doing their job, TADA or any such law would not be effective. More important is the question of its misuse. It is because of its misuse that the Congress Government had at that time in 1995 allowed TADA to lapse and did not renew the special law. It was at that time that those of our friends who are sitting on the opposite side were criticising the misuse.

When they came into Government, they brought in a special law. Now, we are being consistent in our approach. We said that this special law was not necessary and it would be misused as was done to TADA. We repealed POTA and instead brought in the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill. Let us now see how this led to a dilution.

There were three main provisions in POTA which were supposed to be of great use to the law enforcing authorities. The first one was the arrest and remand of people in judicial or police custody. The second was the question of keeping a person in police custody for a certain period of time to enable the person's interrogation. The third was the question of interception of messages. I must clarify that the new amendment has made it clear that the three major provisions of POTA have been retained, which relate to financing of terrorist organisations which are involved in terrorist activities.

श्री मोहन सिंह : बात तो वही है।

श्री निखिल कुमार : पहले पुलिस के पास जो प्रोवीजन था, जिसका वह मिसयूज किया करती थी, वह चीज हटा दी गई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर पुलिस के पास 14 दिन तक के लिये अपराधी को रिमांड पर दिया गया है, यदि वह उससे सही बात नहीं उगलवा सकी तो 30 दिन क्या, 60-90 दिन भी मिल जायें, तो भी वह नहीं उगलवा सकतीâ€¦ (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : जब माननीय सदस्य पहले पुलिस में थे, क्या उन्होंने इसका मिसयूज किया?

MR. SPEAKER: No interruptions please. He does not yield.

...(*Interruptions*)

श्री निखिल कुमार : जब मैं पुलिस में था, अगर इसका मिसयूज हुआ होता तो माननीय सदस्य को पता लग जाता या सब से पहले माननीय मल्होत्रा जी को पता लग जाता। क्योंकि ऐसा मिसयूज ही नहीं हुआ था। गुजरात में सब से पहले इसका सब से ज्यादा मिसयूज हुआ, जिस पर मै बाद में बोलूंगा।

SHRI KHARABELA SWAIN : What is the necessity of â€¦....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: He has not yielded. Nothing is being recorded. Do not get upset. We cannot change anybody's habit so easily.

*(Interruptions)**

SHRI NIKHIL KUMAR : Repeal does not mean dilution of the law to deal with terrorism. ...(*Interruptions*) Repeal does not mean dilution in the attitude towards terrorism. In that, we remain as steadfast and as strong as ever and it will be seen as to how the new law, the Unlawful Activities Prevention Act is going to be utilised and it will not be in any way less effective than POTA. ...(*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : So, itâ€¦ ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: It is not to be recorded. He has not yielded.

*(Interruptions)**

* Not Recorded

SHRI NIKHIL KUMAR : The POTA was draconian. POTA's provisions have been removed and only the normal law will now be utilised. This is a very fine distinction and I am sure you will be able to understand it, if you were able to understand the law. ...(*Interruptions*)

Now, I come to the problems and the major threat facing the internal security. Much has been said about that, so I need not repeat that. I would like to place before this House and invite the kind attention of the hon. Minister of Home Affairs to certain suggestions on how to go about dealing with these problems.

First of all, as far as terrorism is concerned -- and I am going to deal with some specifics, with your permission, Sir, -- it is necessary to draw up some kind of an operational plan of action. Unless you do that, our effort to deal with terrorism in an effective manner will not prove successful at all. We need to have a long-term perspective plan and we should have some kind of a strategy, and for this a few components will be something like this:

a. Area-specific annual plans will have to be made to counter terrorists groups active in a specific area;
b. There has to be a policy of conviction in areas where terrorists are thin on the ground and the network is relatively weak. They should be selected and through operations, they should be eliminated. Their presence should be totally eliminated from that area. Then, we should saturate this area with our own troops and with

our own security forces to see that they do not come back again;

c. There has to be a great deal of coordination. The present degree of coordination between the Centre and the State Governments is not what it should be. This should be in respect of not only plans of action but also equipment, arms, ammunition, etc. But most importantly, there has to be a very facile system of exchange of intelligence. At present, one hears that there has been put in position some kind of an organisation which will aid and assist the exchange and transfer of intelligence. But until that is done, any plan of action will not be implemented effectively.

d. At the same time, we will have to take into account the fact that we have seen in various parts of this country a concerted attempt by Left Parties. Left Wing Extremism is spreading and it has spread from Maharashtrra right through Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and into Nepal. In July, 2001, a special organisation was floated - The coordiantion Committee of Marxist parties and their organisations. It is an umbrella organisation which is overseeing coordination between all those different Left Wing Extremists Groups which have been active in these States − Maharashtra, Andhra Pradesh, Chattisgarh, Jharkhand and Bihar.

The whole idea is that they have built up links from one end of this country to another and they want to convert it into some kind of a combat revolutionary zone. This is an ideological movement and it cannot be countered as a mere law and order problem. There are socio-economic factors which have led to the rapid rise of Left-wing extremism because every possible action has been taken by the law-enforcing authorities to combat them. But they have failed. On the other hand, this whole movement has been increasing. It has been spreading all over. The most menacing development is that it has linked up with a new organisation called Kamtapuri Liberation Organisation in North Bengal. This link-up is further made more menacing by the link-up with the Maoists in Nepal. My request to the hon. Minister of Home Affairs is this : it is all very nice to enter into a dialogue with the Left-wing extremists in Andhra Pradesh. But that may not alone be the answer. First of all, this is not something that is confined to Andhra Pradesh. It is one single movement and it has leaders spread all over the country. There has to be one single coordinated approach. If there has to be a dialogue, it should be a dialogue to cover all the States which are affected.

Secondly, you must think in terms of socio-economic reforms. I come from a district and my constituency is covered by a district which is affected by Left-wing extremism. Not only my district but the whole region of South Central Bihar is affected by Left-wing extremism. We have also seen that this movement is now spreading into other parts of Bihar. I have seen that myself that there is need for socio-economic reforms in these areas.

I read in the papers that the Andhra Pradesh Government has decided to distribute one lakh acres of land in Andhra Pradesh. It is, perhaps, part of the strategy to give to the landless what they need and what is an important reason for their feeling upset with the Government and, therefore, they appear to be easy meat for the theories of the Left-wing extremists. This alone will not do. It will have to be a coordinated approach.

Some six years ago a coordination centre was set up by the Ministry of Home Affairs. It was expected that this centre would coordinate action in the policies between Centre and different States concerned. I do not know what has been the overall result of this coordination centre's activities. But if we go by the fact that this movement has spread, obviously this coordination centre has not been doing what it should have done or what was expected of it. I would, therefore, urge that this coordination centre's overall perspective should change and it should have in its view the local problems and we should come out with solutions to the local problems especially those relating to land-holding particularly.

There is a new scheme that has been introduced which is called Food-for-work scheme. Some 150 districts of this country have been chosen in which this scheme has to be implemented. I am sure the criteria followed for choosing these districts must have been very well thought out. But a good many districts which conform to the criteria have been excluded and it is these districts which are

affected by Left wing extremism for the simple reason that people in these areas are below the poverty line, they have no access to any employment and until some arrangement is made for their employment, for them to be gainfully employed particularly, we will not be in a position to combat this movement. This movement has to be combated not only in an ideological basis but also through administrative and executive steps and developmental works.

16.00 hrs.

Sir, I will now come to the question of communal sentiments. There have been, in some recent years, much written about the threat to India"s secular fabric by this communal movement. I would like to take you back to the year 1989 and a little before that when the movement of building of the temple at Ayodhya led to a countrywide agitation and in its wake came a great deal of bloodshed. If we fast-forward this period from 1989 to last year or to last two or three years, we find that the insistence of religious fundamentalism has been the cause for this movement of

communalism throughout the country.

I must, with due respect to all those who are seated opposite us, bring to the notice that whatever happened in Gujarat is a blot not only on the State itself but the whole country also. If I say this standing here, I might be taken as a person who is interested and is biased, but when the country"s topmost court, the Supreme Court also has the same view to the extent that the cases that were registered in Gujarat and were tried in Gujarat, have now been ordered to be transferred out of that State and to be tried elsewhere, it should send a signal, message to the people that we need to treat this country as a country which has a great deal of importance attached to its secular fabric and if this is to be rent asunder, then this country and its whole fabric will collapse.

माननीय विजय जी इस समय यहां नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता था कि पहले वे कहा करते थे या उनकी पार्टी कहा करती थी कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं उनसे पूछता हूं कि जब वे सरकार में थे तो क्यों नहीं बनवाया? मैं जब लोगों से मिलता हूं तो वे कहते हैं कि उन्होंने कसम खाई या नहीं खाई।â€¦ (व्यवधान)उन्होंने यह कहा है कि जितनी देर सत्ता में रहेंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। â€¦ (व्यवधान)यह जो मंदिर का बनाना है,â€¦ (व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मंदिर तो वहीं बनाएंगे।â€¦ (व्यवधान)

(Interruptions) *

* Not Recorded

MR. SPEAKER: Do not take those things.

â€¦ (व्यवधान)

श्री निखिल कुमार : हां, यह हो सकता है।â€¦ (व्यवधान)कसम राम की खाते हैं, कहते हैं कि जब तक सत्ता में रहेंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे।â€¦ (व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : अगर कोर्ट ने परमीशन नहीं दी तो हम जबरदस्ती कैसे बना सकते हैं।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, I have allowed you one intervention, but it cannot go on.

â€¦ (व्यवधान)

श्री निखिल कुमार : जो नारा था, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई नयी बात नहीं कर रहा हूं।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: He is very law-abiding. He has said that Supreme court has ordered. How could they construct it?

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are right. I have endorsed your view.

SHRI NIKHIL KUMAR : I have three small suggestions to make. First is about our border management.
...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: A very knowledgeable speech is being made.

SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, we accept that illegal migration is a serious problem and it is important to check this, but this should be done through the management of our borders. I would recommend that our border-guarding forces should be given modern arms, ammunition and every possible equipment which is modern and sophisticated, like sensors and other things, which the latest scientific technology has given to us. It should be made available to them. This should be, I suppose, adequate to enable them to detect infiltrators and take action, both by day and by night. Our own DRDO is quite capable of producing this equipment, but if it takes time, then we should look around. I am aware that there is no dearth of such equipment in the world market. I am not suggesting any specific gadgets, but I am sure that the Government will apply itself and make the right choice.

I will emphasise the need for a fast-track procurement mechanism. Often, there is much avoidable delay in the procurement process, and this does not serve our national interest.

Secondly, there is a standard strength fixed for all the Border Guarding Forces deployed on the borders. For each border, this strength has been fixed on the basis of a detailed survey, and research of the demographic complexion of the areas on either side of the border, and other problems. But large areas have been left uncovered, and this is

one reason for having the problem of infiltration. I would say that this is because of the large areas, which have been left uncovered, for practical reasons.

The Border Guarding Forces have been withdrawn from the areas of their deployment, and posted elsewhere to look after the internal security duties. If they are to be diverted from their primary duty, then obviously, they will leave large chunks of areas uncovered, and it will help, assist, and aid illegal migration. I would recommend that our paramilitary forces or the Central Police Force, which have been raised for some specific purposes, should be returned to their primary duties, and should not be taken away and posted to do other duties, which are not covered in their primary duties. If it becomes necessary, then we should even raise additional forces, but the security forces should be posted at the places of their primary duty.

Thirdly, the surveillance along the border must be supplemented by fencing. I have mentioned it in the beginning, and I would like to repeat it, so that the hon. Minister may kindly give some thought to it. I am saying this because work on the fencing is not being done at a satisfactory pace. If it is to be completed at an early date, then attention will have to be paid to it by the Government.

Fourthly, we have been discussing in this House, and even outside, and we have been paying attention to the border security, but we have not paid as much attention to our coastal security. My recommendation is twofold. Firstly, the responsibility for ensuring the security of the coastline, except the riverine belt, especially, along the Gujarat border with Pakistan, should rest with the State police. Secondly, modern watercrafts should be given to the forces guarding the coasts so that they are able to patrol the shallow waters. The Coast Guard and the Indian Navy should not be alone held responsible for this. They should be there to coordinate their efforts with the State police, which should be in-charge of the coastal security.

MR. SPEAKER: Mr. Nikhil Kumar, I have given you more than 25 minutes.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: There are other very illustrious Members also, who would like to speak on this issue.

श्री निखिल कुमार : माननीय रामजीलाल सुमन जी ने पुलिस के रिफार्म के बारे में बहुत बात की थी। â€¦ (व्यवधान)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, it is his maiden speech in the House.

MR. SPEAKER: It is all right, but it does not mean that it will be unending.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: If the Congress Party is allowing all its time to him, then I am prepared to give him more time to speak.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Mr. Nikhil Kumar, you are making very good suggestions.

SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, I was submitting for the hon. Home Minister's consideration that advanced technologies are available to us now, and this should be made use of to equip our security forces to make them more effective. The latest laser-based techniques are now available in the world market like the digital imaging and identity kit, cellular telephone data analysis, forensic narco-analysis / truth serum analysis, etc. There is no dearth of these items of equipment. I am sure we would be able to access some of them, and acquire them to be given to the security forces, so that these forces get well equipped. They would become modern, and they will not have to resort to third degree methods. With the assistance of these scientific techniques it will not be necessary to go in for the special law provisions, as was given in POTA. At the moment, the general laws will be adequate, and it should be adequately put to use.

MR. SPEAKER: Thank you very much. I compliment you on your very constructive speech.

Shri Md. Salim.

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आंतरिक सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में पूरे विश्व में इस तरह की समस्या अधिकतर देशों को झेलनी पड़ रही है, कहीं कम, कहीं ज्यादा। उसके अलग-अलग कारण हैं। चाहे राजनैतिक हों, चाहे साम्प्रदायिक हों, चाहे रंगभेद हो, चाहे जातिवादी हो या ऐथनिक मामला हो, किसी भी कारण को लेकर आंतरिक सुरक्षा की विपरीत घटनाएं घटती जा रही हैं। हमारा देश बहुत विशाल देश है। यहां कई धर्म, कई भााओं और कई जातियों के लोग रहते हैं। यह इतना विस्तृत इलाका है कि हमें ऐसी कई समस्याएं वार्ों से झेलनी पड़ रही हैं।

यूपीए सरकार इस चुनौती को मद्देनजर रखकर बनी है। हम समझ सकते हैं सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को स्वीकारे और उससे निपटे। चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत का सवाल हो, चाहे देश के अन्य भागों में, जैसे अभी कहा गया नक्सलाइट ऐक्सट्रीमिस्ट्स के नाम पर, आंध्र प्रदेश, पीडब्ल्यूजी और वहां से रीग्रुपिंग होकर चाहे उसका स्पिलओवर महाराट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, झारखंड-बिहार के बार्डर, उड़ीसा के बार्डर में हो, बंगाल में उसका स्पिलओवर हो, झारखंड-उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके में हो, चाहे नेपाल की स्थिति हो, उत्तर प्रदेश का लगा हुआ हिस्सा हो, बिहार का हिस्सा हो, उत्तरी बंगाल का हिस्सा हो.â€¦ (व्यवधान)

गुजरात भी आएगा। वह एक और समस्या है। उसके साथ साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना, अलगाववाद तो था। हम देखेंगे कि पिछले दो दशकों से अपने-अपने राजनैतिक कारणों से, रिलीजियस फंडामेंटलिज़्म का इस्तेमाल करके, लोगों की भावनाओं को उभारकर राजनीति करने से हिंसा, द्वेा और लोगों के ज़हन में ज़हर घोलने के कारण तनाव भी बढ़ा और आंतरिक सुरक्षा को भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

अभी श्री निखिल कुमार अपने अनुभव से बोल रहे थे। यहां आने से पहले वे पुलिस प्रशासन में थे। मैंने मल्होत्रा जी की बात भी सुनी। वे भी अपने अनुभव से बोल रहे थे। राजनीति के मैदान में उनकी उपलब्धि है और वे उसके आधार पर बोल रहे थे। हमारे यहां एक समस्या यह है कि हर मामले को साम्प्रदायिक प्रिज़्म में डालकर उसकी नजर से देखना, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे असम का मामला हो, चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे मंदिर-मस्जिद का मामला हो, यह लोग रंगीन चश्मा पहने रहते हैं। यह किसी एक राजनैतिक दल का मामला नहीं है, किसी देश का मामला नहीं है, पाकिस्तान में बैठे हुए जो फंडामैंटलिस्ट जमायते इस्लामी हैं, जम्मू कश्मीर में जो जमायते इस्लामी हैं या हमारे देश में जो मुस्लिम फंडामैंटलिस्ट या हिन्दू फंडामैंटलिस्ट हैं, वे सब उसे हिन्दू-मुसलमान की समस्या की तरह देखते हैं। हमें शर्म आई और अफसोस हुआ जब इस सदन में भी एक वरिठ सांसद जम्मू कश्मीर के मामले को हिन्दू और मुसलमान के मामले की तरह देख रहे थे। विदेशी ताकत हमारे देश में जो हंगामा पैदा करना चाहती हैं, यह लोग अपनी सोच और समझ से उसको बल दे रहे हैं। नजरिया अलग-अलग है लेकिन दर्शन एक ही है। यह हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा है। यूपीए सरकार आने के पीछे गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि गुजरात को पूरे देश ने देखा है। चुनाव जीतने के लिए, िवधायक या सांसद बनने के लिए किस तरह कौन्सपीरेटोरियल, साजिश के तहत ऐसी भावनाएं पैदा की जाएं, सभ्य सोसाइटी में. गुजरात शांतिवादी और खुराक की जुगाड़ करने में भी हिंसा का सहारा नहीं लेता, ऐसे लोगों को भी किस तरह हिंसा में धकेला जा सकता है।

एक पड़ोसी के खिलाफ दूसरे पड़ोसी को उतारा जाता है जिससे कुछ सीटें ज्यादा मिल जाये और सरकार बन जाये। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। यह सिर्फ हमारे देश में नहीं ही, बल्कि यूरोप में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम अफ्रीका में देखेंगे तो ऐसे राजनीतिक दर्शन का अपने-अपने तरीके से सहारा लिया जा रहा है, जहां जिसको जिस चीज का सहारा मिलता है, वह उसको ले लेता है। अमरीका में अगर चर्च का सहारा मिले तो वह चर्च का सहारा लेंगे। यहां अगर किसी को मंदिर का सहारा मिले तो वह मंदिर का सहारा लेंगे । इसी तरह पाकिस्तान और बंगलादेश में अगर मस्जिद का सहारा मिले तो वह मस्जिद का सहारा लेंगे। वे अलग-अलग चोली पहन लेंगे और इस तरह वे लोगों की भावनाओं को उभारते रहेगें । हमारे लिए समस्या है कि यह केवल देश का अंदरूनी मामला नहीं रहा है। यह बॉर्डर क्रास करके, सीमा पार करके टैरोरिज्म फैलाने का मामला भी है, मिलिटैन्सी का मामला है । अंतर्राट्रवाद का जो मामला है, वह अंतराट्रीय पैमाने पर काम कर रहा है। शरीफ लोगों के लिए सीमा है, बार्डर है, वीजा है, पासपोर्ट है लेकिन वे लोग जो औजार लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और नरसंहार करने के लिए साजिशें कर रहे हैं, एजेंट्स लेकर घूमते हैं, हत्यारे, mercemaries हैं तो वे एक सीमा से दूसरी सीमा पार करके चले जाते हैं और विश्व के किसी भी हिस्से में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी वहां इतनी पहुंच है। ऐसे लोग जो जिस क्षमता में जहां बैठे रहते हैं, वहां उनको एक्सप्लाइट कर सकते हैं। इस तरह से वह काम कर रहे हैं। इसलिए यह हमारे लिए और भी ज्यादा बड़ी चुनौती है। मैं एक वामपंथी होने के नाते इसे न सिर्फ धर्म की नजर से देखता हूं, न किसी विशेा जाति की नजर से देखता हूं, न किसी संकीर्ण नजरिये से देखता हूं और न ही इसे मैं केवल लॉ एंड आर्डर का मामला मानता हूं। हमारा ट्रेडीशनल समझ लॉ एंड आर्डर के मामला में ऐसा है कि कुछ थाने, पुलिस, फौज, औजार बढ़ा देने से या कुछ और कड़े कानून बना देने से मामले का निपटारा हो जायेगा लेकिन आजादी के इतने साल बाद तक हमने देखा है कि कुछ नहीं हुआ है। जो देश अभी तक इस मामले में अछूता था वहां भी यह मामला पहुंच रहा है। इसको थोड़ा बड़ी दृटि से देखना चाहिए। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो लोग कहेंगे कि यह तो मार्केसिस्ट है इसलिए अपनी बात रख रहा है। आजकल वे लोग भी जो सर्विस में रहते हैं, जब सर्विस से बाहर आते हैं, अभी मैंने निखिल कुमार जी को सुना, उन्होंने कहा कि सिर्फ लॉ एंड आर्डर का मामला नहीं है। श्री एन.एन. वोहरा कोई मार्केसिस्ट नहीं हैं। उन्होंने पिछली सरकार के दौर में कहा था।

वोहरा कमेटी की रिपोर्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पोलिटिक्स पर भी मैं आऊंगा। वह भी इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से बड़ी समस्या है। मैं वोहरा जी की स्पीच को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने ब्रिगेडियर राजिन्दर सिंह मैमोरियल स्पीच जम्मू में दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भी एक मैमोरियल स्पीच में आऊंगा। रिसेन्टली आपने भी डिलीवर किया है। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Do not bring the Speaker here.

मोहम्मद सलीम : ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह मैमोरियल लेक्चर, जम्मू में श्री वोहरा जी ने स्पीच दी है। मैं थोड़ा इसे इसलिए बोलूंगा कि किस नजरिये से हम देखते हैं, देखा जाता है और देखना पड़ेगा।

> "Experience has shown that the lack of timely concern or failure to deal with the demands of the aggrieved elements invariably leads to enhanced estrangement and the later resorting to violence. When such situations get out of hand, the traditional approach is to deal with them merely as law and order problems. In many such cases, the disgruntled elements abetted and supported by adversary external agencies are easily persuaded to adopt the gun culture and when such developments take place, we see the beginning of militancies and insurgencies. In this context, it is necessary to ensure that the coercive powers of the State are applied only after due deliberation. While dealing effectively with the rising disorder, the State must remain equally responsible for taking timely measures to identify and deal with the root causes of any situation which is likely to generate an internal security problem. The achievement of such an objective would call for timely and systematic attention in dealing with the socio-economic problems of the masses and also showing due concern for their political demands and aspirations."

जो अभी पिछले दिन सदन में बात हुई थी, यूपीए सरकार जब बात कर रही है, वह कश्मीर के बारे मे हो, नार्थ ईस्ट के बारे में हो, उनके जो रूटकॉज हो, जो डिससैटिस्फेक्शन है, जो एसपेरेशन्स हैं, जो डेमोक्रेटिक एसपेरेशन्स हैं, उनकी जो मांगें हैं, चाहे विकास का मामला हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, उस पर भी नजर

रखी जा रही है। मैं अलग से देखने की बात नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग यह कहें कि सिर्फ डेवलपमैंट हो जाने से बाकी मामला हो जायेगा तो ऐसा नहीं है। चाहे वह नार्थ ईस्ट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आंध्र प्रदेश में है चाहे नेक्सलाइट एरिया जिसके बारे में आप बोल रहे हैं ज्यादातर वह पिछड़ा इलाका है।

जो पिछड़े हुए लोग हैं, विकास में जिनको हम पीछे छोड़कर चले आए हैं, जिनके विकास की दर इतनी नहीं है कि भविय में कल्पना भी कर सकते हैं। 2-4-5-10-साल में बाकी देश के अन्य भागों में या विश्व के अन्य भागों में जिस तेजी से हम चल रहे हैं, हम उसको पकड़ पाएंगे। उसे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। इसके अंदर कुछ मिसपर्सेप्शंस तैयार किये जा रहे हैं। डिसइंफॉर्मेशन कैम्पेन है, जैसे हम यहां सदन में देखते हैं कि किस तरह से डिस्टॉर्ट किया जाता है। तो वहां भी ऐसे नेतृत्व खड़े होते हैं जिनका पोलिटिकल आस्पिरेशंस हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो पॉवर में घुसपैठ चाहते हैं, वे उसको एक्सप्लॉयट करते हैं और इसके लिए वे डिस्टॉर्ट करते हैं, हिस्टरी को भी डिस्टॉर्ट करते हैं। पोलिटिक्स को भी डिस्टॉर्ट करते हैं। इसके बाद एक ऐसी जगह में हम पहुंच जाते हैं जिसका सामना हम गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कर रहे हैं। इस ही कारण हमें एक कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी चाहिए। हम ऐसे मुद्दों पर किस तरह से आन्तरिक सुरक्षा के मामले में हम हर पहलू पर किस तरह से ध्यान देते हैं। हम अगर एक पहलू को निकालकर कहेंगे तो वह उसी तरह से होगा, जैसे एक अंधा जिस तरह से हाथी देखता है, वह दुम देखे या सिर देखे या पैर देखे। इसी प्रकार कश्मीर देखे तो मुसमलान देखे, असम देखे तो बांग्लादेशी घुसपैठ देखे या अगर नागालैंड देखे तो क्या क्रिश्चियन्स देखेगा और कई जगह देखे तो क्या बुद्धिस्ट देखेगा ? इस तरह से हम अंधेरे में ही अपने अंधेपन को साबित करेंगे।

इसलिए मैं चाहता हूं कि एक काम्प्रीहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि पूरे विश्व भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हमने तो पिछले 6 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा। पीछे एन.डी.ए. की सरकार आई थी तो राट्रीय सुरक्षा को ही एक बड़ा मुद्दा बनाकर ले आया गया था। बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला लीजिए, हम क्यों उसे मुसलमान और हिन्दू करके देखेंगे ? इस देश में अगर कोई विदेश से आकर राट्र में आकर बसता है तो वह राट्र की जिम्मेदारी है। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह घुसपैठियों को रोके, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो, चाहे वह पूर्व से आए या पश्चिम से आए। वह तो राट्र की आन्तरिक सुरक्षा का मामला है। लेकिन उसे अगर हम साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश करेंगे, उससे अगर हम राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो कॉमन कॉज है, उसको अगर हम कंफलिक्टिज कॉज में ले जाएंगे तो न तो वह राट्रीय हित का होगा, न उस मुद्दे के साथ हम चुनौती का सामना करेंगे। अकसर इस देश में ऐसा हुआ है कि उससे जो कॉमेनिलिटीज हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट है, उसको हम कंफलिक्ट्री इंटरेस्ट में बदल देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब कंफलिक्ट बढ़ रहा है तो वह कंफलिक्ट कहां से घटेगा ? अगर दूसरे लौह पुरुा इस देश में पिछले 6 साल से थे और सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी थी तो 6 साल में घुसपैठियों को रोकने के लिए कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया ? यह सवाल क्या हम आपसे नहीं पूछेंगे ? हम सरकार बनाएंगे तो एक बात कहेंगे और सरकार से विरोधी पक्ष में चले जाएंगे तो फिर भावना को निकालकर भागते रहेंगे। जिम्मेदारी उनकी भी थी। आज तक इस देश में सीमा पर पहरा देने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सीमा पर पहरा देने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है और गृह मंत्री जब यह कहकर कहें कि सरकार तो यह कहकर बनी थी, इसी सवाल को एक्सप्लॉयट करके आया गया था कि विदेशी घुसपैठ हो रही है और देश की आन्तरिक सुरक्षा हाशिये पर है तो उसको रोकने का बंदोबस्त करना चाहिए था। किसने मना किया था कि 6 साल बाद इस मुद्दे को उठाएंगे और बीच में आप कुछ नहीं करेंगे। सेंसस के डॉटा को लेकर अगर धर्म के नाम पर, अगर पोपुलेशन के सवाल को लेकर, अगर फैमिली प्लानिंग के सवाल को लेकर, धर्म के नाम पर बांटेंगें तो इस तरह से इस देश की हम कौन सी सेवा कर रहे हैं ?

देश के सौ करोड़ लोगों को हम अलग-अलग हिस्सों में बांटकर क्या आन्तरिक सुरक्षा को हम सुरक्षित रख पाएंगे या देश की सुरक्षा को सुरक्षित रख पाएंगे? हम तो और असुरक्षा के अन्दर रह रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम इन मुद्दों को न तो राजनीतिक और न ही धार्मिक दृटिकोण से देखें। सैकुलर मूल्क में रहने की दृटि से इसे देखें। हमारे देश में यह समस्या है। अगर उसके लिए कहीं विशेा प्रावधान करने की जरूरत है तो उसे भी जरूर रखना चाहिए लेकिन जब इसे देखें तो थोड़ा रंगीन चश्मा उतार कर देखना चाहिए, साफ नजर से देखना चाहिए। इसी तरह से जो देश में साम्प्रदायिक वातावरण है, पिछले 15-20 वर्ाों की स्थिति देखें तो जितने कत्ले-आम हुए हैं, जो फसादात हुए, जो बर्बरीयत हुई, जो ब्रूटलाजेशन ऑफ सोसायटी हुई, मैं गुजरात में हिन्दू और मुसलमान का मसला नहीं देखता, हिन्दुस्तानी मारे गए, कौन विदेशी मारे गए? महाराट्र से लोगों को निकाल कर जब फेंका गया, वहां बंगाल, बिहार से मजदूर काम करने के लिए आए, नॉर्थ बिहार से आए, असम से आए, नॉर्थ ईस्ट से आए, आप उन्हें बांगलादेशी कहकर लेबल लगा देंगे, आप ऐसा करके देश की एकता को खतरे में डाल रहे हैं, आप विदेशी को एंट्री प्वाइंट पर क्यों नहीं रोकते हैं ? आप देश में यह सवाल क्यों ले आते हैं चूंकि देश की जनता का आपको बंटवारा करना है, मैं बांग्ला भााी हूं, मैं बंगाल से आया हूं, मैं पारिवारिक बैकग्राउंड से मुसलमान भी हूं तो किसी का आप धर्म देखकर, किसी की भााा देखकर आप उसकी राट्रीयता की पहचान दिलाएंगे ? कौन से कानून में वह है, लेकिन यह चिंता हमारे सामने बार-बार लाई जाती है इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। सीपीआई (एम) के प्रतिनिधि के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि आप सीमा पर पहरा लगाओ, विदेशी घुसपैठ को रोको। यह सबकी, केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आप उसको रोकेंगे नहीं और उसके सहारे राजनीति करेंगे, धर्म और भााा के नाम पर जनता का बंटवारा करेंगे, तो हम उसका विरोध करते हैं। विरोध करना भी चाहिए, देश के हित के लिए करना चाहिए। आजकल कितनी मिलीटरी केपेबिलिटी है, कितनी न्यूक्लियर ताकत है, कितने एफ-16 टैंक हैं, इससे देश की सुरक्षा का मामला तैयार नहीं होता। आजकल विश्व के ज्यादातर देश सुरक्षा के मामले में सरहदों पर नहीं जूझ रहे हैं, अंदर जूझ रहे हैं। सीमा को पार करके समस्या देश के अंदर घुस गई है, उसकी रोकथाम के लिए जो मैंने काम्प्रीहेंसिव पालिसी की बात की है, वह जरूरी है।

एनडीए के समय में राट्रीय सुरक्षा कौंसिल बनी थी। आप नेशनल सिक्योरिटी इंडेक्स बनाएं, उसका सचिवालय बनाएं। इसी साल के शुरूआत में चाइना में, अमेरिका में यह बनाया है। जिस तरह से हम लोग ह्यूमन डवलपमेंट के इंडेक्स देखते हैं, जैसे एन.एस. और निफ्टी के इंडेक्स देखते हैं कि कितना आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी इंडेक्स का मामला है। उसमें वे कहते हैं कि आपके जो आंतरिक संसाधन हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेशनल रिसोर्सेज में जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अंदरूनी अर्थ नीति को भी देखना पड़ेगा कि कितना विकास हो रहा है और किस ढंग से हो रहा है। विश्व की अर्थ नीति के विकास में क्या हो रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी को भी समझें। उसको देश के उद्योग में, समाज में कृाि में और गांवों तथा शहरों में हम कितना आगे ले जा रहे हैं, उसके भी आंकड़े सामने रखने पड़ रहे हैं। आज कम्यूनिटी एफर्ट का भी महत्व है, आपकी कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, यह भी एक मुद्दा है। गवर्नेंस की क्या क्वालिटी है, समाज में क्या विकास दर है, समाज में अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, उसके लिए जनता को कितना एम्पावर किया है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य देशों के साथ आपकी क्या कूटनीति है, उनके साथ आपके जो सम्पर्क हैं, वह किस प्रकार स्मार्टली डील कर रहे हैं, इन सब आंकड़ों के बाद नेशनल सिक्योरिटी का आंकड़ा मापा जाता है कि हम किस जगह पर हैं। हमारा देश इस तरह की चिंताओं से किस तरह से सामना कर पाएगा, यह ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर हम एक ही पहलू से देखेंगे और बाकी पहलुओं को नहीं देखेंगे तो हम इस मुद्दे के साथ इन्साफ नहीं कर पाएंगे.

मैं आखिरी बात criminalisation of पालिटिक्स की बात कहना चाहता हूं। बहुत से लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी बात कैसे पूरी होगी। हम विभिन्न पार्टियों के सांसद यहां बैठे हुए हैं। हम अपने सीने पर हाथ रख कर सोचें कि हम कितना इस देश की राजनीति को गंदा कर रहे हैं और बाहर जाकर हमें लोगों की गालियां सुननी पड़ती हैं। जब क्रिमिनिलाइजेशन आफ पालिटिक्स हो रहा है, कितने सांसदों और विधायकों को स्टेनगन लेकर काम करना पड़ता है। क्यों यह आज स्टेटस सिम्बल बन रहा है, क्यों लोग सांसद और विधायक को देख कर डर कर भागते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। आप जानते हैं वोहरा कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी। यह जो राजनीति के साथ समाज विरोधी तत्वों का नैक्सेस बन गया है, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। राजनीति के साथ धर्म का जो नैक्सेस तैयार हो रहा है, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। राजनीति के साथ लोगों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि उन्हें इस तरह की बातों से बरगलाया जा रहा है, उसको भी तोड़ देंगे, तभी हम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर पाएंगे।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन अत्यंत ही महत्वपूर्ण विाय देश की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा कर रहा है। मुझे खुशी है कि इसका आरम्भ माननीय सदस्य रामजीलाल सुमन ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में करने का काम किया। जब माननीय विजय कुमार मल्होत्रा बोल रहे थे, तो शुरू में जो उनका भााण था, उससे लगा कि वह सही रास्ते जा रहे हैं, लेकिन बाद में लगा कि फिर बेताल पुरानी डाल पर जा बैठा। इनका भााण सुनने से लगा कि इन लोगों की साम्प्रादायिकता से ऊपर उठने की क्षमता नहीं है और सारी बात सुनकर बेताल अपने उसी पुराने स्थान पर चला गया।

मैं अपने कामरेड मोहम्मद सलीम जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सभी बातों को यहां रखा। आज आवश्यकता इस बात की है हम अगर देश की सुरक्षा के बारे में बातें करना चाहते हैं तो अपने राजनीतिक विचारों, अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों से ऊपर उठकर राट्र के हित में, राट्र के विकास के लिए, राट्र की सुरक्षा केलिए और आंतरिक सुरक्षा कैसे मजबूत हो, इस ईमानदारी से हम सबको विचार करना चाहिए और सरकार को भी उसी तरह से सुझाव देना चाहिए।

16.30 hrs. (Shri Ajay Maken in the Chair)

मैं माननीय् सदस्यों से और विशेाकर विपक्ष के माननीय नेताओं से जानना चाहता हूं जो बार-बार विदेशी घुसपैठियों, बंगलादेशी घुसपैठियों का सवाल उठा रहे हैं कि क्या आपने ऐसे कुछ कैसेज पकड़े। आपकी सरकार 6 वार्ों से थी। आपके गृह मंत्री थे, आपके प्रधान मंत्री थे तो आपने उस समय कारगर कदम क्यों नहीं उठाए।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराट्र) : आप भी तो हमारे साथ थे।â€¦ (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : आपने दूसरा मुद्दा मदरसों और आईएसआई का उठाया। â€¦ (व्यवधान)इंडों-नेपाल बार्डर पर जो मदरसे हैं उनके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वहां किस तरह से यतीम बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आपमें से कुछ साथी मेरे साथ चलें तो आपको पता चलेगा कि जिन बच्चों का कोई नहीं है वहां उन्हें किस तरह से खाना और शिक्षा दी जाती है। आपने कहा कि वहां आईएसआई ट्रेनिंग दे रहा है तो यह बात केवल नारा देने के लिए आप कहते हैं। क्या आपने एक भी आईएसआई का अड्डा पकड़ने का वहां पर काम किया? अगर आपने आईएसआई का अड्डा पकड़ने का काम किया होता तो हम आपकी बात मानते। मैं उस इलाके से आता हूं। वहां पर सैंकड़ों ऐसे मदरसे हैं जहां हजारों यतीम बच्चों को, जिनको खाना नसीब नहीं होता है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को जकात लेकर या दूसरी जगहों से पैसा लेकर खिलाने-पिलाने का काम किया जाता है। उसका अनुकरण आपको करना चाहिए। माननीय ि वजय कुमार मल्होत्रा जी को गुजरात के बारे में भी बोलना चाहिए था जहां पर लोगों को जलाया गया। गुजरात का सवाल कहां चला गया, जहां इतना गंदा काम गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया। क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है? देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी के सर्वेसर्वा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दंगों के बाद जब गुजरात गये थे तो उन्होंने कहा था कि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने राजधर्म का पालन नहीं किया। राजधर्म का पालन क्या होता है, यह हमको भी बतला दीजिए। क्या कत्लेआम करना राजधर्म होता है? अल्पसंख्यों की हिफाजत करना राजधर्म होता है, विकास करना राजधर्म होता है, कौमी एकता बरकरार रखना राजधर्म होता है, साम्प्रदायिक तनाव को कम करना राजधर्म होता है। साम्प्रदायिकता को बढ़ाना राजधर्म नहीं होता है जो आपकी गुजरात सरकार ने किया। विपक्ष में बैठने के बाद भी आपको होश नहीं आया है, आप मदहोशी में हैं। जनता आपको भविय में सबक सिखाएगी और आप उसी स्थान पर चले जाएंगे जहां पहले थे।

आज सारे देश में साम्प्रदायिकता का जहर भरने वाले जब भााण देते हैं तो लगता है कि उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने का काम नहीं करते हैं। आपकी पार्टी की एक्ट्रेस, स्मृति ईरानी ने बयान दिया और चाबुक मारा लेकिन ऊपर से दबाव के कारण फिर बयान बदल दिया। आप माननीय नरेन्द्र मोदी को हटाइये, नहीं तो आप समाप्त हो जाएंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। â€¦ (व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : बिहार के बारे में बोलिये।

श्री रघुनाथ झा : बिहार तो साम्प्रदायिक एकता का दुर्ग है।â€¦ (व्यवधान)माननीय आडवाणी जी से बिहार के बारे में पूछिये।â€¦ (व्यवधान)

बिहार साम्प्रदायिक एकता का दुर्ग हैâ€¦ (व्यवधान) आडवाणी जी से बिहार के बारे में पूछिये।जब श्री आडवाणी जी राम रथ पर सवार होकर देश में आग लगा रहे थे और सोमनाथ से लेकर सारे देश में उन्होंने चुनौती दी, उस समय बिहार में एक गरीब के बेटे ने उन्हें गिरफ्तार करके जैसे *â€¦â€¦* आप लोग बिहार में 23 तारीख को चलिये।â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Whosoever is speaking without my permission will not go on record.

*(Interruptions) **

* Not Recorded

â€¦ Expunged as ordered by the Chair.

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : सभापति जी, इस बात को एक्सपंज कीजियेâ€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : झा जी, आप मुझे संबोधित करें।

श्री रघुनाथ झा : बाबरी मस्जिद को ढहाया गयाâ€¦ (व्यवधान)हजारो लोग मारे गये। लाखों घर जलाये गये, बीजेपी जैसी साम्प्रदायिक पार्टी को यह हक नहींâ€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: If there is anything objectionable, it will be deleted from the records.

...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : श्री खारबेल स्वाईं जी, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब एक वक्ता बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिये। Please address the Chair.

...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : श्री झा साहब, आप चेयर को अड्रेस कीजिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो भी औब्जैक्शनेबल होगा, वह एक्सपंज किया जायेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ रिकार्ड पर नहीं जा रहा है।

श्री रघुनाथ झा : सभापति जी, पप्पू यादव के बारे में बहुत बात कहते हैं। हमारी बिहार सरकार की पुलिस ने उन्हें पकड़ा हैâ€¦(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, पप्पू यादव इस सदन के मैम्बर हैं।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका बोलने के लिये नम्बर आने वाला है,,आप बैठिये। आपका नाम लिस्ट में है। यदि आप बोलना चाहे तो अपने टाइम में बोलियेगा।

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, मैं एक बात गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है। माओवादी इनसरजैंसी नेपाल में व्यापक रूप से है जिसका सीधा असर बिहार पर पड़ता है। वे बिहार से भारत में प्रवेश कर रहे है। पूरा बार्डर खाली है। वहां कोई बार्डर रोड नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में दो एअरपोर्ट बनाये हुये थे जो रक्सौल और हथुहा में थे। इसके अलावा हमारे ऐरिया में छोटी-बड़ी 100 नदियां नेपाल से निकलती हैं । बरसात के दिनों में गंगा से लेकर गंडक, कोसी से लेकर बागमती आदि की बाढ़ से बहुत कठिनाई होती है। आंतरिक सुरक्षा के लिये बार्डर रोड बनाया जाना बहुत जरूरी है। यह काम जल्दी होना चाहिये। माओवादी संगठनों, नक्सलवादियों और क्रिमिनल्स के पास ऐसे हथियार हैं जो हमारे सुरक्षाकर्मियों के पास नहीं हैं। हमारे पास आधुनिक गाड़ियां नहीं हैं.â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him speak. Let him make his point. You can make your point when your turn comes.

...(*Interruptions*)

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, मैं सरकार से कह रहा हूं कि बहुत दिनों से केन्द्र सरकार के पास बिहार का पुलिस के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव लम्बित पड़ा है। आसाम का भी प्रोपोजल है। हमारा अनुरोध है कि सरकार पैसा देकर पुलिस के आधुनिकीकरण का काम करे। आज जिस तरह से नेपाल में माओवादी इनसर्जेन्सी सिर उठा रही है, उस बारे में आपको नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से एक बार तिब्बत के मामले में हम गफलत कर चुके हैं और तिब्बत चीन के कब्जे में चल गया, उसी तरह से अगर हम नेपाल के बारे में ढीली-ढाली नीति अपनायेंगे तो वह भी हमारे लिए एक दिन दुखद अध्याय बन सकता है। इसलिए इस संबंध में नेपाल सरकार से वार्ता करके वहां से भारत में लोगों का जो अवैध प्रवेश हो रहा है, उसे तुरंत रोकने का काम सरकार करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सदन आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा कर रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा के मामले दिनों-दिन गंभीर होते जा रहे हैं। हमारे कुछ पड़ौसी देश ऐसे हैं, जिन्हें इस बात में खुशी होती है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियां जोर से चलती रहें। इसके लिए वे लगातार कई प्रकार के प्रयास करते आ रहे हैं। एक समय था जब हम जम्मू-कश्मीर के बारे में कहते थे। लेकिन आज देश का कोई राज्य और शहर ऐसा नहीं है जहां आतंकवादी गतिविधियां न हों और जिनके कारण हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में न आई हो। आसाम, मिजोरम, मेघालय, महाराट्र और पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य हैं, जहां कई आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। देश में कोई नगर और महानगर भी इनसे अछूता नहीं है। देश के नगरों में जैसे दिल्ली, मुम्बई, संभाजीनगर, औरंगाबाद, नांदेड़ और फरीदाबाद आदि ऐसे कई शहर हैं, जिन शहरों में पड़ौसी देश अपने लोगों को भेजकर वहां की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, देश में कितनी घटनाएं हुई हैं - र्वा 2003-2004 में 143 सुरक्षा दल के लोग मारे गये, 679 नागरिक मारे गये और 781 लोगों का अपहरण हुआ। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मुझे लगता है कि हमारा ध्यान केवल वोटों की राजनीति की तरफ अधिक है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि हम देश को बचा पा रहे हैं या नहीं, हम यह नहीं देखते हैं। एक तरफ हमारा देश आंतरिक सुरक्षा की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हम वोटों की राजनीति की नीति पर चल रहे हैं। हमारे देश में किसके अधिक वोट हैं, हम उसे पहले संभालते हैं।

सभापति महोदय, आंतरिक सुरक्षा के मामले में मदरसे हमारे देश में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे कितने मदरसे हैं जो बिना परमीशन के चल रहे हैं। इन मदरसों में क्या चलता है। क्या कभी इस ओर सरकार ने देखा है। जो बच्चे पढ़-लिख नहीं सकते, जिन बच्चों के मां-बाप नहीं होते हैंâ€¦(व्यवधान)

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : क्या आपने देखा है।

श्री अनंत गुढ़े : हमने देखा है।â€¦(व्यवधान)

श्री चंद्रकांत खैरे : हमने देखा है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : पांच र्वा में आपने क्या देखा है तथा आपने क्या किया है?

MR. CHAIRMAN : Mr. Owaisi, when you get your chance, you can make your point.

श्री अनंत गुढ़े : जिन मदरसों को पाकिस्तान और बंगलादेश की मदद मिलती है, वे मदरसे हमारे देश में खुलेआम बिना परमीशन के चल रहे हैं। कल मदरसा खुलता

है और तुरंत उसकी बिल्डिंग बन जाती है, यह पैसा कहां से आता है।

कौन से बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं? कहां से बच्चे यहां पर आते हैं? यहां वे बच्चे आते हैं, जिन बच्चों के मां-बाप नहीं हैं, जिन बच्चों को खाने को नहीं मिलता, जिनका कोई आगे-पीछे नहीं है, ऐसे बच्चों को मदरसे में लाकर इस देश के विरुद्ध बातें उनको अरबी भााा में पढ़ाकर हमारे देश में आतंकवाद का माहौल पैदा करने की कोशिश चल रही है। यह केवल आज की समस्या नहीं है। देश में और 10-15 साल यह चलेगा तो हम केवल सदन में मदरसों के बारे में ही चर्चा करेंगे कि मदरसों की वजह से हमारे देश में आतंकवाद बढ़ गया है। यह बात भविय में होने वाली है। â€¦ (व्यवधान)मैं तो अकेला बोलने वाला हूँ।

सभापति महोदय : आपने अपने समय से ज्यादा बोल लिया है।

श्री अनंत गुढ़े : सभापति जी, सरकार को इन मदरसों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार ने कितने मदरसों की चैकिंग की है? पुलिस क्या करती है? इसी वजह से 'सिमी' के कार्यकर्ता आकर मदरसों में पढ़ाकर इस देश में विघटन फैलाने की बात करते हैं। इस पर हमें राजनीति न करते हुए होंठों पर ध्यान न देते हुए इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि देश की सुरक्षा कैसे बनी रह सकती है। सरकार कई करोड़ों रुपये इन सब बातों पर खर्च करती है। हमारे सुरक्षा बल हैं और अर्द्ध सैनिक बल तथा पुलिस बल हैं लेकिन उन पर से विश्वास दिनोंदिन उठता जा रहा है। नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में एक अपराधी को जिसको पुलिस नहीं पकड़ सकती, कोर्ट जिस पर कार्रवाई नहीं कर सकती, महिलाओं को इकट्ठा होकर कोर्ट के सामने उसका खून करना पड़ा। क्यों नहीं हमारी पुलिस काम कर सकती, क्यों नहीं हमारा ध्यान पुलिस पर है? सभापति जी, सभी राज्यों को सरकार सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये देती है। मैंने आंकड़े देखे हैं। 2000-2001 में जो पैसे दिये गये हैं, उसमें 71 फीसदी पैसा खर्च हुआ है। 2001-2002 में जो पैसे दिये गये हैं, उसमें 43 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है। कई राज्यों की वित्तीय स्थिति बिल्कुल खराब है। मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि ऐसे राज्यों को पैसे देने की जरूरत है।

आज मुम्बई जैसे शहरों में बड़ी संख्या में बंग्लादेशी आ रहे हैं। कई सालों से मांग हो रही है कि इन पर बैन लगाइए। वे लोग फुटपाथ पर रहते हैं और वहीं सोते हैं। वहां कई तरह के अपराध वे लोग करते हैं और वहां के लोगों को तकलीफ देते हैं, लेकिन कई बार मांग उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सके। अगर इसी ढंग से चलता रहा तो हिन्दुस्तान का नाम बदलने की बारी भी आ सकती है। हमें जागरूक होने की जरूरत है, जागरूक होना हमारे लिए आवश्यक है। बंग्लादेशी हमारे यहां आ रहे हैं लेकिन हमारा देश-प्रेम कहां गया? जब तक हम अपने राट्र से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक राट्र पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक राट्र सुरक्षित नहीं चल सकता। अगर सुरक्षित रूप से हमें राट्र को चलाना है तो इन सब गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है और इस देश के मदरसों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to highlight the internal security problems of our country.

Right from the very beginning, before and after becoming a Member of Parliament, it seems that we have learnt only to give a commentary on the internal security problems of our country. हम लोगों को देखना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा की समस्या किस वजह से आई है और यह इस देश में कैसे फैल रही है? We have to look into the grounds or causes of the spread of internal security problems throughout the country.

Seniors have deliberated a lot on the Jammu and Kashmir issue. Members have deliberated on the naxalite issue. Today, I would like to tell this august House that there is no State called North-East, but there are eight States in the region. I want to deal with issues related to the North-Eastern states. The Government of India is always repeating one mistake. Whatever be the problem in the North-East, it uses only one yardstick and it uses only one eye, the eye of law, to look into the problems of the North-East. We have got eight States, including Sikkim. We have got different ethnic communities in different States. It should be dealt with having these ethnic differences in mind. In Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Assam, Arunachal Pradesh and Sikkim, we have got different communities. The problems are not similar for all the States. Today, after Jammu and Kashmir, the North-Eastern States have become the fertile ground for the underground activities of the ISI.

I would like to highlight the ground cause for these underground activities in the North-East. The Government of India has laid its own trap for insurgency and underground activities in the North-East. We have got Mizoram Accord, Nagaland Accord, Manipur Accord, Bodoland Accord and Assam Accord. Which

one of these Accords or Agreements was fulfilled by the Government of India? This is one of the causes for the alienation of the people living in that part of the country.

Now, I will deal with State-wise issues, highlighting only the few basic points. Let us take the latest example of Manipur. Recently, my sisters and relatives of Manipur stood naked protesting, in a democracy, against a law which was brought by the then Viceroy of British India, Lord Linlithgow in 1942. When India got independence, this law was abolished. But in 1958, when Shri G.B. Pant was the Home Minister, this august House brought that law for the North-East. Right from that day till today the Government of India"s attitude towards North-East was wrong. हम हिन्दी में कहते हैं कि पूर्व-उत्तर के लिए नज़रिया उस दिन से ही गलत था।

The same laws which are applicable to other States could have been implemented in that part of the country also.

The simple meaning of Armed Forces (Special Powers) Act is to kill civilians on mere suspicions. Again this law was amended in 1972 and applied to all the seven States of the North-East. The Government of India has placed the people of North-East in the dark. Emergency was imposed in the entire North-East. All the agitators and all the

people who are agitating against this Act are not separatists. It may be limited to a few. But the Government of India has taken it for granted that anybody or any group that is agitating in the North-East is a separatist. That is not correct. Today, I would like to inform this august House that the people of North-East are Indians, they will remain Indians and India is our country.

Because of this law, in Manipur, our sisters and mothers stand naked. This is shameful in a great democratic country like India.â€¦ (*Interruptions*) I am mentioning about all the seven States of the Region. In spite of taking the initiative, in spite of looking into the Manipur issues, one Committee has been constituted to look into the Armed Forces Act about which the Manipur State is agitating. I would like to request the Home Ministry and the Government of India to look into Section 4 of this Act where, on a suspicious ground, they can kill anybody without producing any warrant and all that. इस टास्क फोर्स को यह कमेटी देखे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखे।

This Manipur issue is not similar to that of the issues of Arunachal Pradesh. I belong to Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh was treated as one of the peace-loving States, islands of peace in the country. Now, it has been affected by the Naga underground terrorists. Recently, on 26th November of last month, one of my close friends, who was a *Zilla Parishad* Member in Lohit District was kidnapped. There is the other district Changlang which is also affected. We have got the Chakma refugees. They came to Arunachal Pradesh. This is the gift of the Congress Government of 1964. When there was a clash between the Hindus and the Muslims in Bangladesh, many refugees had been settled in Arunachal Pradesh without taking any cognisance of the local leaders of Arunachal Pradesh. Then, Arunachal Pradesh was known as NEFA. About 4000 refugees had been settled without any consultation with the local leaders. The refugees came. Now, there is a nexus between the Chakma refugees and the Tripura underground terrorists. मेरे एक साथी जिला परिद के मैम्बर थे, उन्हें पिछले 26 नवम्बर को किडनैप किया गया। उनसे 20 लाख रुपये की डिमांड की गई, लेकिन 18 लाख रुपये दिये गये। जब पुलिस ने रेड की, तो पता लगा कि उनको पहले ही मारकर जंगल में दफना दिया गया है।

When the Police Department of Arunachal Pradesh arrested six people including one lady, it came to be known that they were all terrorists from Tripura. This is the position of the peace-loving State of Arunachal Pradesh. I have given a memorandum to the hon. Home Minister to look into the refugees issue in detail. They should be deported from Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is protected under the Bengal Regulations Act, 1873. We have got the Inner Line Act, the inner line pass. In spite of all these laws, the Election Commission has directed the Government of Arunachal Pradesh to include the refugees in the voters list whereas the Government of India has not given any citizenship right to these refugees. So, this is one of the causes. In future, internal security problem will be generated from this cause.

In Assam, we have got the Assam Accord. We have got the Bodoland Accord. None of these Accords and agreements has been implemented by the Government of India. So, this is the reason why the inhabitants of that part of the country are feeling alienation. टाइम कम है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नोडल मिनिस्ट्री कायम की गई, under the leadership of Shri A.B. Vajpayee. Ten per cent of this fund allotted to each Ministry should be given to the North-East. They are under the Development Minister of the North-East. आज तक कितना पैसा दिया, यह स्टेटमेंट इस सदन में लायें और पूर्वात्तर राज्यों के लोगों को इस बारे में जानने दिया जाये। यह भी एक बड़ा कारण है। आज तक जो भी मेघालय की प्राब्लम है, वहां आई.एस.आई. असम में Even I have got objections to the statement made by the American diplomat. It has come out in the Assam Press Release saying that he is ready to modernise the Assam Police Force.

17.00 hrs.

हमें इससे स्बक सीखना है कि आईएसआई पॉलिसी के आधार पर ऐसी स्टेटमैंट दिया जाना is an insult to the country. We have got objection to this. We have got the ability and we have got the manpower to look into it. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Mr. Kirip Chaliha, when you get your chance, you make your point. This is his maiden speech. Please do not interrupt him.

Mr. Tapir Gao, please conclude. You have already taken 10 minutes.

SHRI TAPIR GAO : Sir, the Border Security Force has been entrusted with the task of manning our border with Bangladesh. Out of 4,000 kms. border, 368 kms. of border fencing has been damaged. I would like to know what action the Government is taking to protect the damaged fencing so that daily infiltration from Bangladesh can be stopped.

Then, the IMDT Act should be repealed immediately. Until and unless this is repealed, we cannot stop infiltration. In respect of this, the hon. Minister has made a statement that this Act would spread all over the country. If this is done, this will not be beneficial to the internal security of the country.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Mr. Chairman, Sir, it was with some amusement that I heard Prof. Vijay Kumar Malhotra speak today on the internal security scenario in the country and also with a tinge of sorrow. For the Congress Party, the question of internal security is not a matter of party politics. In fact, it cannot, and should not, be a question of party politics for anybody in the country.

Sir, during the last seven years, the Congress Party, sitting on the other side, extended full support to the Government on the question of internal security and today, with barely seven months on this side, one could not be but amused to hear the BJP leaders diagnose the entire problem in a way as if it was the making of somebody other than the BJP.

When I stand here to speak, I am conscious of the fact that the people of Jammu and Kashmir have been subjected to untold sorrow and suffering during the last almost two decades. A large number of people have been rendered homeless. They had to leave their homes and hearths for the most unhelpful environs of the refugee camps. But at the same time, we cannot lose sight of the fact that it was the Congress Party, many years back, which initiated steps to bring about normalcy in the State and it is the Congress today which is determined to do so.

The Prime Minister recently went to Jammu and Kashmir and taking a holistic approach of the entire problem, he ordered − this, of course, would be criticised by the Members on the other side − reduction in the number of security forces posted in the State to ensure build an environment of mutual trust and understanding. At the same time, an economic package of Rs. 24,000 crore has been announced. Much more has to be done and I understand that.

Sir, again I was surprised to hear Prof. Vijay Kumar Malhotra taking objection to one word which the hon. Home Minister may have used somewhere about the terrorists. He said, उनको भाई कहा। क्या किसी को भाई कहने में कोई गुनाह है? वे

बहुत भावुक हो गए। लगता था जैसे वे इस बात का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि वे लोग जो कत्ल-ए-आम कर रहे हैं, उनको आप अपने गले से लगाना चाहते हैं। क्या आप वह वक्त भूल गए, जिन्होंने उन लोगों को कत्ल-ए-आम करने के लिए यहां तैयार किया, जिन्होंने उनको यहां सब प्रकार की ट्रेनिंग दी, ऐसे लोगों को जहाज में बिठाकर, अपने एक वरिठ मंत्री के साथ, जब वे आपको गालियां दिए जा रहे थे, आप उन्हें कांधार छोड़ने जा रहे थे?

क्या वह उस दिन की बात को भूल गये हैं। आज अगर कांग्रेस ने कह दिया कि कोई हमसे बात करना चाहता है, तो हम उससे बात करेंगे, उसमें क्या यह गलत है ?What is democracy all about? जम्हूरियत में यही होता है कि जो भी आदमी बात करना चाहता है, उससे आप बात कीजिए। हमने यही नेक्सलाइट्स के साथ किया है। इलेक्शन से पहले वहां की आन्ध्रा की सरकार ने, जो उस वक्त आपके साथी थे, क्या कहा था ? उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव में सिर्फ नेक्सलिज्म का मुद्दा होगा। हमने उसके विपरीत बात की थी। हमने कहा कि सिर्फ लॉ एंड आर्डर की ही समस्या या मुद्दा नहीं है, This is a socio-economic problem as well and it was with that in mind that we went to election and you know what happened there. The people voted overwhelmingly against the TDP, their partner, and not the Congress. उसके बाद अगर वहां एक प्रौसैस, उन लोगों को साथ लाने और उनसे बात करने का शुरू किया तो उसमें भी आप गलती निकालेंगे। एक शब्द कह दिया कि वह भाई है, तो आप उस पर एतराज करेंगे कि बातचीत के अलावा कोई और रास्ता हमें अपनाना चाहिए ।

चूंकि यह आतंरिक सुरक्षा का मसला है, इसलिए मैं दो-तीन मुद्दों के बारे में एक साथ बात करना चाहूंगा। आपने एक बात आटोनॉमी की कही। आप भूल गये कि उस समय श्री नरसिंह राव जी ने बुरकिनो फासो मे क्या कहा था ? उस वक्त एक ब्लू प्रिंट जम्मू कश्मीर की बात का समाधान करने के लिए दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर कोई किसी तरह की अफरातफरी मचाना चाहता है तो उसके साथ हमारा किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं आज पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। इसमें सबसे पहले आपके गृह मंत्री रहे। आप कह देंगे कि आपके नहीं, बल्कि वह आज हमारे साथ हैं। इस तरह से बात नहीं बनती। आपके गृह मंत्री थे, उनकी बेटी के लिए आपने क्या किया ? मुझे उस वक्त ताज्जुब होता है, मैं वह बात फिर कहना चाहता । जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा, उससे बाहर श्री आडवाणी जी, जो विपक्ष के नेता हैं, वे कहते हैं कि कांग्रेस के हाथों देश सुरक्षित नहीं है। ये कहां से आये हैं ? क्या वे 57 वां का इतिहास भूल गये हैं ? किस-किस हालात में हिन्दुस्तान की सुरक्षा एक मुद्दा बनाकर चार्टर आफ फेथ, एन आर्टिकल ऑफ फेथ, किसने किया, कांग्रेस ने किया। किसने जाने गंवायीं ? कांग्रेस के, देश के बड़े-बड़े नेताओं की जानें गयीं। ठीक है, देश मे अलग-अलग जगहों पर हालात खराब हों, तो हमें उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जब कश्मीर की बात हुई, 1953 की मैंने बात नहीं की, मैं मल्होत्रा जी को याद कराना चाहता हूं कि उनकी सोच और हमारी सोच में एक अंतर था। जो लोग इनकी डोर संभाल कर रखते हैं, वहां जम्मू-कश्मीर को तीन हिस्से में बांट देने का, धर्म की बिना पर कारगिल और वेली को अलग, लेह को अलग और जम्मू को अलग करने का एक दस्तावेज तैयार किया गया था। कांग्रेस ने उसे आज भी नहीं माना और पहले भी नहीं माना। जब मैंने बुरकिनो फारसो का जिक्र किया था, प्रधान मंत्री श्री नरसिंह जी के भाण का जिक्र किया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि सदियों से वहां बहुत डायवर्सिटी रही है. भिन्नता रही है लेकिन समूचा जम्मू कश्मीर एक यूनिट के तौर पर रहा है और उसे हम हिन्दुस्तान का अटूट अंग मानते हुए बरकरार रखेंगे। प्रधान मंत्री जी ने यही कहा कि हम किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन देश की जो रेखाएं हैं, उनको दूसरी बार नहीं लिखा जा सकता है। उस पर आपको एतराज है ? आप समझते हैं कि देश की जो आतंरिक सुरक्षा है, उसके साथ कम्प्रोमाइज हो रहा है। इतना ही नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस स्थिति समझती है। कांग्रेस बहुत मुश्किलात के हालात से निकली है। जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा हिन्दुस्तान को अपना देश मानते हैं और मानते रहेंगे। जैसा उधर से कहा गया कि अगर हम एक चश्मे से देखें, हर चीज को तोड़-मरोड़कर बात करने की कोशिश करें तो शायद न उससे अपना भला होगा, न देश का भला होगा और न अपना जो राजनीतिक मुद्दा है, उसका भला हो सकता है।

सिर्फ इतना कहते हुए मैं मामूली सी बात का जिक्र करना चाहता हूं। नैक्सेलिज्म के बारे में हमने सिर्फ बातचीत करने के लिए कहा है और जब से आप जानते हैं, एनएससीएन बात करने के लिए आये। कांग्रेस की सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि बातचीत हिन्दुस्तान के बीच में हो और यहां लोग आए क्योंकि आज नागालैंड में भी लोग महसूस करते हैं कि इतने वर्षों से झगड़ा चलता रहा है, वहां से हमें क्या मिला है ? इसलिए वे चाहते हैं और खास तौर पर वहां की महिलाएं चाहती हैं और इसीलिए वे बाहर निकलकर आ रही हैं कि हमें बातचीत करनी है, हिन्दुस्तान का एक अच्छा अंग बनकर रहना है। मणिपुर में नागालैंड कंसोलिडेशन का सवाल है, समस्या उठ जाती है लेकिन उसके लिए सभी को मिलकर बातचीत करनी होगी और सबसे ज्यादा इन चीजों पर बातचीत करनी होगी कि वहां की सोशल तथा इकॉनोमिक कंडीशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप समय का इशारा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिस हॉलिस्ट्क एप्रोच की जरूरत है, वही तरीका, वही रास्ता कांग्रेस ने अपनाया हुआ है। बेशक वे हमारी नॉर्थ-ईस्ट के स्टेट्स हों, बेशक नैक्सेलिज्म की समस्या के साथ डील करने की बात हो, बेशक जम्मू-कश्मीर के साथ डील करने की बात हो। मैं मामूली सी बात का जिक्र करना चाहता था लेकिन आपने समय का इशारा

कर दिया है। इसलिए इतना कहकर ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न सभी को बैचेन करने वाला मुद्दा है और इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने निरन्तर देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत, आतंकवाद की बढ़ती हुई समस्या, सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद इस नजरिये से उसको देखने की कोशिश की है, उनकी चिंता में मैं भी अपनी चिंता को शामिल करता हूं।

जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, बंटवारे के बाद से ही हमारे देश में सबसे महत्व का विाय रहा है और इस पर निर्णय लेने का जो काम हमने इस देश में हमेशा सर्वानुमति से किया, सभी दलों को विश्वास में लेकर किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि पिछले 9-10 महीने में कश्मीर में आतंकवाद के संबंध में भारत सरकार ने जो भी निर्णय लिया, जो भी नीतिगत वक्तव्य दिया और जिस तरह के भी प्रयास किये, उन प्रयासों में सभी दलों को शामिल नहीं किया गया। मैं अपना अफसोस इस मुद्दे पर प्रकट करना चाहता हूं कि वहां से सेना हटाने, सेना में कटौती करने जैसा एक महत्वपूर्ण फैसला भारत सरकार ने लिया। इन लोगों को तो विश्वास में नहीं लिया, यह बात समझ में आती है लेकिन जो लोग सहयोगी दलों में हैं, उनको भी विश्वास में इस बात के लिए नहीं लिया गया, यह बहुत कट का विाय है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दिन से वहां से सेना में कटौती की गई है, वहां के उग्रवाद में थोड़ी-बहुत कमी या अधिकता हो सकती है, उसकी परिस्थितियां हैं क्योंकि जब से अफगानिस्तान में लोक तंत्र की स्थापना हुई है, भारत में भाड़े पर अपने घुसपैठियों को भेजने में पाकिस्तान को भी थोड़ी दिक्कत हो रही है।

इसलिए आज जो थोड़ी-बहुत कमी दिखाई पड़ रही है, वह कमी इसलिए नहीं दिखाई पड़ रही है कि पाकिस्तान ने अपने रवैये में परिवर्तन कर लिया है, कमी परिस्थितियोंवश दिखलाई पड़ रही है और ऐसी कमी कई बार आज़ाद भारत के इतिहास में दिखाई पड़ी। अभी पिछले सप्ताह लोक सभा में जब पूर्वोत्तर के उग्रवाद के बारे में प्रश्न किया गया तो माननीय गृह मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया कि बंगलादेश में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद में घुसपैठिये और उसके ठिकाने बंगलादेश में स्थापित हैं। उनको पाकिस्तान के आई.एस.आई. की सामरिक और आर्थिक और स्ट्रेटेजी संबंधी सभी तरह की इमदाद पाकिस्तान द्वारा मिल रही है।

अब जब पूर्वोत्तर में विस्फोट हुए, दुर्भाग्य की बात है कि गांधी जयंती के अवसर पर हुए। भारत सरकार की ओर से तीन वक्तव्य आए। एक जिम्मेदार मंत्री का वक्तव्य आया कि पाकिस्तान का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तुरंत उसका प्रतिवाद आया कि उसका हाथ नहीं है। फिर रक्षा मंत्री का बयान आया कि नहीं, आईएसआई का हाथ है और उसके पुट प्रमाण हैं। जब किसी एक प्रश्न पर सरकार के तीन जिम्मेदार मंत्री तीन तरह के वक्तव्य देंगे, तो इस बात का संकेत जाता है कि सरकार आतंकवाद का मुकाबना करने में संगठित नहीं है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज की परिस्थितियों में यह दिखाई पड़ रहा है कि घुसपैठ में कमी आई है, उस कमी का कारण उसके पीछे दुनिया के एक शक्तिशाली देश का सम्बन्ध है। वह भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बिगाड़ कर रखना चाहता है। नरसिंह राव जी के जमाने से लेकर वाजपेयी जी के जमाने तक और आज की सरकार ने, तीनों सरकारों ने इस सिलसिले को जारी रखा। बावजूद इसके कि भाजपा के मित्र कहते रहे कि बातचीत से कश्मीर की समस्या का निदान नहीं है, भारत को अंतिम संर्घा करना चाहिए। लेकिन जब वे सरकार में आ गए तो इन्होंने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में इस उपलब्धि को भी गिनाते हैं कि वाजपेयी जी ने लाहौर में जाकर पाकिस्तान से इस समस्या का बातचीत से हल करने का सिलसिला शुरू किया। इस बात को सभी सरकारों ने स्वीकार किया है कि कश्मीर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है। सिद्धांत रूप में हम सब स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच भाईचारे का रिश्ता होना चाहिए। पड़ोसी का रिश्ता तो है ही, लेकिन हम पड़ोसी नहीं, दोनों भाई हैं। किन्हीं परिस्थितियोंवश एक साम्राज्यवादी ताकत ने हमें बांट दिया। इसलिए हम दोनों के बीच भाईचारा होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप में यह बात अच्छी लगती है। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी लोकतांत्रिक शक्तियां पाकिस्तान में मजबूत होती हैं, तो इधर घुसपैठ में कमी आती है। जब कभी वहां तानाशाह और सैनिक हुकूमत आती है तो घुसपैठ में बढ़ोत्तरी होती है। संयोग से आज वहां सैनिक तानाशाह है। लेकिन वह भी आंतरिक उग्रवाद से प्रभावित है और उनके ऊपर भी आक्रमण हो चुके हैं। इसलिए यहां घुसपैठ में कमी आई है कि उधर घुसपैठ करने के लिए आतंकवादियों में आपसी लड़ाई से उनकी शक्ति जाया हो रही है। यह जो अवसर मिला है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए।

मैं बात को लम्बा नहीं करना चाहता, क्योंकि समय कम है। पूर्वोत्तर का जो उग्रवाद है, वह कहां से शुरू हुआ। हमारे मित्र ने कहा कि किसी महिला के साथ रक्षा बलों ने ऐसा कर दिया। ऐसी बात नहीं है, पिछले आठ-दस वार्ों में वहां के उग्रवादी संगठनों के साथ भारत सरकार संधि विराम किए हुए है। हमारे प्रतिनिधि पिछले आठ-दस सालों से कभी एमस्टर्डम जाते हैं तो कभी थाइलैंड जाते हैं और वहां उनके निधियों से बात करते हैं। उनको महिमा मंडित करने का काम किया जाता है। हम एक समयसीमा चाहते हैं कि एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) से भारत सरकार की कब तक वार्ता चलेगी। अभी तो लग रहा है कि एक अंतहीन वार्ता चलती रहेगी। क्या हम उनको इस बात की छूट देंगे कि उनकी जो आक्रमणकारी शक्ति है, उसमें इजाफा वे करते रहें। उनका जो हरावल दस्ता है, जो आक्रमण करने वाला दस्ता है, उसका वार्षिक बजट 30 करोड़ रुपए का हो गया है। उनके पास पांच हजार आज की तारीख में ऐसे स्वयं सेवक हैं, जो आपके ठिकानों पर हमला करने की स्थिति में हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आप बातचीत कर रहे हैं। वृहद नगालैंड को लेकर आपने संधि विराम कर दिया। उसको लेकर मणिपुर की जनता में विस्फोट हुआ। उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। क्या भारत सरकार वृहद नगालैंड के सिद्धांत को स्वीकार करने को तैयार है, यदि है तो नगा उग्रवादियों केसाथ एक समझौता तो हो सकता है, लेकिन दूसरे विवाद के विाय और खड़े हो जाएंगे, जिसके लिए मणिपुर की जनता आज की तारीख में तैयार नहीं है। इसलिए इस संवेदनशील प्रश्न पर भारत सरकार को एक समग्र और समन्वित नीति तैयार करने की जरूरत है. हम एक सीमा निर्धारित करके उनसे वार्ता करें। उनसे यह भी तय करें कि वार्ता की यह अंतिम तारीख हो, तो वही होनी चाहिए, उसके बाद हम अपनी शक्ति और ताकत के साथ वहां के उग्रवाद को खत्म करने की कोशिश करें। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं।

जहां तक नक्सलवाद का सवाल है. यह आज की पैदाइश नहीं है। सन् 1967 में जब इस संसद के भीतर विधि-विरुद्ध अध्यादेश कानून पास किया और अगर आप उसकी बहस को आज की तारीख में पढ़ें, तो उसी समय इस देश में नक्सलवाद की आहट सुनाई देने लगी थी। विभिन्न राज्यों में संयुक्त विधायक दलों की सरकारें बनी थीं और साम्यवादी पार्टी उसमें शरीक हो गयी थी और उसमें इस विचारधारा के लोग जो यह आरोप लगाते थे कि साम्यवादी आंदोलन अब संसदीय पद्धति की ओर प्रवेश कर रहा है, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। उन लोगों ने इस विचारधारा को जन्म दिया था। इसका विस्फोट अप्रैल 1969 में नक्सलवाड़ी में हुआ. जहां 150 भूस्वामियों की एक साथ हत्या कर दी गयी थी। इसीलिए इस विचारधारा के लोगों को नक्सलवादी विचारधारा के नाम से जाना जाने लगा। आज की तारीख में चार राज्यों में इसका फैलाव हो चुका है। जैसा मेरे मित्र ने सुझाव दिया कि इस आंदोलन को काउंटर करने के लिए हमें आर्थिक और सामाजिक पहलू को देखना पड़ेगा। आर्थिक और सामाजिक कारणों से इस आंदोलन की उत्पत्ति होती है। सन् 1977 के बाद जब से साम्यवादियों की हुकूमत पश्चिमी बंगाल में आई तब से उन्होंने भू-स्वामित्व के मामले को युद्ध-स्तर पर हल किया। इसलिए नक्सलवादी आंदोलन वहां खत्म हो गया। इसकी आधारशिला उन राज्यों में फैली जहां भूमि का अधिकार गरीबों के हाथों में नहीं है। इसलिए भारत सरकार को इसे कानून-व्यवस्था का सवाल न मानकर इसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से उपजा हुआ आंदोलन मानना चाहिए और इस पर काबू पाने के लिए हमको सामाजिक और आर्थिक सुधारों की ओर पहल करनी चाहिए - ऐसा मैं आग्रह करता हूं। आपके पास समय कम है और मेरे पास भी समय कम है। इसलिए इन थोड़े से सुझावों के साथ अपनी चिंता प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : सभापति महोदय, देश खराब स्थिति में पहुंच चुका है लेकिन सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि माननीय बंसल जी ने बताया और मैं उनसे सहमत हूं लेकिन सरकार राट्रीय सुरक्षा के मामले में राजनीति में डूबे, यह ठीक नहीं है। सरकार तो विपक्ष को भी कांफिडेंस में नहीं लेती

है। अभी 9000 टूप्स अन्तर्राट्रीय बार्डर से विद-ड्रा किये गये, लेकिन इस पर भी विपक्ष के साथ सरकार ने बातचीत करना उचित नहीं समझा। देश के अंदर जो समस्याएं हैं उन पर विपक्ष को कांफिडेंस में लेना जरूरी है, ऐसा सरकार मानती नजर नहीं आती है। आप सब नेशनल पेपर्स देखिये, अखबारों ने छाप दिया कि सरकार का गृह मंत्रालय पर विश्वास नहीं है। गृह मंत्री स्वंय मास्टर-डिजास्टर है। डेली न्यूज-पेपर्स ने लिख दिया कि यह मास्टर-डिजास्टर है। देश की स्थिति पिछले 7 महीनों में बिगड़ गयी है, इस बात को सरकार को मानना चाहिए। इसके समाधान के लिए भी विपक्ष को विश्वास में लेना जरुरी है। सितम्बर तक के जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें 350 सिविलियन नार्थ-ईस्ट में मारे गये हैं और उधर इसी समय तक वायलेंस की जो 860 घटनाएं हुई हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मारे गये सिविलियन्स की संख्या 100 है और दो अक्टूबर को वहां जो घटनाएं हुई वह सब को मालूम हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी कश्मीर गये और वहां पर उनकी सभा के नजदीक जो विस्फोट हुआ, ऐसा पिछले 7 सालों में कभी नहीं हुआ। टैरेरिस्ट बातचीत करना चाहते हैं, यह मेरी समझ या देश की समझ के बाहर की बात है। सरकार बहुत गंभीर है, ऐसा भी नहीं लगता है। मेरा विचार है कि सरकार के तीन पावर सेंटर्स बन गये हैं। गृह मंत्री स्वतंत्र नहीं है, वे प्रधान मंत्री जी पर निर्भर करते हैं और प्रधान मंत्री जी दूसरों पर निर्भर करते हैं। यही देश की स्थिति के बिगड़ने का मुख्य कारण है। देश की स्थिति आज अच्छी नहीं है। नगालैंड में और मणिपुर के बारे में सरकार का विचार क्या है? गृह मंत्रालय स्पेशल आर्म्स फोर्स एक्ट को वापस लेना नहीं चाहता है, बातचीत करना नहीं चाहता है ।लेकिन प्रधान मंत्री के दफ्तर में प्रधान मंत्री खुद बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम आर्म्ड फोर्सिज एक्ट को विदड्रा करने के लिए विचार करेंगे। होम मिनिस्ट्री, प्रधान मंत्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में कोआर्डिनेशन नहीं है जिस के कारण देश की हालत ज्यादा बिगड़ रही है। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि

"Diplomatic pressure in Bangladesh and Myanmar to demolish the camps "

जो नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति है, उसके बारे में सभी जानते हैं कि कौन एंटी सोशल एलिमैंट्स को फंडिग और फाइनेन्स करता है? राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में होम मिनिस्टर ने कहा कि आईएसआई टैररिस्ट्स को फंडिंग करता है जिससे वे कैम्प चलाते हैं। देश में अस्थिरता पैदा करने में आईएसआई का मुख्य हाथ है। इस बात को सरकार खुद मानती है। असम के माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट और असम की समस्या है, उसका मुख्य कारण बांग्लादेश और म्यांमार में जो कैम्प चल रहे हैं, वहीं से सारी गतिविधियां चल रही हैं। वहां आर्म्स और एम्युनिशन की स्मगलिंग होती है। सिनो-म्यांमार के बॉर्डर के पास उन्हें वैपन्स आसानी से उपलब्ध होते हैं। उन कैम्पों के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान से सारे हथियारों की स्मलिंग हो रही है। इसके साथ ड्रग्स की भी स्मगलिंग होती है।

17.26 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

ड्रग्स स्मलिंग का पैसा इनसर्जैंसी एक्टिविटीज के काम आता है। ड्रग्स स्मलिंग का धंधा म्यांमार से वाया साजाऐन-तामाम्यांमार रूट पर होता है। सरकार इसे रोकने के लिए क्या काम कर रही है? मैं कश्मीर के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। एनडीए के समय में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ दो राउंड की बातचीत हुई थी। सात महीने हो गए हैं। सरकार ने एक बार भी उनके साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं समझी जबकि उनके साथ दो बार डॉयलॉग हो चुका था। क्या सात महीने में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई जिससे बातचीत शुरू हो सके। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेस के लोग यह कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ पहले इस बारे में बातचीत की जाए। वह इसके बाद ही भारत सरकार के साथ बातचीत करेंगे। इस बारे में सरकार की क्या इनटैंशन है? क्या वह इसकी परमिशन देंगे? क्या वह पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद हमारे साथ बातचीत करेंगे? सरकार की इस बारे में पूरी तरह से क्या इनटैंशन है? यह हमें मालूम नहीं हो रहा है। वह यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानैंट मैम्बरशिप के लिए भी हमारा विरोध करते हैं। हम जिस के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वहां वह इसका विरोध करते हैं। इस बारे में सरकार का स्टैंड क्लीयर होना चाहिए। जो ऐसे इनसर्जैंट्स ग्रुप और मिलिटैंट्स ग्रुप्स हैं, क्या हम उनके साथ बातचीत करेंगे या नहीं? ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेस बातचीत करने से पहले जो कंडिशन्स रखते हैं क्या सरकार उनको मानने के लिए तैयार है? सरकार कहती है कि Sky is the limit. क्या वे जो कंडिशन्स रखेंगे, सरकार उनको मानने के लिए तैयार है?

डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि 9 हजार से ज्यादा सैनिक बाडर से विदड्रा किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ 200 कैम्प्स चल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी भी देश पर विपदा है। ऐसी स्थिति में जो नौ हजार सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल से विदड्रा हुए, क्या सरकार ने उस पर अच्छी तरह से िवचार करके यह काम किया या किसी के प्रैशर से किया? यह बताने की यहां जरूरत है।

देश में नक्सलवाद की भी समस्या है। सामाजिक या आर्थिक नीति इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। क्या इस समस्या को हल करने के लिए सरकार कोई पैकेज दे रही है? आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नक्सलवादियों के साथ बातचीत की लेकिन कई दूसरी स्टेट्स उनके साथ बातचीत करना नहीं चाहती हैं।

लेकिन यह स्टेट की इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर प्राब्लम नहीं है। नक्सलवाद की प्राब्लम को भारत सरकार को खुद राज्य सरकार से बातचीत करके हल करना चाहिये।

सभापति जी, हैदराबाद में गृह मंत्री जी ने सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के सी.एम. को बुलाकर बातचीत की थी और उन्हें फरमान दे दिये गये लेकिन इस बात को यहां नहीं छोड़ देना चाहिये। और राज्यों में भी यही प्राब्लम है। इसलिये यह केवल राज्य सरकार की बात नहीं है। एक स्टेट की इंटरनल प्राब्लम या लॉ एंड ऑर्डर खाली उस स्टेट के लिये नहीं, वह सारे देश की प्राब्लम है। नेपाल से माओवादी आकर सारे देश में फैलते जा रहे हैं। इसलिये सरकार की नक्सलवाद की प्राब्लम को हल करने की क्या इंटैंशन है, मुझे ठीक मालूम नहीं लगती है। देश के सभी स्टेट्स को डायरेक्शन देनी चाहिये कि वहां की पुलिस फोर्स का मौडर्नाइजेशन किया जाये । इसके लिये स्टेट गवर्नमेंट को 100 परसेंट ग्रांट देनी चाहिये। आज देश गम्भीर परिस्थिति में है। सरकार को इस सदन को कांफिडेंस में लेना चाहिये और इस प्राब्लम को सौल्व करने की चिन्ता करनी चाहिये।

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Thank you, Sir. Today we are discussing in this august House about the internal security of our country. It is not a mere law and order problem. Not only in our country but at present there is a phenomenon of problems of internal security in the whole world also. You see our neighbouring countries like Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Pakistan, etc. and also the two most powerful countries of the world, USA and Russia. The problem is there in different countries for different aspects and for different reasons, whether it is on religious basis, whether it is an ethnic problem or whether it is a socio-economic problem. There are so many problems concerning this internal security of different countries.

But now we are concerned about our own country, our own motherland. I heard the speech of hon. Member Shri Vijay Kumar Malhotra. I heard the speeches of some Members of the Opposition Benches. They are considering this problem as a communal problem. They are accusing one section of religious people, those of minority community of our country who have sacrificed their whole life for the Independence movement and who have contributed much in our country's nation-building process also. But we are considering this problem as a socio-

economic and humanitarian problem also.

The emphasis of speeches of some of my friends is that the *madrasas* are the only problem for creation of this problem; in these *madrasas* the orphan boys are coming and staying there and they are learning some lessons which are anti-national, anti-India also and that is the main reason; and *madrasa* is the pivot of the dispute and insurgency and internal security of the country. I have heard one of the leaders of the BJP Benches. Their one-point programme is on Bangladeshi infiltrators and that is the main problem of this internal security situation of our country.

Day before yesterday our hon. Minister of Defence visited Kolkata and told in the media and to the people also that we should deal with the matter not with the arms but with a sympathetic view. The President of the BJP and the hon. Leader of the Opposition visited Assam and West Bengal in order to boost up the morale of his Party workers who are now demoralised after the elections. He told in the media in Guwahati and Kolkata that he advised his workers to fight against the Bangladeshi infiltrators.

That is their main programme. That is their one-point programme there. Sir, I am residing at Indo-Bangladesh border and the border is at a stone"s throw from my house. Sir, you do not forget that the language and the culture is the same of the people of West Bengal, the people of Tripura and some parts of Assam, and the people of Bangladesh. We are singing the song of Rabindranath Tagore and Qazi Nasrul Islam. We belong to the same culture, same creed and same language. So, I say emphatically that people are going from West Bengal, that is, India to Bangladesh and coming also from Bangladesh to India. This is happening not only at Indo-Bangladesh border, but at all the other borders also. That is not the problem of infiltration. My emphasis is on this point. That is why, the Bengali-speaking people were subjected to harassment and torture in Delhi, Mumbai and other places as they are speaking Bengali and some of them belong to the minority community also.

I want to remind my friends of what is happening in Andhra Pradesh, what is happening in Jharkhand, Maharashtra and Bihar. In all these States, there are taking place the activities of the People"s War Group and MCC who has connection with the Maoist group in Nepal. I want to ask whether they are doing all these activities on the basis of religion or with some communal angle. There is some basic problem also. Do not forget that after the Independence of our country, we are making Golden Jubilee celebrations with charm and in a colourful way. But

it is also a fact that since then, thousands and thousands, lakhs and lakhs of people are living without any bread, without any shelter and without any home. We should consider all these things from the socio-economic point of view.

My esteemed colleague Shri Mohan Singh pointed out correctly that before 1977, naxal activities had spread throughout West Bengal, but after the Left Front came into power in West Bengal, land reforms were implemented and land was distributed among the tillers. The top people had become landless because they had given their land to the tillers and this programme was successfully implemented in West Bengal. As a result of that, naxal activities subsided in West Bengal. Now, I come to Andhra Pradesh. Andhra Pradesh Government sat with the naxal leaders, with leaders of People"s War Group. What did they demand? They demanded that land should be given to the tillers. In all the States - barring West Bengal, Kerala and Tripura - whether it is Jharkhand, Bihar, Orissa or Andhra Pradesh, the big landlords are there and the landless peasantry are not getting any land. There, the programme of giving land to the tiller has not been implemented.

Sir, these activists are not alone. They are getting support from a large number of people. Without the support of the people, they cannot initiate or start all these activities. So, we should pinpoint the main thing behind the problem. Their diagnosis is different and our diagnosis is different. We consider this a socio-economic problem.

In the North-Eastern States, there are so many problems. In Manipur, one problem is of Armed Forces (Special Power) Act. Kangla Fort is under the control of the Army and since long, the people of Manipur have been demanding withdrawal of this draconian law. I say that I am not denigrating the Armed Forces, I am not denigrating the BSF. All the police forces of our country should be strengthened. We have no objection to that. But the attitude of the BSF and other paramilitary forces should be pro-people and they should be fair to the people; otherwise, they cannot subside all these problems.

I remind the hon. Minister that he knows of Manorama episode. Two or three years back, we had visited Manipur. At that time, Manipur was burning. Thereafter, elections took place and popular Government was formed. After that, due to Manorama episode, again Manipur is burning. What happened in Manorama case?

You all are aware that our sisters and mothers are running naked in the streets. It is a sorry and shameful state of

affairs of the civilisation of our country. We should understand that it is not a matter to be solved with the help of arms, or sword is not a solution to deal with these problems. One has to go to the root of the problem to solve these problems of the common people of our country. Otherwise, so many projects can be declared, but they would be of any use.

Three Prime Ministers went to Assam, and they declared so many economic packages for the people of Assam, Manipur, and other North-Eastern States. Many Prime Ministers have also visited Jammu and Kashmir, and have declared so many economic packages to solve their problems. The Government should ensure to solve these basic problems immediately.

I have the utmost respect and regard for our hon. Home Minister. I would request the hon. Home Minister, who is very competent, to please look into the matter from socio-economic point of view, otherwise, we will not be able to combat this problem, and subside it.

SHRI KHARABELA SWAIN : Are you referring to the socio-economic problems?

MR. CHAIRMAN : Shri Ajoy Chakraborty has concluded his speech. Nothing else will go on record.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN : Shri Ajoy Chakraborty has completed his speech. There can be no questions afterwards. Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

* Not Recorded

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ) : सभापति जी, आज देश की आंतरिक सुरक्षा पर अहम चर्चा इस सदन में हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो यूपीए की सरकार चल रही है और जो पार्टियां इनको समर्थन दे रही हैं, क्या उनका इस देश के साथ संबंध है? जो लोग हमारे नेता मल्होत्रा जी के भााण पर आपत्ति कर रहे थे, जब सीपीएम के सलीम जी बोले और अजय चक्रवर्ती बोले तो एक विाय का बार-बार उन्होंने उल्लेख किया कि बीजेपी के लोग सारी समस्याओं का सांप्रदायिकता के आधार पर आकलन करते हैं। हम एक समाचार आपने सामने रखना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडैन्ट्स यूनियन की जनरल काउंसिल की बैठक होती है। उस बैठक में एनएसयूआई की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जाता है कि चाइना के मैप में अरुणाचल प्रदेश को नहीं दिखाया जाना चाहिए। उसकी निन्दा करते हुए एक प्रस्ताव कांग्रेस की छात्र संगठन एनएसयूआई लाती है। वामवादी जो जेएनयू में अपना दबदबा रखते हैं, उनके रिजाल्यूशन को 11 वोटों से डिफीट करते हैं। एन्एसयूआई के लोग कहते हैं कि यह तो उनका पुराना चरित्र है, देश-विरोधी चरित्र है। यह खबर "पायनीयर " और "राट्रीय सहारा " में छपी है। ऐसे लोग क्या हमें देश की सुरक्षा के बारे में नसीहत देंगे जो देश के प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं रखते हैं। अगर सब कुछ ठीक चलता है और यह आंतरिक सुरक्षा, नक्सली हिंसा सामाजिक समस्या है तो फिर पश्चिम बंगाल में परिस्थिति कोई खराब नहीं है। 25 साल से ज्यादा समय तक उनका शासन चला है, और पश्चिम बंगाल में कोई परिस्थिति खराब नहीं है, वहां राम-राज्य की प्रतिठा हो चुकी है।

सभापति महोदय, इस सदन में जो चर्चा हो रही है, उसका एक वैचारिक धरातल है, उसका एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है। आज हम आरोप करते हैं कि जो यूपीए सरकार चलती है, उसका यह मल्टी डाइमैन्शनल डिसाइडिंग पॉइंट है, उसकी कोई नीति नहीं है। अजय चक्रवर्ती जी रक्षा मंत्री जी के बयान को उद्धृत कर रहे थे, मैं भी उद्धृत करना चाहता हूँ। दस दिन पहले यहां गृह मंत्री जी बयान दे रहे थे कि यहां बंग्लादेश से इनफिलट्रेशन नहीं, इम्मीग्रेशन हो रहा है। कल भुवनेश्वर में भारत सरकार के रक्षा मंत्री कहते हैं कि इस देश में एक प्रमुख समस्या बंग्लादेश से इनफिलट्रेशन की है। यह प्रतिपादित करता है कि सरकार के दो कैबिनेट मंत्री दो तरह के बयान देते हैं। एक मंत्री सदन में एक प्रकार का बयान देते हैं और दूसरे मंत्री दूसरे प्रकार का बयान देते हैं।

सभापति जी, मेरा इस सरकार पर आरोप है कि यह इंटरनल सिक्योरिटी को केजुअल रूप में लेती है और जिस प्रकार के समझौते कर रही है, वह ठीक नहीं हैं। यह सरकार कश्मीर समस्या पर वैचारिक दृटि से कनफ्यूज है। मैं आपके माध्यम से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब विदेश में भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राट्रपति मिलते हैं, समझौते का प्रस्ताव तैयार करने के लिए जब बात करते हैं, डायलाग का आदान-प्रदान होता तो, भारत की ओर से सीमापार घुसपैठ और क्रॉस बार्डर टैररिज्म का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता, इसका जवाब मंत्री जी अपने उत्तर में दें।

सभापति महोदय, मैं एक ही विाय उठाना चाहता हूं ; अगर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी समस्या की समीक्षा सही रूप में सरकार करती है, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वे इसका सही उत्तर देंगे कि क्या वहां के डैमोग्राफिक (Demographic) ग्राफ में 20 सालों में भारी परिवर्तन नहीं आया है ? आज से 20 साल पहले जम्मू रीजन का डैमोग्राफिक (Demographic) ग्राफ क्या था और अब क्या है, इसका उत्तर गृह मंत्री जी अपने बयान में दें।

महोदय, साम्प्रदायिक आधार पर जब कोई बात की जाती है, तो हमारे ऊपर एक ही आरोप हमेशा लगाया जाता है कि हम एक ही सम्प्रदाय विशे की बात करते हैं। यहां बार-बार कांग्रेस की ओर से एक ही प्रश्न उठाया गया कि हमारी सरकार के समय हमारे मंत्री भारत की जेलों में बन्द पाकिस्तानी आतंकवादियों को कंधार छोड़ने गए। मैं बताना चाहता हूं कि यदि सरकार में हिम्मत है, तो वे ऐसा प्रस्ताव पारित करें कि हमने गलती की, तब उसे मालूम होगा। क्या हम देश के लोगों को जिनका ि वमान अपहृत किया गया था, जिनको कंधार ले जाया गया था, क्या उनको मरने के लिए छोड़ देते। इस प्रश्न पर कांग्रेस हमें हमेशा कठघरे में खड़ा करती है, हमेशा हमारी निन्दा करती है। अगर हमने गलती की है, तो वह प्रस्ताव पारित करे और बताए कि वह इसके विरुद्ध है और हमने गलती की है, तब उन्हें पता लगेगा कि इस बारे में देश की क्या भावनाएं हैं।

महोदय, बलिदान का ठेका केवल कांग्रेस ने ही नहीं लिया है। कांग्रेस के लोग क्यों भूल जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कहां हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ ? श्री दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत बड़े विचारक थे। उनकी हत्या मुगलसराय में की गई थी। इन्हें उनकी याद नहीं आती है। बलिदान पर किसी की मौनोपोली नहीं है।

महोदय, जब हम नक्सलियों के बारे में प्रश्न उठाते हैं, तो कांग्रेस सरकार इसको ला-एंड-आर्डर का प्रश्न बताकर छोड़ देती है। गृह मंत्री नक्सली समस्या से निपटने के लिए आठ राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं और कहते हैं कि यह एक राज्य की समस्या है। मैं पूछना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री बयान दें कि आंध्र ्र ादेश पुलिस की रिपोर्ट क्या है, क्या नक्सलियों के संपर्क आई.एस.आई. के लोगों से नहीं हैं। पुलिस की रिपोर्ट है कि नक्सलियों और आई.एस.आई. एक-दूसरे के

संपर्क में हैं और उनकी नेपाल से लेकर तामिलनाडु तक एक कोरीडोर बनाने की योजना है ?

महोदय, हमें किसी के साथ बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है, बात करिए। इस देश में 57 साल की आजादी में से 50 साल तक तो आप ही का शासन रहा। अपने शासन काल में आपने बुनियादी समस्या का समाधान नहीं किया, इसलिए यह प्रश्नचिह्न अब खड़ा हुआ है। आप किसी से बात करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किन शर्तों पर बात होगी, वह देखना चाहिए। कोई कहते हैं कि हम शस्त्र रखकर बात करेंगे, हम आर्म रखकर बात करेंगे, तो क्या ऐसे लोगों से बात करने की अनुमति भारत का संविधान देता है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा ? हमारा यह आरोप है कि कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के साथ वोटों के लिए समझौता किया था। इसीलिए आज वहां बात हो रही है।

महोदय, एन.एस.सी.एन. के साथ कांग्रेस ने बात शुरू की है। जब एन.एस.सी.एन. की बात आती है, तो हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के उस समय के मुख्य मंत्री जमीर साहब के साथ, खापलांग ग्रुप के क्या संबंध थे, क्या उसके मुखिया जो नगालैंड में रहते थे, उनके साथ संबंध नहीं थे, एन.एस.सी.एन. के साथ इतने दिन के बाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बात शुरू की थी। गृह मंत्री जी जब इस चर्चा का उत्तर दें, तब इस बारे में वे हमें बताएं।

सभापति महोदय, इंटरनल प्रॉब्लम को साम्प्रदायिक रूप दे दिया जाता है। एक मित्र कह रहे थे कि पोटा की अगर यह सरकार आलोचना करती है और कहती है कि हम कम्युनल विाय को क्यों उठाते हैं, एक सम्प्रदाय की बात क्यों करते हैं। मैं महाराट्र के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले पांच सालों से महाराट्र में कांग्रेस का शासन था। वर्ा 2002 से लेकर वर्ा 2003 के अंदर मुम्बई में, महाराट्र में छः बम-विस्फोट हुए। महाराट्र की पुलिस, कांग्रेस शासन की पुलिस उन्हें पकड़ती है। सारे लश्कर-ए-तोएबा के साथ सम्पर्क रखते हैं । और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि किस विाय को लेकर भारत में लश्कर-ए-तोएबा प्रचलित है।

सभापति महोदय, दिल्ली के अंदर ज़ामिया-मिलिया में तीन लोगों को मई, 2002 में पकड़ा जाता है, जिनके पास डिस्ट्राय नेशनलिज़्म एस्टेब्लिशड खिलाफत की एक कैसेट मिलती है।â€¦ (व्यवधान)अगर दुर्भाग्य से कोई विशेा सम्प्रदाय के व्यक्ति इस विाय से जुडते हैं तो क्या उसे नहीं उठाना चाहिए ? देश और सदन के सामने नहीं लाना चाहिए, यह साम्प्रदायिक हो जाता है ? मदरसे के बारे में कहा जाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मदरसा खुलता है। यह मदरसा दिल्ली और मुंबई में क्यों नहीं खुलता है, भारत की सीमा पर यह क्यों खोला जाता है ? इसके संबंध में भारत सरकार की रिपोर्ट क्या है, इसका भी सदन के सामने खुलासा किया जाए।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आईएमडीटी के बारे में कहना चाहता हूं, क्या भारत में दो विधान चलने वाले हैं? भारत में क्यों इमीग्रेशन एक्ट का अलग आईन चलेगा, असम में क्या अलग चलेगा? हम मांग करते हैं कि अगर ऐसे डबल स्टैंडर्ड की पालिसी रहेगी तो देश में इंटरनल सिक्योरिटी की बात सिर्फ एक भााण ही रह जाएगी। हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि यह एक पार्टी का विाय नहीं है, सरकार को जो मदद चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर किसी विाय पर कोई आपत्ति उठानी है तो यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकार में है। यह साम्प्रदायिक विाय नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आईएमडीटी एक्ट को रिपील किया जाए । एक मल्टी परपज़ नेशनल आईडेंटिटी कार्ड शुरू किया जाए। अब घुसपैठ एक समस्या है और उसे लोग मानते हैं। गृह राज्य मंत्री जी ने भी स्वयं उसे स्वीकार किया है। जो लोग आर्म्ज़ के साथ बात करना चाहते हैं, देश में किसी के पास भी अनलाइसेंस आर्म्ज़ है तो उसे बैन किया जाए और नक्सली समस्या को डील करने के लिए एक ज्वाइंट कमांड फोर्स तैयार की जाए। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय. हमें कहा गया कि एनडीए छः साल तक सत्ता में रहे, आपने क्यों सीमा पार आतंकवाद के लिए बात नहीं की, बंगलादेशी घूसपैठियों के बारे में क्यों नहीं बात की। हमारी सरकार ने बात की थी, भूटान के साथ बैठ कर भारत सरकार ने बात करके, भूटान की राज सत्ता की सहायता लेते हुए, वहां जाकर हमारे देश ने बगावत करने वाले लोगों को पकड़ा था। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ भााण देते हैं।â€¦ (व्यवधान)हम म्यांमार भी पहुंचे थे। इस सरकार को हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए दोबारा आरोप करते हैं। क्रिमीनली केजुअल है, होश में आएं। देश और राट्र की अस्मिता को सुरक्षा दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यावाद।

SHRI KIRIP CHALIHA (GUWAHATI): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving us this opportunity to discuss this very important subject, the subject of internal security.

National security, be it internal or external, cannot unfortunately, be a uni-dimensional affair. It cannot be a uni-dimensional affair because security depends upon a huge number of factors. You also got to have an attitude to understand the problems of security.

I thank Ramji Lal Sumanji for he has forwarded his arguments and placed his views in a very constructive, unbiased and non partisan manner. He has been able to speak in a manner due to which situation does not get aggravated. Unfortunately, many of us, because of our very firm, maybe wrong, convictions about ourselves, tend to pass comments which can have detrimental repercussions in many places, especially in places which have high sensitivity, places like the North-East. One's comment in this highest forum of democracy about communities can have repercussions which may lead to aggravation of national security. That is because, national security, as I said, is not a uni-dimensional phenomenon.

Shri Santoshji will agree with me that to build up national security, internal security or external security of the country, सिर्फ पुलिस फोर्स से या मिलिट्री से सिक्योरिटी नहीं बनती है। एक देश की सिक्योरिटी, उसकी शक्ति हजारों सालों से हमारी जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफीकल सिचुएशंस हैं, हमारे देश की जो सभी चीजें हैं, development, food security, ethnic pride and contradictions, isolation, religious differences, ये सारी बातें सिक्योरिटी को छूती हैं। सिर्फ मिलिट्री या पुलिस से ही सिक्योरिटी नहीं बनती है। यही भूल कभी-कभी लोग करते हैं, जो सोचते हैं कि बड़ी-बड़ी बातें करके if we act in a partisan manner and if we act like great patriots only by critising the present incumbent, we become extremely efficient, then, we distort facts, then, we lose our sense of reality and then our appraisal of national security cannot be realistic and true. After all, as I said, national security cannot be a matter of politicisation. It cannot be a matter for personal interpretation because national security, even internal security for that matter today, has connections with international agencies, international events and global events. हमें बड़ी हंसी आती है, जब लोग अपने छोटे से दायरे में इसे ले जाकर ऐसे-ऐसे इण्टरप्रिटेशन करते हैं, जिसके लिए मैं क्या कहूं। I feel very funny or discouraged. यह

असेम्बली ऑफ क्लैशिंग इण्टरैस्ट नहीं है। Parliament is not an assembly of clashing interests. When we discuss issues like security of nation, when we would talk of defence; when we talk about law and order, and for that matter when we talk about a number of vital problems faced by this country, this is a deliberative assembly where we ought to get together so solve certain problems. यहां पर डिबेटिंग पाइण्ट्स करके या अपने-अपने पोलिटिकल एजेण्डा को लाकर जब डिस्कशंस होते हैं, उसी एजेण्डा के तहत लास्ट 6 महीने से हमारे होम मिनिस्टर साहब के खिलाफ कितनी सारी अफवाहें हैं, कितनी सारी बातें हैं, जैसे कि 6 महीने में सब कुछ बदल सकता है। 6 साल में जो लौह पुरुा हैं, उनको भी हम जानते ह। We have high respect for him. पर लौह पुरुा की एक साध्वी ने एक मीटिंग में जो हालत कर दी है और अभी एक और टी.वी. एक्ट्रैस ने जो हालत की है, वह हमने देखा है। लौह पुरुा पेपर टाइगर बन गये हैं। बी.जे.पी. का जो 6 साल का शासन है, उसे हमने देखा है। We have seen the problems. We have seen the Prime minister of this country very very pitifully giving big dodgers - this is thus far and no further. Brinkmanship cannot be statesmanship.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, I have discussed with other colleagues also regarding extending the time of the House up to 7 o" clock and the hon. Minister of Home Affairs will reply tomorrow.

MR. CHAIRMA: Hon. Members, shall we extend the time of the House till 7 o" clock?

...(*Interruptions*)

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : इण्टरनल सिक्योरिटी से इसका क्या सम्बन्ध है?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: So, the time of the House is extended till seven o" clock.

...(*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ सिंह : इस पर कल बहस करवाइये, ताकि जो लोग आज नहीं बोल सके, कल बोल सकें।â€¦ (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : जो आज नहीं आये हैं, अगर वे कल बोलेंगे तो कल सुबह से दोपहर तक चलेगा। कल सुबह 11 बजे आयेंगे तो कहेंगे, अब हम बोलते हैं। जो आज आये हैं, वही बोलें।

MR. CHAIRMAN: No discussion. Nothing will go on record except the speech of Shri Kirip Chaliha.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Chaliha, you can speak, but there should be no discussion between Members.

...(*Interruptions*)

SHRI KIRIP CHALIHA : I am concluding, but my party"s time is there. ...(*Interruptions*)

18.00 hrs.

What many of my friends have said is this. You cannot analyse the internal security problem of this country with a jaundiced eye. I do not like to be an agent of my party when we talk of internal security. I come from North-East. I speak about terrorism in North-East. I have carried the dead bodies of my colleagues who were victims of terrorism. I have fought terrorism on the face of it as a Youth Congress leader. I carried dead bodies. I know what these guns are. Let me tell you about the scenario in the North-East. I compliment the Home Minister repeatedly for this. I think, he is the right man with a right temperament. क्या कहना चाहते हैं कि अगर कहीं ऐक्सट्रीमिज़्म होगा, टैरोरिज़्म होगा, नक्सलाइट की प्रॉबल्म होगी तो आप उनसे बात नहीं करेंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे? ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. There are about 15 Members to speak.

...(*Interruptions*)

SHRI KIRIP CHALIHA : I come from North-East. You must give me a chance to speak. ...(*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : He is using high-sounding words. He has nothing to say. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Kirip Chaliha says.

*(Interruptions) â€¦**

SHRI KIRIP CHALIHA : Sir, about the North-East we have a very peaceful negotiation going on now with Naga rebel leaders. The Commander-in-Chief of ULFA who had all along been saying that he would never come for talks,

for the first time, he has sent feelers saying that he is willing to come for talks. For the first time, the NCDFB has come for talks. In spite of all the politicisation by the BJP and the then Defence Minister who did all the negotiations with the insurgents with political motive the Manipur situation has improved. Now, it is back on the rails. And I congratulate the Home Minister for his patience, for his statesmanship about the handling of the situation. What is the harm in talking to naxalites? Do the naxalites not have an ideological base? Is it wrong to talk to naxalites? That is what they say. They want to convert this whole country into areas of naxalities influence. Forty per cent of the districts are today ravaged by the menace of naxalites. Prof. Malhotra was saying that we must apply force. I just remind him what has been said here. He will agree that the use of force is only temporary. It gets subdued for a moment. But it does not remove the necessity of being subdued and the nation is not governed just perpetually to be conquered. Just because you have the Army, just because you have a huge police force, just because people of Manipur or Nagaland or Tripura or the North East are small in number, you do not use this as a solution. Prof. Malhotra will agree that the process of dialogue, the process of understanding small nationalities and their problems and grievances is important. Why should there be politicisation? You are suddenly raking up old issues. One leader from the BJP goes to Assam and politicises the whole situation

* Not Recorded

and once again incites the people. The biggest danger to the nation's security will be if the political divide is carried to an extent whereby all contradictions become a step for instability.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KIRIP CHALIHA : This is a huge subject and you are not giving me the permission to speak. I thank you for all the opportunity you have given me to speak.

SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate on this important subject.

Today, we are discussing the problems of international security in the country. We should find out the root cause of this problem. Many speakers have highlighted the main causes of this problem. I would also like to highlight some of the main problems concerning the internal security. Most of them, who are indulged in these separatist and extremist activities, are the Indians and they all belong to the poorer sections of our country. If I may say correctly, most of them are the downtrodden people belonging to the Scheduled Tribes community, backward communities and the economically weaker sections of our country, and they are all taking the help from our neighbour countries.

18.06 hrs. (Shri Pawan Kumar Bansal *in the Chair*)

Sir, in this way, the States which are having the international borders with them are the worst affected by these separatist and extremist activities. The States like Jammu and Kashmir, the entire North-Eastern States and Uttar Pradesh are all facing this problem. To guard our borders, the Government has created para-military forces like Border Security Force and CRPF. But this is not enough. Fencing of our borders would be one of the effective methods to curb this problem. But the work is going on at a very slow pace. The decision had been taken to fence all the borders of the entire North-East. The work has started also, but the progress is very slow. There are some new problems there. The Bangladesh Government is not agreeing to fence it at the Zero Point. Our Government has agreed to have it at 150 kms away from the Zero Point border. Here, lakhs of small cultivators, small land owners are on the verge of losing their land, as it has all gone under the zone of fencing. There is some announcement that some time, the border would be opened and they can go to work there. But this is not enough. Therefore, I would suggest a solution to the Government that, if it is possible, they should compensate for all those lands that are coming in the way of fencing. This would be a very good solution. Otherwise, those cultivators, small land owners are bound to suffer.

Sir, my next point is that these extremist and separatist groups are getting arms and ammunitions from outside. These activities started in our country some 25 to 30 years ago. At that time, they were using muzzle-loaded pipe guns. But now, they are getting semi-automatic weapons and sophisticated weapons. They are getting them through Bangladesh and some of our other neighbouring countries. In smuggling these sophisticated arms, our neighbouring countries are helping these groups. I would, therefore, request the UPA Government to talk to our neighbouring countries and see that they should stop all these arms smuggling to our country.

Sir, I think, it is known to the Government that almost all these groups, outfits have camps going on in our neighbouring countries. Some camps are being operated in Bangladesh, Myanmar and Pakistan. So, we should try to exert some pressure on the neighbouring countries to see that they stop helping these extremist groups working

in our country. Rather, these countries should help us in curbing these extremist activities.

Sir, we should also continue our dialogues with these extremists groups. Political solution is the best solution.

In Mizoram also, earlier a lot of violence was taking place.

A lot of killings had taken place but now there is not such type of extremist activities. Wherever these extremists are there, we should continue to have a dialogue with them so as to find a solution to the problem.

It is a very sorry state of affairs that some of the leading political parties in our country have links with these extremists. I can say this with regard to both the BJP and the main ruling Party, Congress. Especially, in my State, during the last Assembly elections, which were held on 27th February, 2003, the Assembly seats were divided amongst the extremists for INPT and Congress. After one year there were another parliamentary elections, the last parliamentary elections, in which the BJP which was at that time in power at the Centre, officially took help from the extremist INPT forces. So, I request that the main leading ruling Parties should not indulge in such activities as it gives encouragement to these extremist forces.

Sometimes, during encounters these extremist forces are getting killed by the paramilitary forces. But in these encounters civilians are also sometimes getting killed. My request is, such civilians who are being killed in cross fires should be duly compensated as it is a big loss for the poor families.

In the month of May next year, Autonomous District Council elections will be held in Tripura. We are afraid that the main Opposition Party, Congress will again align with these extremist forces. I warn the Government that if it will be so - the UPA Government at the Centre, which is being run with our support − we will review our decision taking that into consideration.

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, रामजीलाल सुमन जी द्वारा आन्तरिक सुरक्षा की जो चर्चा उठाई गई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने शब्दों में चिंता ज़ाहिर की है। हम भी उनकी चिंता से अपने को सम्बद्ध करके अपनी बात आगे रखना चाहते हैं।

यह नयी सरकार बनी है, तब से यह समस्या आई है और इसलिए ऐसी चर्चा आयी है, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार की चर्चा पिछले सत्रों में भी चलती रही है और इस सत्र में भी प्रश्न और शून्यकाल के माध्यम से हम लोगों ने चर्चा उठाई है। हम यह महसूस करते हैं कि देश भी चिंतित है और सरकार भी निश्चित तौर पर चिंतित होगी कि इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढ़ा जाए ? **जो आन्तरिक सुरक्षा का सवाल है, इसका एक कारण हम नहीं मानते। यह बात ठीक है कि हमारे जो कुछ पड़ौसी देश हैं, उनकी तरफ से हमारे देश में उथल-पुथल मचाने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। आतंकवादी घटना की वजह से जम्मू-कश्मीर ही प्रभावित नहीं है बल्कि कोई घटना घटती है तो सारा देश प्रभावित हो जाता है।**

अब तो जम्मू-कश्मीर से बढ़कर देश के अन्य भागों में ये ताकतें अपना सिर उठाने लगी हैं और इसके लिए कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। जहां हम लोग खड़े हैं और बैठे हैं, वे उसके भुक्तभोगी हैं, क्योंकि यहां भी उनका हमला हो चुका है.

सेना में कटौती की चर्चा चल रही है। हमारे जैसे लोग उससे चिंतित हैं। चिंतित इस बात से हैं कि एक सवाल के उत्तर में गृह मंत्री जी का बयान आया, जिसकी चर्चा हो चुकी है, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की घटनाओं में कमी हो रही है। इन्होंने आतंकवादियों को भाई के समान देखने की बात भी लोक सभा में कही थी। दूसरी तरफ अखबारों में छपा और अन्य स्रोतों से जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, जो रक्षा मंत्री जी के बयान आए हैं, उनसे लगता है कि आतंकवादी फिर यहां घुसने के लिए अपना ठौर-ठिकाना ढूंढ़ रहे हैं कि किस रास्ते से प्रवेश करें। ये दो तरह की बातें हो जाती हैं। पता नहीं गृह मंत्री जी किसको अपने भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या उन लोगों को अपना भाई स्वीकार करते हैं जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में माताओं और बहनों की इज्जत और अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है ? क्या उनको वह भाई मानना चाहते हैं, जिन्होंने सेना के जवानों पर जुल्म ढहाकर वहां जश्न मनाने का काम किया है या उन आतंकवादियों को भाई बनाना चाहते हैं जो हमारे देश में उथल-पुथल मचाकर देश की अस्मिता पर खतरा पैदा करना चाहते हैं ?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : आपने सवाल किया है इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। हम उन लोगों को अपना भाई समझते हैं जो भूख से, बेकारी से या घर नहीं होने की वजह से या आर्थिक वजह से या फिर दूसरों के जुल्म की वजह से गुस्से में आकर हथियार लेकर निकलते हैं। उन्हें समझाने की जरूरत है, ऐसा हम मानते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : हमारे राज्य में करीब 37 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे है...(व्यवधान)... (कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

MR. CHAIRMAN : That will not go on record.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This is not going on record. Mr. Swain, I am requesting you to please cooperate.

*(Interruptions)**

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. हमें समय का ध्यान रखना है। सिर्फ जो बात प्रभुनाथ सिंह जी कहेंगे वही बात रिकार्ड में जाएगी।

â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I would request you to please cooperate.

â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। हमारे पास समय कम है।

श्री शिवराज वि. पाटील : तो क्या उन लोगों को गोली मार देंगे, उनको समझाना होगा।â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The Minister has the right to intervene. हमें इसे आज खत्म करना है आपके साथी भी बोलना चाहते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कह सकते हैं। उस वक्त जो कहना है वह कहें।

â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने कंसीड किया था उन्होंने बात कही है, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। जब आपका मौका आएगा, तब आप अपनी बात कहना।

.....

* Not Recorded

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हम उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो सुनोयिजत ाडयंत्र के शिकार होकर भारत में उथल-पुथल मचाना चाहते हैं। मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी वार्ता के खिलाफ मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है। जब आपसे पहले की सरकार थी, जिसके अगुवा माननीय अटल जी थे, जो बस से लाहौर गए थे, जिसका स्वागत सबने किया था, आपने भी किया था। सब चाहते हैं कि वार्ता से समस्या का समाधान हो। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि दुश्मन दोस्त तीन परिस्थितियों में बनता है। एक वह परिस्थिति होती है, जब उसकी नीयत साफ हो जाती है और फिर वह दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दूसरी परिस्थिति वह होती है जब वह महसूस करता है कि हम इतने कमजोर हो गए कि हम लड़ने की स्थिति में नहीं है। तीसरी परिस्थिति वह होती है जब वह चाहता है कि विश्वास में लेकर इनको धोखा दे। आप उनकी नीयत परखें। आपके पास बहुत सी एजेंसीज हैं। उनके माध्यम से पता करें, ढूंढिए कि आखिर उनकी नीयत क्या है। अगर उनकी नीयत साफ है तो आप वार्ता के माध्यम से देश में अमन-चैन ला दें, तो उससे बड़ा खुशहाली का दिन देश में कोई नहीं हो सकता। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे कदम बढ़ाएं। लेकिन यह कहते हैं कि आप सावधान रहें। सावधान उन लोगों से रहें जो आपको विश्वास में लेकर धोखा देना चाहते हैं, तो वहां गृह मंत्री जी आतंकवादियों से लड़ने के सिवा, हथियार के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। आप अपने सैन्य बल को मजबूत करें, ताकि वे उनका मुकाबला कर सकें।

हम यह भी मानते हैं कि देश की बढ़ती हुई आबादी, रोजगार का घटना, बेरोजगारी का घटना, आतंकवाद की घटनाओं के लिए कारण नहीं बन रहे हैं। लेकिन नक्सल वाद की घटना में ये कारण जरूर बन रहे हैं। आतंकवाद की जो घटनाएं इस देश में घट रही हैं वे सुनियोजित ढंग से बढ़ रही हैं। दुनिया का दादा देश अमरीका की नीयत भारत के प्रति बड़ी खराब है। जिन दिनों हम सरकारी पक्ष में बैठा करते थे उन दिनों भी हम कहा करते थे कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति से अमरीका अंदर ही अंदर चिंतित है। पड़ोसी देश को आर्थिक सहायता और हथियारों की मदद करके वह उनका इस्तेमाल आपके देश में करवाता है। आपके पड़ोस में जो नेपाल है वह आईएसआई का अड्डा बना हुआ है जहां रेडियो, टेलीविजन के द्वारा भारत के खिलाफ प्रचार किया जाता है और वहां से जाली रुपया भेजकर भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का प्रयास भी चलता है। अगर आप अपनी खुफिया एजेंसियों को लगाएंगे तो आपको इन सब बातों का पता चलेगा। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश और बिहार से लगी हुई है। हम बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए हमें वहां की कुछ बातों की जानकारी रहती है। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि उन सब इलाकों को देखने का कार्य कीजिए।â€¦ (व्यवधान)नक्सलवाद की जहां तक बात है तो देश के आधे राज्य इससे प्रभावित हो चुके हैं। नक्सलवाद की घटना को विधि-व्यवस्था की घटना के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकता है। नक्सलवाद की घटना में कहीं जाति के नाम पर, कहीं सम्प्रदाय के नाम पर जो घटनाएं घट रही हैं, आर्थिक तंगी उसका एक बड़ा कारण है। हम लोग भी उससे प्रभावित हैं। नेपाल से माओवादी बिहार के जहानाबाद, औरंगाबाद इलाकों में तथा और चार-पांच जिलों में पैदल ही नहर के रास्ते कंधे पर हथियार टांगकर आते हैं और घटनाएं करके फिर नेपाल चले जाते हैं। पुलिस की हिम्मत उनके सामने आने की नहीं होती है। बिहार सरकार वहां कुछ नहीं कर पाती है। जब लोक सभा में इन सवालों को उठाया जाता है तो कहा जाता है कि यह राज्य का मामला है। इन सवालों को आप राज्य का कहकर टाल नहीं सकते हैं। राज्य भी तो देश के अंदर ही आता है। जब आप महसूस करते हैं कि राज्य उन सब चीजों से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है तो केन्द्र को पहल करनी चाहिए। कई राज्यों में अजीब घटनाएं घट रही हैं। चिट्ठी भेज दी जाती है कि दस लाख रुपया भेज दो । ऐसा अभी बिहार में एक डाक्टर के साथ हुआ। उसकी हत्या कर दी गयी और हत्यारे खुले आम कहते हैं कि हमने हत्या करवाई है। हमें पैसा चाहिए क्योंकि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमें आर्थिक मदद कीजिए। पैसा नहीं दोगे तो सब डाक्टर्स को हम मार देंगे। इस मसले पर पूरा बिहार बंद रहा और अखबारों में इस घटना की खबर छपी। अखबार में खबर छपी की 65 आदमी चिकित्सा के अभाव में मारे गये लेकिन यह तो शहर का आंकड़ा है, जो गांव में चिकित्सा के अभाव में मरे, उनकी संख्या की गिनती नहीं है। चिकित्सक हड़ताल पर रहे और उनके कारण कितने मरे, उनकी संख्या की गिनती नहीं है। इसमें सम्पन्न लोग नहीं मरे क्योंकि वे तो शहर में इलाज कराते हैं, लेकिन गांव में जो मरे, वे गरीब लोग थे, जिनके पास पैसा नहीं है। इन सब चीजों को राज्य की, विधि-व्यवस्था की चीज कहकर टाला नहीं जाना चाहिए। मेरे कहने पर आप विश्वास मत कीजिए और अपनी एजेंसियों से आप पता करवा लीजिए। हम यह भी नहीं कहते हैं कि राज्य सरकार से टकराव लेकर ऐसा कीजिए। राज्य सरकार से सहायता लेकर और इसे देश की समस्या मानकर इसका समाधान निकालिये। वहां अमन-चैन नहीं है। वहां पर अगर बच्चा स्कूल जाता है तो मां किडनैप हो जाती है और अगर मां बच्चे को स्कूल लेने जाती है तो बच्चा किडनैप हो जाता है। लोगों को विश्वास हो गया है कि वे इस राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। हम घर से बाहर नहीं जा सकते, बाजार नहीं जा सकते, सगे संबंधियों के घर जाते हैं तो हत्या होती है। वहां अमन-चैन समाप्त हो चुका है।

मल्होत्रा जी ने बांग्लादेश के घुसपैठियों का सवाल उठाया। हम मानते हैं कि वह भी एक समस्या है। 6 साल तक हमारी सरकार थी। हमने इसमें कितनी पहल की

और कितनी सफलता पायी, यह भी हमारे साथियों को बताना चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं यदि हमने सफलता नहीं पायी तो नई सरकार इसमें पहल नहीं करेगी। यदि बांग्लादेश के घुसपैठियों या दूसरे विदेशियों के कारण देश में समस्या पैदा होती है तो उसमें पहल करनी चाहिए और पहल करके इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

मदरसों की चर्चा चलती है। हम यह बात नहीं मानते कि हर मदरसों में आईएसआई की भूमिका है या दूसरा कोई प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन बॉर्डर इलाकों में 1-2 जगहों से ऐसी सूचना मिलती है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं कह नहीं सकता लेकिन आम चर्चा है - जैसे बेतिया का इलाका है, आप वहां खुफिया तंत्र लगाइए और इसे दिखवाइए। अगर ऐसा होता हो तो उसे रोकना चाहिए। मदरसे तालीम की चीज है। हमारे यहां देहाती इलाकों में मदरसे हैं जहां बच्चों को तालीम मिलती है। वहां आईएसआई की कोई गतिविधियां नहीं चल रही है और न ही विदेशी पूंजी लगी है लेकिन बेतिया जो नेपाल से सटा बॉर्डर इलाका है, वहां से सूचना मिल रही है कि वहां ऐसी घटनाएं घटती हैं। आप इन पर निगरानी करवा दीजिए। अगर ऐसा हो तो रोकिए क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। गृह मंत्री जी, कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन को हाई लाइट किया जाता है। जब अपराधी अपनी तस्वीर टेलिविजन में देखता है और अखबार में मोटे-मोटे अक्षरों में देखता है तो उसका मनोबल बढ़ता है। वह सोचता है कि अगर इससे भी बड़ा अपराध करेंगे तो और बड़े अक्षरों में छपेगा। जो चीजें समाचार में लाने लायक हैं, उन्हें ही लाना चाहिए। जिन चीजों को समाचार में लाने से देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा महसूस होता हो, उन चीजों पर रोक लगाने की जरूरत है। इस संबंध में मीडिया के लोगों से बातचीत करके कहना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें है जो टेलीविजन और अखबार में लाने से समस्या को बढ़ावा मिलेगा, समस्या घटेगी नहीं, उसे वंचित रखा जाए।

सभापति जी, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, इसलिए एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज आपके उत्तर का पूरे देश को इंतजार है। टीवी पर आ रहा है कि सदन में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हो रही है। देश की जनता यह जानना चाहती है कि गृह मंत्री जी बताएंगे कि उन्होंने देश के एक-एक व्यक्ति को सुरक्षित रखने की क्या तकनीक अपनायी है, क्या व्यवस्था की है, क्या नया फार्मूला निकाला है? हम चाहेंगे कि कल जब आप जवाब दें तो अपने जवाब के माध्यम से देश की जनता को यह बता कर निश्चिन्त करें कि वे सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। हमें आशा है कि यदि आप कहेंगे तो इस पर अमल भी करेंगे और आपके कल के जवाब के बाद देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं।

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर) : माननीय सभापति महोदय, आंतरिक सुरक्षा के संबंध में यह सदन नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर रहा है। अनेक माननीय सदस्यों ने विशेा करके श्री रामजीलाल सुमन, श्री मोहन सिंह और अन्य सदस्यों ने इसके बारे में विस्तार से बताया। मुझे मालूम है कि मेरा समय कम है और मुझे उतने विस्तार से बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विाय दो घंटे-तीन घंटे तक भी चर्चा करते रहो तो भी समय बहुत कम है। इस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता है।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि देश में आंतरिक सुरक्षा पर जो खतरा है, उसके कुछ कारण हैं। उन कारणों में उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातीयता, सीमावाद और क्षेत्रवाद की चर्चा की लेकिन इसके अतिरिक्त दो पहलू हैं - एक यह है कि देश की आजादी के बाद निरन्तर देश प्रेम की भावना कुछ लोगों में कम होती जा रही है।

मैं सब लोगो के बारे में नहीं कह रहा हूं। जिस प्रकार देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिये अमीर-गरीब, ऊंच-नीच या धर्म का भेदभाव किये लोग मिलकर आगे बढ़ते थे, आज वह भावना दिखाई नहीं देती है। आज उसका कारण आर्थिक स्थिति खराब होना, बेरोज़गारी, भुखमरी बताया जाता है। वैसे देश की आजादी के पहले भी ये कारण थे लेकिन सब लोग - जिनके तन पर कपड़ा नहीं था, पेट में अन्न का दाना नहीं था, वे भी भारत माता की जय और वन्दे मातरम् बोलते हुये देश की आजादी के संघा में कूद पड़े। आज उस प्रकार की भावना का अभाव है। इस भावना में निरंतर बढ़ोत्तरी होती जा रही है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि देश की आजादी के पहले लोगो में समर्पण की भावना, सर्वोच्च न्यौछावर करने की भावना या देश-प्रेम से ओत-प्रोत भावना बहुत ज्यादा थी लेकिन आज उस में कमी आ रही है। उसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग देश में रहते हुये भी देश से अलगवादी होते जा रहे हैं। इसका एक पहलू यह भी है कि जो बात कुछ माननीय सदस्यों ने नहीं कही, मैं उसे कहना चाहता हूं। जो पहलू पहले उल्लिखित हो चुके हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा।

सभापति महोदय, एक बात यह है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, जिनके तारतम्य में कानून बने हैं। अनुच्छेद की खामियों के कारण कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके कारण अलगाववादी स्थिति पैदा हुई है। इससे आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। उस खतरे में निरंतर वृद्धि हो रही है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेा अधिकार मिले हुये हैं। इनमें मिजोरम,नागालैंड, मणिपुर शामिल हैं। अन्यान्य अनुच्छेद-2 में ए.बी.सी.डी. जोड़कर उन्हें कुछ विशेा अधिकार दे दिये गये हैं। इससे भी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। संविधान की धारा-370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ विशेा अधिकार दे दिये गये हैं। अगर भारतीय संसद कोई कानून पास करती है, तो जब तक वहां की विधान सभा उसके लिये सहमति नहीं देती, वह कानून लागू नहीं होता है।

18.32 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the chair)

अगर माननीय गृह मंत्री जी या मैं या कोई और व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहना चाहे. जमीन खरीदना चाहे या वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना चाहे या चुनाव लडना चाहे तो वह अधिकार उसे नहीं मिल सकता, जबकि कहा यही जाता है कि देश के किसी भी राज्य में भारत के नागरिक को रहने का अधिकार है। संविधान के अनुसार सभी राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं लेकिन कई राज्यों को संविधान के अनुसार विशेा अधिकार दिये गये हैं । इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अघोाित युद्ध छेड़ रखा है। वहां के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को मार-मार कर बाहर कर देते हैं और बाहर होने पर वहां निरंतर ि वदेशी घुसपैठ में वृद्धि होती जा रही है। उन घटनाओं का प्रभाव जम्मू कश्मीर पर इतना हो गया है कि कोई साहस नहीं कर पाता। इसलिये वहां लोग परेशान हैं। इसी प्रकार की स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों की भी है। एक तरफ पाकिस्तान की सीमा को सील कर दिया गया और कांटेदार बाढ़ लगा दी गई है लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा इतनी अधिक है कि उस दिशा में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं इसके लिये किसी सरकार विशेा को दोा नहीं देना चाहूंगा क्योंकि कोई कार्यवाही नहीं होने से घुसपैठ नहीं रुकी। देश की आजादी के बाद जितनी सरकारें रही हैं, जो कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता थी, उसका प्रयास सक्रियता से नहीं किया गया। इस कारण भी लोग परेशान होते जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि जो बंगलादेश से विदेशी घुसपैठिये आ रहे हैं, यह एक गंभीर समस्या है और इस दिशा में कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस सरकार के माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इस दिशा में सक्रिय और कारगर पहल करें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण नहीं है। हम नारा लगाते हैं -

"हम दो हमारे दो" परंतु इसका कहीं भी पालन नहीं होता है। समान नागरिक कानून बनाने की आवश्यकता है, लेकिन वह नहीं बनाया गया है। यह भी एक कारण है। हिंदुओं के लिए कानून बना दिया कि एक ही शादी करेगा। अच्छी बात है, हम उसे स्वीकार करते हैं। रूढ़िवादिता को त्यागना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। परंतु हमारे यहां एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि यहां के राजा-महाराजाओं तथा अनेक लोगों ने एक नहीं, अनेक शादिया की थीं। फिर दूसरे वर्ग के लिए दूसरी शादी करने की छूट क्यों है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह सेक्युलर देश है। लेकिन समान नागरिक कानून न होने के कारण हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को दैनंदिन खतरा पैदा होता जा रहा है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही पड़ौसी देश पाकिस्तान और बंगलादेश से हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने के लिए एक नहीं अनेकों प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। चाहे फिर वह आई.एस.आई. हो या सिमी की गतिविधियां हो। बंगलादेश में उनके अड्डे भी पाये

गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और माननीय मोहन सिंह जी ने सात दिसम्बर को एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के जवाब में माननीय गृह मंत्री, श्री शिवराज पाटील ने कहा है - बंगलादेश में भारत के विद्रोही ग्रुपों की गतिविधियों के शिविरों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि पाक आई.एस.आई. पूर्वोत्तर के उग्र वादियों को सामग्री और संचार तंत्र में सहायता प्रदान कर रही है। हमने प्रश्न में यह भी पूछा था कि वे लोग अगर यह कर रहे हैं तो सरकार उन्हें रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है। उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। फिर हमने यह पूछा था...

उपाध्यक्ष महोदय : गेहलोत जी, आप कंक्लूड करे।

श्री थावरचंद गेहलोत : आपने सदन का एक घंटा बढ़ाया है। उस हिसाब से हमारी पार्टी के बीस मिनट बढ़ते हैं और बीस मिनट बढ़ने के बाद हमारी पार्टी से मेरे अलावा एक माननीय सदस्य को और बोलना हैâ€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री पवन कुमार बंसल : आपकी पार्टी ने पहले ही कितना समय ले लिया है।â€¦ (व्यवधान)बहुत वक्त हो चुका है।

श्री थावरचंद गेहलोत : जब हमने यह पूछा तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब हमने उनसे उनके दौरे के ब्यौरे के बारे में पूछा तो उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी नहीं दी। आज पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से ज्यादा स्थिति खराब होती जा रही है। नगालैंड में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की कार्यवाही की गई।â€¦ (व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : आप इधर से बोल रहे हैं और मैं यहां बैठा हूं। आप कह रहे हैं कि आपने यह पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि यह आपने कब पूछा?

श्री थावरचंद गेहलोत : मैं आपको सात दिसम्बर के प्रश्नोत्तर का हवाला देकर बता रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील : अगर वह लिखित में हैं तो आप उसे पढ़कर बताइये।

श्री थावरचंद गेहलोत : मैंने पहले ही कहा था कि मैंने और मोहन सिंह जी ने सात दिसम्बर को प्रश्न किया था, यह उसके उत्तर का रेफरेंस है।

श्री शिवराज वि. पाटील : कोई प्रश्न जो लिखित रूप में पूछा जाता है, उसका जवाब लिखित रूप में दिया जाता है, मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है।

श्री थावरचंद गेहलोत : लिखित रूप में जो पूछा था, आपने नहीं बताया, वही मैं बता रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील : बताइये, उसका क्या जवाब दिया। यह सदन लोगों को मालूमात देने के लिए है, लोगों को बहकाने के लिए नहीं है।

श्री थावरचंद गेहलोत : यह बात सही है, लेकिन मैंने आपको पढ़कर सुनाया है।â€¦ (व्यवधान)**मैं आपको फिर से पढ़कर सुना देता हूं।**

श्री शिवराज वि. पाटील : इसका उत्तर क्या है।

श्री थावरचंद गेहलोत : केवल उत्तर ही पढ़कर सुनाऊ या प्रश्न भी पढ़कर सुनाऊं।

श्री शिवराज वि. पाटील : दोनों पढ़कर सुनाइये।

SHRI THAWAR CHAND GEHLOT : The reply given to (e) and (f) parts of the question is:

> "Reports have been received about activities and camps of Indian insurgent groups inside Bangladesh. Reports also indicate that the Pak, ISI is providing materials and logistic support to the North Eastern militants."

यह आपका जवाब है, प्रश्न का हिस्सा भी आप कहें तो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। प्रश्न यहां रखा है, मैं वह भी पढ़कर सुना देता हूं। मैंने उसे यहां रख दिया है, अब उसे निकालना पड़ेगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सैक्रेटरीज बात करते हैं, मिनिस्टर बात करते हैं, प्रधान मंत्री बात करते हैं, सार्क में बात करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका जवाब देने में।

श्री थावरचंद गेहलोत : यह कागज़ मैंने फाड़ दिया था, फिर पढ़कर सुना रहा हूँ। यह तारांकित प्रश्न संख्या 83, दिनांक 7.12.2004 का है। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। â€¦ (व्यवधान)मंत्री जी कह रहे हैं कि पढ़कर सुनाओ तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो कागज़ फाड़कर फेंक दिया था। मैंने उनको उत्तर सुना दिया था। अब वह कह रहे हैं कि प्रश्न बताओ तो मैं सुना रहा हूँ।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं, वह बहकाने वाली बात हो रही है।

श्री थावरचंद गेहलोत : बहकाने वाली बात नहीं है। जो प्रश्न मैंने पूछा, उसका उत्तर पढ़कर सुनाया है। उसके बाद आप कहें तो मैं प्रश्न पढ़कर सुना देता हूँ।

श्री शिवराज वि. पाटील : आपने कहा कि मैं पढ़कर सुनाऊंगा, तो मैंने कहा कि पढ़कर सुनाइए। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Without my permission, nothing should be recorded.

(Interruptions) *

श्री थावरचंद गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, आज मणिपुर में कुछ लोग स्कूलों में छात्रों को हिन्दी पढ़ने से रोक रहे हैं, एन.सी.सी. में जाने से रोक रहे हैं। उनको

आतंकवादी संगठनों और अंडरग्राउंड संगठनों द्वारा धौंस दी जा रही है कि अगर आप हिन्दी पढ़ेंगे, एनसीसी में भाग लेंगे तो मार दिये जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि वहां विकास कार्यों के लिए सरकार पैसा देती है पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। वहां के ठेकेदारों से, अधिकारियों को बोलकर चैक दिलवाए जाते हैं, चैक के बदले अंडरग्राउंड संस्थाओं के लिए 10-15 परसेंट धनराशि वसूल की जाती है और चैक बाउंस हो जाते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगाई, मणिपुर की सरकार से मांग की कि कार्रवाई करो, हाई कोर्ट ने ऐसे निर्देश दिये हैं। मैंने भी प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है। आपको भी मैं पत्र की कापी और अलग से पत्र भेज दूंगा और चाहूँगा कि आप भी कार्रवाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं इस समय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने जो बिन्दु उठाए हैं, आप अगर देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने का काम करें, समान नागरिक संहिता लागू करें, धारा 370 समाप्त करें, मल्टी परपज़ परिचय पत्र बनाकर बंग्लादेश से जो घुसपैठिये आ रहे हैं, उधर म्यांमार से आ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करें कि वहां तार की बाड़ लगे, घुसपैठिये नहीं घुसें और वे आकर देश की अर्थव्यवस्था को न बिगाड़ें और पूर्वोत्तर राज्यों में गड़बड़ न कर सकें। इस प्रकार का कानून बनाने का काम आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो माननीय कहते रहेंगे कि आपकी सरकार ने क्या किया और आप कहेंगे कि उन्होंने क्या किया। मैं कहना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद 50 सालों तक जिन लोगों ने राज किया है, उसमें अगर आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है तो सबसे ज्यादा दोषी अगर कोई है तो वे हैं। उसके बाद अगर आप किसी को गिनना चाहें तो उसके पहले जो सरकार थी, वह भी दोषी है परंतु पिछली सरकार ने यदि कोई गलती की है तो ज़रूरी नहीं है कि वही गलतियां आप भी करें। आपके पूर्व पार्टी ने कोई गलतियां कीं तो आप भी उन्हें दोहराएं, इसकी **आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि यह राजनैतिक समस्या भी है। राजनीति में वोट की खातिर इस प्रकार की संस्थाओं को जो बढ़ावा देने का काम पिछली सरकारों में हुआ है, वह नहीं होना चाहिए। â€¦** (व्यवधान)

* Not Recorded

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH (KANAKAPURA): Sir, we must also get some opportunity.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

श्री थावरचंद गेहलोत : एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। "सिमी " ने बंग्लादेश में एक कैम्प बना रखा है और उन्होंने भारत का एक नक्शा जारी किया है। भारत के नक्शे में एक मुसलमानिस्तान बनाया है जो शायद टीवी में आज तक या एनडीटीवी पर भी आया है। जम्मू कश्मीर से लेकर सीधे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और बंग्लादेश तक उन्होंने मुसलमानिस्तान का एक नया नाम दिया है -- यह "सिमी " का अभियान है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इसकी जांच-पड़ताल करें, सीमा पर प्रतिबंध लगाएँ, इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाएं और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रोक लगाएं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपकी इजाजत से इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, केवल कुछ सजैशन देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : रैपिटीशन न हो, तो अच्छा है।

चौधरी लाल सिंह : सर, रैपीटीशन नहीं होगा, जो मैं बोलूंगा उससे रैपुटेशन बनेगी।

सर, आप जानते हैं कि शरीर का अंदरूनी हिस्सा अगर अच्छा हो, तो बाहर का कुछ भी खाएं, सब पच जाता है, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर अंदरूनी हिस्सा ठीक नहीं है, बीमार है, तो बाहर का कुछ भी खाएं, पचेगा नहीं और तबियत खराब हो जाती है।

मैं सब्मीशन करूंगा कि हमारी कुछ पालिसीज हैं, उनके बारे में मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे उन पर ध्यान दें। एक तो सिक्योरिटी डिपलायमेंट करते हैं, उसका जो पैटर्न है, वह ऐसा है कि जम्मू-कश्मीर में एक ही स्थान पर बी.एस.एफ. भी तैनात है, सी.आर.पी.एफ. भी तैनात है, जे.के.पी. भी तैनात है और आर्मी भी लगी हुई है, लेकिन इन सब में कोई तालमेल नहीं है। यदि मुख्तलिफ एरिया बांट दिए जाएं और हर एरिया में एक ही फोर्स की जिम्मेदारी आयद कर दी जाए, एक फोर्स को उस एरिया के लिए रेस्पांसीबल बना दिया जाए, तो बेहतर रहेगा।

सर, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल डल लेक एरिया में सी.आर.पी.एफ. के लोग मारे गए, तो कहा गया कि वह एरिया तो बी.एस.एफ. के पास था। फिर लोअर मंडू में जब 30 आदमी बी.एस.एफ. के मारे गए, तो कहा गया कि वह एरिया तो सी.आर.पी.एफ. वालों के अंडर में था। इस प्रकार से जब वारदात हो जाती है, तो फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं। निश्चित एरिए में एक ही फोर्स की ड्यूटी लगाई जाए और उसी को उसकी जिम्मेदारी दी जाए, तब काम ठीक प्रकार से होगा।

सर, मैं बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट में एस.पी. होते हैं। उन्हें नोडल आफीसर बनाकर टोटल सिक्योरिटी उनके अधीन करनी चाहिए। हमारी पूरी रियासत में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऐसी बात नहीं है कि देश में बेईमान और लुटेरे ही हैं या बेईमान और लुटेरे अफसर ही बचे हैं। देश में बहुत ईमानदार और नेक इंसान भी हैं और ऐसे बहुत से अफसर भी हैं। मेरा कहना है कि पूरी रियासत में से ऐसे नेक और ईमानदारी 14 अफसर छांटिए और उनमें से हर एक को एक-एक डिस्ट्रिक्ट की फुल-फ्लैज्ड जिम्मेदारी दे दीजिए, उन्हें पूरी पावर दे दीजिए और कहिए कि यह आपका जाइंट वैंचर रहेगा, इसी पर आप काम करेंगे। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा।

सर, हमारे यहां एस.पी.ओज. और बी.डी.एस. आपने बनाए हैं। उनके लिए यहां से पैसे जाते हैं। आप 1500 रुपए एस.पी.ओ. को देते हैं। वहां चार-चार आदमी एक-एक एरिया में लगाते हैं। उन्हें मुश्किल से 400-400 रुपए मिलते हैं। 400 रुपए में न वे अपनी यूनीफार्म बनवा पाते हैं, न उनके पास ठीक प्रकार के हथियार होते हैं और न ही उनके पास कम्युनिकेशन के साधन होते हैं। जब वे मिलीटेंट को देखते हैं, तो आर्मी को बुलाने हेतु सूचना देने के लिए उनमें से 90 प्रतिशत लोगों के पास कोई साधन नहीं होते। सिर्फ 10 परसेंट लोग ही ऐसे होते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन के साधन होते हैं। मेरा कहना है कि इस तरफ खास ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार जब मिलीटेंट द्वारा कोई एस.पी.ओ. या बी.डी.एस. मारा जाता है, तो उनकी फेमिली को कुछ नहीं मिलता। उनकी फेमिली को एनकरेजमेंट मिलने की बजाय तबाह हो जाती है, बरबाद हो जाती है। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इनकी जो पे और स्टेटस है, वह भी नहीं के बराबर है। इसलिए उसे बढ़ाना चाहिए।

सर, जब प्रधान मंत्री वहां गए थे, उन्होंने एनाउंस किया था कि वहां पांच बटालियनें खड़ी की जाएंगी। मेरी गुजारिश होगी कि जो एस.पी.ओज. और बी.डी.एस. वहां 10-10 वर्ा से काम कर रहे हैं, वे 20 वर्ा की उम्र में लगे थे और अब उनकी उम्र 30 वर्ा हो गई है। जब नई बटालियनें खड़ी की जाएं, तो एक क्राइटीरिया बनाया जाए, जिसमें इन लोगों को प्रोटैक्शन दी जाए और इन्हें भी मुलाजिम के रूप में उन बटालियनों में लिया जाए। इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वे अच्छा काम करेंगे।

सर, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी प्रौटैक्शन मिली हुई है, जो सरकारी सुरक्षा में हैं। वे लोग प्रोवोक करने का काम करते हैं और रियासत तथा हिन्दुस्तान की तबाही और बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं करते हैं। उनकी सिक्योरिटी को विथड्रा करना चाहिए। इससे उनका दिमाग ठीक हो जाएगा।

आपके जो लोग नेशनलिस्ट हैं, देशभक्त हैं, उन्हें आप बचाइए। वे वहां मारे जा रहे हैं और उनका मरना देश के लिए सबसे घातक है, उन्हें स्ट्रेंथन करना सबसे जरूरी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पाक ड्यूल पालिसी है।â€¦ (व्यवधान)

महोदय, आप थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, लेकिन जम्मू-काश्मीर के साथ ज्यादती मत कीजिए। मेरे डोडा क्षेत्र में माडवा, बाड़वन, दशन, मोहर, गूल-अरनास, बनी आदि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जहां कम से कम एक हजार विदेशी आतंकवादी हैं। आप चेक करवा लीजिए। वहां 86 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, सारे रास्ते पैदल के हैं, इसलिए वहां कोई नहीं पहुंच सकता। वहां न आपकी सिक्योरिटी वाले पहुंच सकते हैं। वहां लोग टोटली कट-अफ हैं। अगर पाकिस्तान से बात हो रही है तो वे उन्हें वापस क्यों नहीं बुला रहा है, वे खामोश है। पाकिस्तान किसी भी समय कुछ भी करवा सकता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। वह चुप्पी क्यों साधे हुए है, उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाया गया? वहां जो हजारों मिलिटेंट्स के ग्रुप बैठे हुए हैं, उनकी तरफ आपको खास ध्यान देना होगा और जो एक प्लानिंग की जा रही है यह किसी धर्म का सवाल नहीं है, किसी एरिया को तबाह करना और इंटरनल सिक्योरिटी में बाधा डालना, मैं समझता हूं कि गलत है। मंदिर और मस्ज़िद बननी चाहिए।

महोदय, एक पालिसी तैयार हुई है। जैसे एक पालिसी बनती है कि सड़क के किनारे क्या करना है, आप चेक करेंगे। मुझे लगता है कि किसी दिन नेशनल हाई-वे भी ब्लाक होगा और कई जगह हादसे हो चुके हैं। You take care. इस पर बहुत सीरियस ध्यान देने की जरूरत है। जम्मू-काश्मीर रियासत के बारे में मैं अपनी पर्सनल राय देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि लद्दाख की अपनी पहचान है, जम्मू और काश्मीर की अपनी पहचान है। सब धर्म के लोग वहां रहते हैं, उनकी अपनी-अपनी आइडेंटिफिकेशन है। यहां काश्मीर वाले आटोनोमी मांगते हैं, जम्मू और लद्दाख ने कभी नहीं मांगी, कुछ चंद लोग आटोनोमी मांगते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उन्हें आटोनोमी दीजिए, काश्मीर को आटोनोमी देकर काश्मीर बना दें, लद्दाख को बना दें और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन हो जाएगा। आप जम्मू को एक स्टेट बना दीजिए, नहीं तो आपका आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ टूट जाएगा।

महोदय, आपके पास एक जे.के. अफेयर है और कोई कंक्रीट पालिसी नहीं बनती। आज किस से बात करनी है, पहले वाले कहते हैं कि उससे करनी है और अब वाले कहते हैं कि उससे करनी है, इससे नहीं करनी है, उससे करनी है। यह तय किया जाए कि किस से बात करनी है, कौन लोग हैं, किस के साथ बात करनी है। जम्मू-काश्मीर में यह होता है कि आर्मी वाले, सिक्योरिटी फोर्स वाले कहीं ठीक भी करते हैं तो ह्यूमन राइट्स वाले उनकी ऐसी की तैसी करते हैं और न्यूज़ पेपर्स में ऐसे ही छपता है। मैं समझता हूं कि उससे डिसक्रेजमेंट जा रही है। आपने जो सरंडर की पालिसी की है, उसे दोबारा रिव्यू किया जाए। आपको पता है कि नगरोटा में फेक लोगों ने सरंडर किया। उन्हें जब पेश किया तो वे हथियार लेकर आए। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पास हथियार कहां से आए? ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। â€¦ (व्यवधान)

महोदय, आप मेरे कस्टोडियन हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में मेरे ऊपर तीन अटेक हो चुके हैं। क्या आप सब लोग नहीं चाहते हैं कि मैं जिन्दा रहूं, मैं यहां आऊं और बात करूं? I am the representative of the people. मेरे ऊपर तीन अटेक हुए और डीएसपी उसमें मारा गया तथा छ: सिपाही भी मरे। मेरे आगे वाली गाड़ी उड़ी। मैं वहां जलसा कर रहा था, वहां चार आदमी मरे और तीन जख्मी हुए। वहां एक जगह बम ब्लास्ट किया, लेकिन वह फटा नहीं। मेरे ऊपर तीन अटेक हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, मेरा अपनी कांस्टीट्यूएंसी डोडा में जाना इतना मुश्किल हो गया है कि कहने की बात नहीं है। मैंने आपसे प्रार्थना की थी, उसके बाद मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, भगवान के सहारे जो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं।

I am representing a particular area, which is the largest constituency of India. हिन्दुस्तान की तीन कांस्टीट्वेंसीज बड़ी हैं, उनमें से एक कांस्टीट्वेंसी मेरी पड़ती है, कठुआ से लेकर टनल तक कितने रोज लोग देखे, मेरे चार लोग मरे हैं, परसों आपने खबर पढ़ी होगी। मेरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में चार पुलिस वाले मरे, जो पीसफुल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां मरे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट्स टोटली डिस्टर्ब्ड हैं, उनकी क्या हालत होगी, यह आप सोच सकते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाये कि किस तरह से आप चाहते हो। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो मुझे कोई ऑब्जैक्शन नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं लास्ट में कहूंगा कि एक बात का ध्यान रखें कि जो लोग गलत हैं, अगर उनके साथ सख्ती भी करनी पड़े तो आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। जो लोग ठीक हैं, उनको आप ठीक करिये। जो सुधरने वाले हैं, उनको सुधारिये, जो बिगड़े हुए हैं, उनको एक बार ठीक कर दीजिए, सारी मुश्किलें ठीक हो जाएंगी।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I endorse the views expressed by Hon. Members. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Ramadass, I request you to please be brief.

PROF. M. RAMADASS : Sir, this is my difficulty every day. My party is a small party in this House and at least here small is not beautiful!

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मेरे पास जितनी लम्बी लिस्ट है, उसके लिए कम से कम दो-ढाई घंटे का टाइम और बढ़ाना पड़ेगा।â€¦ (व्यवधान)

PROF. M. RAMADASS : I endorse the views expressed by hon. Members here that internal security is important. From my point of view, internal security is as important as, if not more important than, development itself. In the absence of internal security, planning for development would be like writing on the sea sands which are being constantly washed away by sea water. Therefore, internal security must be given utmost attention.

Hon. Members who have expressed their views have made two points. The first is that there has been a spate of internal security problems after the present Government has come into existence. The second is that this Government is treating this matter with a criminal callousness and indifference. I counter these two arguments because no statistics has been given to show that there has been a rise in the problem of internal security. At the

same time, I have statistics to prove that if we take the first six months of this year and the corresponding six months of last year, the number of atrocities and incidents of killings have been lesser during these six months. This is the inter-temporal picture.

When we take the country-wise experiences of security issues, our National Security Council Secretariat has worked out what is called, 'National Security Index' for 50 countries. Obviously, USA comes out with the first rank. China has come out with the second rank, India has come out with the eighth rank, and Pakistan ranks 49th among 50 countries. Therefore, when compared with other countries also, the security situation is not as alarming as it is made out by hon. Members here.

At the same time, I am not willing to say that the security situation is very comfortable. We must take care of it through a new approach. We need to have an approach of reconciliation wherever it is required.

To my mind, there are three components of internal security. One is the problem in the North-East; the second is the problem in Jammu and Kashmir; and the third is the Naxalite problem. In all these problems, the Government should adopt unconventional methods or new approaches to solve them. I feel that the Government should evolve a policy of neutrality wherever the problem comes. ...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास लिस्ट में 12 स्पीकर्स हैं।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : If it is agreeable to hon. Members, you can allow hon. Members to speak tomorrow also. ...(*Interruptions*)

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : बाकी चर्चा कल रख दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वे बोल रहे हैं, आप उनको सुन भी नहीं सकते। वे कुछ कह रहे हैं तो उनको कम से कम कुछ कहने दो।

श्री शिवराज वि. पाटील : आज जो लोग तैयार होकर आये हैं, उनको कल आने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज जितने लोग बोल सकते हैं, उतने बोलें तो ठीक है। उसके लिए आप टाइम बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : टाइम एक घंटा बढ़ा दें?

श्री शिवराज वि. पाटील : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आपको ब्रीफ होना पड़ेगा, वरना टाइम एक घंटा बढ़ाने के बावजूद भी लिस्ट खत्म नहीं होगी।

19.00 hrs.

PROF. M. RAMADASS : The Government should evolve a macro-level approach to this issue of internal security and it should be based on the principle of non-discriminatory treatment wherever the question comes. When the Government shows favouritism to some and some kind of discrimination to others, it spoils the

whole atmosphere in the country. Therefore, the Government should be non partison in the matter of internal security. I would feel that as a first step, the key positions in the security forces should be manned by competent persons and the Government should start the process of de-politicisation of appointments and promotions at the senior level in Armed Force as well as Central Police Organisations. The Government should insist that these leaders of competence must inculcate a new culture of integrity and professionalism among the Forces.

Thirdly, the internal security should be left to the care of the Central Forces and the Army should not be deployed to tackle the situation of internal security. The Army Chiefs and other people whom you are appointing should take the accountability part of it and they should try to see that there is an end to smuggling of weapons, narcoties and other instruments for the terrorist groups.

With regard to the North-East, I would feel that the Government should form a group to review the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 which has become the bone of contention. This Act has been in existence for a long time. It has not worked well. Therefore, the Government will have to think anew and constitute an all-Party committee to review this Act. If it is needed, some of the provisions, which have been misused, can be dropped and even a new law can be brought in place of this Act. We will have to send a new signal and a message to the terrorists in that area by doing so. ...(*Interruptions*)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: This is a good suggestion. We have already acted on that. A committee has been constituted and a Supreme Court judge has been made the Chairman of it. There are four other members who are looking into this. ...(*Interruptions*)

PROF. M. RAMADASS : Sir, this Act has to be repealed as the case of POTA. Some of the provisions, which have been misused, must be deleted. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. M. Ramadass, please conclude.

...(*Interruptions*)

PROF. M. RAMADASS : Now, I come to the next problem. In the case of Jammu and Kashmir, we have tried several experiments. We have seen a large number of retired Army Generals and everybody there. It has not worked. I would feel that it is the Muslim sentiments in Jammu and Kashmir that must be respected. Therefore, I would feel that the Government should send an open invitation to the Indian Muslim leadership to take all immediate and possible measures to bring about a sense of conciliation among the Muslims there, which alone can provide a durable solution to the problem of Jammu and Kashmir.

As far as the problem of naxalites is concerned, the Government should try the experiment of Andhra Pradesh and try to open up the process of dialogue with them and try to ease their problems.

The Government should recognise the linkage between bad politics and bad security and politics, and politicians should not provide a helping hand to those who are indulging in those acts of insecurity.

Finally, the Government should work out a comprehensive package of social and economic measures which are the ultimate goal for achieving social justice in this country. Unless economic development and social justice is ensured, the problem of security would be at stake.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): The internal security of our country has deteriorated not only during the UPA Government's regime but since successive Governments, whatever they may be. So, the terrorists, even the Maoists Group of Naxalites, fundamentalism and Left extremism are all posing threats to our internal security.

We call India, that is *Bharat*, a Union of States. The law and order problem is the State subject. Different political parties are ruling different States. On the question of internal security if the Government of India decides to take any policy decision, then they have to consult the political parties and take them into confidence. When the NDA Government was in power, at the time of Kargil war, repeated meetings with all the political parties took place and there were exchanges of views and inputs and everything. Security is not the Government's duty alone; but internal security is for everybody, for all the political parties. We are all united on this aspect. The whole country is united. The people of this country are also united for the sovereignty of our nation and for its internal security. There is no dispute about it.

Whichever Party is in the Government, they have to take all the political parties into confidence. In Andhra Pradesh, the Government has started discussions with the naxalites. My Party is not against the discussions. How will this Union Government tackle the situation? You are leaving it to the States and the States have already started discussions with the naxalites. But that is not the problem of Andhra Pradesh alone. That is the problem of many other States also. Normally each State has its own perception. The other States also have this problem. They have not started discussion with the naxalites. That is why the Government of India should take a comprehensive view on combating this naxalism. Otherwise, it will not be controlled. If in one State dialogue is started and it is controlled, then how can we control it in other States? A comprehensive policy is required in our country to combat this Maoist naxalism in our country.

Since two decades, according to our experience, 64,000 civilians have been killed by the terrorists. Infiltrations are going on continuously. You take even the two neighbouring countries − Pakistan and Bangladesh. The ISI camps are established recently. The Government's information is there and the intelligence information is also there that the infiltration from Bangladesh is going on and lakhs of people are coming. That is why, since Independence, all the political parties have been demanding on one thing and every Government has been assuring it on the floor of the House. It is about multi-purpose identity card. Some States have their own identity cards. They are spending lot of money. Instead of wasting money on identity cards for particular purpose, a comprehensive all-purpose identity card will serve a lot of purpose to tackle this internal security situation.

We have to think in terms of social and economic lines. You have announced one special package for Jammu and Kashmir. You have to announce some similar packages for the undeveloped areas in Andhra Pradesh in Telengana, in Rayalaseema and in States like Chhattisgarh and other parts where you have to announce a comprehensive package for unemployed youth, for building roads, for providing the basic minimum amenities. You have to provide it; otherwise, how can we tackle that problem and how can we separate the issues? This is not a law and order problem. We have to think in terms of socio-economic lines. We have to give special packages for all these areas, to those areas which have got a threat from these outfits, be it terrorists or whatever it may be. We have to think of it.

Sir, you take the law and order situation in Andhra Pradesh. Seven months after the Congress Government came into power, 37 TDP workers were brutally killed by the Congress Party. We have given a representation to the hon. Prime Minister when he visited Andhra Pradesh. We have given a representation to the Rashtrapatiji and to the National Human Rights Commission also. Then the National Human Rights Commission asked about the details of investigation and everything and then, to some extent, the murders were stopped. The partisan attitude should not be there.

Law and order is the State subject; but the Government here should keep an eye, keep a watch. It is the duty of the State to protect the life and property of the citizens. It is a constitutional duty. It is the fundamental right of the citizens. Suppose, the State failed to protect the life and property of a citizen and we are keeping silent, the Constitution is keeping silent, what will happen? The Government of India should act very firmly to control all these types of murders, dacoity, kidnapping and all these things.

We have to think of new and innovative ideas to combat this new type of issues and have new approaches. They are also thinking in a new direction. We have also to think in a new direction to combat all these outfits.

DR. H.T. SANGLIANA (BANGALORE NORTH): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful that I have got this opportunity to speak on the national security matter. Having been in the Police service for 36 long years, I have been observing the happenings in the country all these years. I do have certain suggestions which I request the Ministry of Home Affairs to take into consideration.

While talking about national security, basically we know that the security of the nation depends on the quality of intelligence reports that we are able to gather. In this aspect, I have been observing that in the North Block, people, who are considered to be North-East experts and who have been handling the Government related issues regarding the activities in North-East etc., are just the people who could get into such positions because of close contacts. Also, at the State level, there has been inadequacy of the reliability of the intelligence personnel. Therefore, my suggestion is that there should be frequent change of intelligence network personnel, both at the Centre and in the States.

I was in Manipur about two weeks ago. I checked up with the locals there - from the local journalists and also those who I knew were involved in unlawful activities in the past - what was happening there and it was the confirmation of what I had expected that the people who are supposed to be really in the know of the happenings at the grassroot level, are not used, are not contacted as they should be. Therefore, my suggestion is to frequently review the security network functioning so that all intelligence reports that we get are actionable.

I happened to be in charge of the Special Task Force constituted to nab Veerappan for about three months. Our failure there was, again, because of absence of actionable intelligence. I wrote a six-page letter to the Government suggesting that under-cover policemen should roam about in the jungles and after six to seven months, it should be possible to get real and actionable intelligence. Ultimately, similar thing was done and we got Veerappan.

The second point I would like to emphasise is that in Mizoram, we had very strong public opinion against insurgency. It resulted in the MNF coming over-ground and now MNF is ruling there. But in other States in the North-East, like Manipur and Nagaland, we have not been able to organise public opinion strong enough to go against the activities of the undergrounds. Therefore, what is important is to try to form public opinion, which can be done by way of broadcast through radio stations. Even if people are not in a position to speak through television or radio stations for fear of consequences, and if we drop pamphlets conveying popular public opinion against insurgency it will have a psychological impact on the minds of the undergrounds as well as the overgrounds so that a day will come when both the undergrounds and the overgrounds will agree to come to the negotiating table.

The next suggestion I would like to give is that for intelligence collection, we have to hire retired officials from the police and from the CPOs, who have been there in the North-East and even in other places. I do not know how many such retired officials are participating in the collection of intelligence in all these trouble-affected areas. This has to be verified.

Another point is that many of our police officers are careerists, and not professionals. Careerists always spoil the functioning of the police department. POTA was really a very welcome step, and I was one of the happiest police officers when it was introduced, but it was misused because of the weakness of the police leadership. They were prepared to bend against the provisions of the law. Unless the police leadership is tuned to honesty, integrity, and real solid dependability I am sure , the successor of POTA will also face the same fate or failure and again something will have to be done about it.

Fundamentalism is suspected to be in the three main religions of India, namely, Hinduism, Islamism, and Christianity. There has to be frequent dialogue amongst them. I would suggest for creation of religious harmony wing in one of the Ministries, so that the activities or complaints of people alleging indulgence in illegal activities in any one of these groups. Such a Ministry or such a wing can coordinate with the States, and every nation threatening incident, small or big, can be effectively and quickly handled for maintaining security in the country.

Now, I will come to North-East. I have been born and brought up in the North-East, and I have been watching very closely the developments over there. We still have a lot of irritants, mostly economic and social irritants. Firstly, even the connectivity by air is very poor, and our people are compelled to buy air-tickets in black. Students, who want to avail the students' concession, are not allowed to avail it because the payments made by them is less than the full passenger fare.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Sangliana, please conclude.

DR. H.T. SANGLIANA : Therefore, these kinds of irritants have to be removed. Cash crops, which are quality crops, are sold at very low prices. I would like to cite an example. A kilogram of ginger is sold at Rs. 8, which will fetch Rs. 80 in Delhi. Therefore, these kinds of irritants have to be removed. These irritants are threat to national security and they should be removed.

Another problem is poor road connectivity in the North-East. As a result of absence of roads along the borders crops grown in the border areas like Myanmar border, etc. ...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : काफी समय हो गया है, अब खत्म करें।

श्री थावरचंद गेहलोत : बोलने दीजिए, मेडन स्पीच है।

DR. H.T. SANGLIANA : Sir, this is my maiden speech, and this is an important matter. ...(*Interruptions*) Sir, kindly allow me to speak a little more. ...(*Interruptions*) Opening up of the rural areas by having motorable roads, at least, jeepable roads, will certainly open up the rural areas so that people in those areas will have a feeling of integration with the mainland. Another point is with regard to the â€¦ (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, this will be your last point.

DR. H.T. SANGLIANA : Yes, I am coming to my last point. The success of the Special Armed Forces Act, which we are talking about so much nowadays, will actually depend on whether it is properly used or not properly used.

According to me, nothing is wrong in this, as nothing was wrong in POTA, if our officers and men use it properly and judiciously, which they do not do. Many times, we have seen allegations made against the Army the CPO personnel, but a blanket denial will always be there. These things irritated the people of the North-East, who have suffered a great deal in the hands of the brutal ones. Therefore, this aspect has also to be looked into for improving the overall security position of the country.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Sir, as you know, internal security is a vital component of national security because internal security cannot be separated from external security. On this day, in the year 2001, the country was exposed to terrorist acts when the terrorists committed a gruesome act in front of the august House of India. It also exposed the vulnerability of our security system. A wide-ranging discussion had already been held on the issue of internal security.

Since Independence, our country has been suffering from the syndrome of insurgency, terrorism, secessionism, a sort of religious fundamentalism, and a State-sponsored terrorism has been perpetrated from across the border. They must be thinking of how to retaliate their defeat in the Bangladesh War. Under the rubric of "Operation Gibralter" and "Operation Topac", ISI activities have been growing in India affecting Jammu and Kashmir and the North-East.

It is true that India is multi-cultural, multi-lingual and a multi-ethnic society. Therefore, the problem is not homogenous one, rather it is a heterogeneous one. That is why, our approach in regard to insurgency must be multi-model because economic deprivation alone has not caused insurgency. Various ethnic groups, who are out to assert their identity, sometimes, have taken up arms. Therefore, these divisive tendencies must be taken cognizance of before we formulate any comprehensive security plan in India.

We have already negotiated with our neighbouring country, Burma, to flush out insurgents. Our hon. Prime Minister had already offered an economic package to Jammu and Kashmir. Our hon. Home Minister has already expressed his desire to have a dialogue with the Hurriyat Conference. Naturally, the UPA Government is very much consistent in its approach, which may create a congenial atmosphere and help defusing the long-standing problems that we have been facing over the years.

Sir, our neighbouring country Bangladesh has become a hub of anti-Indian activities at present. We should all be aware of the fact that a hostile neighbour like Bangladesh must be stopped from harbouring domestic rebels and offering sanctuary to Indian insurgents. Already Bangladesh has been raring up its uncouth face in the name of obscurantism. In the name of religious fundamentalism, the anti-Indian forces are being assembled there. They are out to destroy India.

India-Bangladesh border is totally porous. There is a language barrier between the security personnel deployed at the border and the local people because the people there look the same, their language is the same, their dresses

are the same. Therefore, the Government should deploy there such personnel who are accustomed to the local language, local customs and the local culture. Otherwise, various complexities will continue to arise at India-Bangladesh border.

So far as multi-purpose photo identity cards are concerned, I would like to ask the hon. Home Minister as to what was the actual performance of the pilot project that had been initiated earlier in this regard. I come from district Murshidabad where two blocks, namely Murshidabad and Jiaganj, have been identified for issuing multi-purpose photo identity cards. But, from what I have observed, that process is going very slow. I request the hon. Home Minister to expedite that process so that people can derive the benefits of these multi-purpose photo identity cards.

West Bengal has again started witnessing the Left extremism nowadays. It has already taken toll of a number of police personnel and CRPF *jawans*. A few minutes earlier, my colleague Shri Chakraborty was exhorting that land reforms should be implemented. West Bengal was the pioneer of land reforms in India. Likewise, land distribution was also started in West Bengal in the years 1971 to 1975 during the Congress regime. But, land reform is not the panacea for the problem of Left extremism in West Bengal. If that had been the case, incidents like Belpahari, Salbani, Bandawan and Kokrajhar would not have taken place.

In view of the alarming situation obtaining in various States, I would suggest that our intelligence networks should be reviewed. If necessary, the Government may ponder over the idea of creating a federal police structure without compromising the sovereignty and freedom of individual States. I say this because the networks of insurgency have developed into an intricate cobweb.

We are living on a landmass which is surrounded by the Golden Crescent and the Golden Triangle where drug trafficking and money laundering is the source of arms for the anti-social elements. We are simply giving sustenance to the insurgents in India. Therefore, our approach must also include reconciliation. It is much safer to reconcile with the enemy than to conquer him. That is because defeating him will deprive him of his poison only while reconciliation will deprive him of his will.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

On the issue of internal security, I agree with my colleague Shri Ajoy Chakraborty who spoke about several aspects. I do not want to repeat all those issues.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please try to give suggestions only.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY : I request you, Mr. Chairman, Sir, to give me a few minutes to put only a few points.

Firstly, what I feel is that besides the cross-border-supported terrorism, underemployment, untouchability, and utter poverty are also the reasons for a section of our youth to take to terrorism. While we are taking the measures to defend our country from the extremists and to suppress all sorts of anti-national activities, we should also look at the issues from both the angles - one is the law and order problem and the other is the socio-economic problem. If we solve these problems, extremists" recruitment will stop. In some places, mishandling is also creating problems.

Some of the Members have explained particularly about the Manipur problem. There is a very serious demand that the Armed Forces (Special Powers) Act should be repealed. There is a feeling that the Army will get demoralised with this type of Act. What about the demoralisation of the people of the entire Manipur? I request the hon. Home Minister to look at it from that angle.

At this juncture, I would like to also request the Minister to study as to what are the types of methods that are being adopted in many democratic countries. If any civilian crime is committed by the military people, are they also being tried in military courts? I do no think this is being adopted in democratic countries. This is very colonial in nature. We respect the Armed Forces. We can give them necessary facilities. As far as the Army is concerned, they should have some special advantages. But that does not mean that they should be tried in separate courts when they commit civil crimes. They should be treated on par with the common people. Along with the Special Powers Act in Manipur and other places, attempt should be made to win over the people. People should be taken into confidence.

Regarding the naxalite issue, even when the Telugu Desam Party was in power, there was an attempt to start discussions with naxalites. We all feel that it is not only a law and order problem but also a socio-economic problem. Our Union Home Minister, Shri Shivraj Patil has taken an initiative that wherever there is a possibility for such a discussion, they can make an attempt. In the last three years, almost 435 extremists were killed, 5,075 naxalite and extremists were arrested, and around 2,500 surrendered but still the problem of naxalites could not be solved. Hence, where a true discussion is possible, an attempt should be made. The TDP leader, Shri Yerrannaidu has proposed that a comprehensive package should be taken to the backward areas. In Andhra Pradesh, we, the Communists and Left parties, had proposed such a package. Unfortunately, when his party was in power, it was rejected, which has created all the problems in the backward areas.

Here, I would like to say that the so-called murders between the Congress and TDP parties are really called factional murders. When the TDP party was in power also, this type of murders had taken place. We were appealing to both the Congress and the TDP parties not to allow factionalism in their respective parties. These parties encourage factionalism for their political advantages. Unfortunately, these murders are continuing.

Lastly, I would like to say that the internal security also includes creating confidence in minorities and other people. The anti-Sikh riots in Delhi and anti-Muslim riots in Gujarat have put our country to shame. The real culprits should be punished and the people, particularly the minorities, should get confidence that in this country they can get justice and real culprits will be punished. All the suggestions mentioned above put together can solve the problem. If you treat it only as a law and order problem, this problem cannot be solved.

SHRI MANI CHARENAMEI (OUTER MANIPUR): Sir, I would like to congratulate our hon. Prime Minister and the Home Minister for the initiative taken for bringing peace in Jammu and Kashmir and for taking steps to talk with naxalites and particularly for pursuing the peace process in Nagaland for the Naga people. I belong to the State of Manipur and I am a Naga. We have been hoping for peace for the last fifty to sixty years. The Naga problem has caused enough internal security problem in our country. It has incurred terrible loss to the nation in terms of lives, property and wealth. We are hopeful that during this peaceful negotiation, our internal security could be improved and we will be able to see the light of development in our area. Moreover, We will be able to have confidence in building the country and in strengthening the nation.

There may be a lot of objections. But we are seeking justice from India and not from any State. So, we are hopeful that you will do justice to the Naga People area so that internal security in this region could improve.

DR. BABU RAO MEDIYAM (BHADRACHALAM): Sir, I would like to participate in this discussion. There are two potential areas or factors that are threatening our internal security. One is the communal menace and the second one is naxalite violence. I want to say something about naxalite violence. They claim that they are for the people. They talk about how they came into existence and what their aims are. They claim that they are fighting for the people and they are Marxists and Leftists. But the fact is that they are neither Marxists nor Leftists, they are anarchists. So, anarchism is naxalism. I would like to say that they are disturbing the developmental process. They blasted telecommunication facility. They are obstructing and opposing the road networks, which are being sanctioned. They are anti-tribals and anti-developmental. That is why, I want to suggest to the hon. Home Minister that we must create awareness among the people about how this naxalism is anti-people and anti-developmental.

The second thing is about the surrender. This surrender and rehabilitation policy is to be implemented effectively.

The third thing is, we must equip our forces. We must make them aware because people feel that, on one side, during night time, naxalites threaten the people, and during day time, the police threaten the people. I request the Home Department to take into consideration the people's voice and we must enlighten the people against the menace of naxalism.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों को आज एक ही चिंता है कि समय-समय पर सरकारें बदल रही हैं, लेकिन आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मैं उन घटनाओं की ओर नहीं जाना चाहूंगा, जिनका उल्लेख मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों द्वारा किया जा चुका है कि कितने लोग मारे गये, कितने उग्रवादी मारे गये आदि के बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन जहां तक आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त करने की एक योजना सरकार ने बनाई है, उस पर भी खटाई का बट्टा लग गया है। केन्द्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों की उपेक्षा की वजह से समय-समय पर आंतरिक सुरक्षा को खतरा बढ़ा है। जब कि केन्द्र और राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने एक हजार करोड़ रुपया दिया है। इसमें से आधा केन्द्र सरकार को वहन करना है और आधा राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन दो-तीन सालों में देखा गया है कि केवल 79.81 परसेन्ट पैसा खर्च हुआ है। वर्ा 2001-2002 में 43.81 परसेन्ट पैसा खर्च हुआ। यह पैसा बेहतर हथियार, बेहतर संचार उपकरण, अच्छे वाहन तथा कंप्यूटर आदि के लिए दिया गया है।

अभी भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश गए थे। उन्होंने वहां की कानून-व्यवस्था के बारे में चिन्ता व्यक्त की। मैं कहना चाहूँगा कि अगर मान लें कि राज्य में कोई भी दिक्कत आती है तो माननीय गृह राज्य मंत्री जी को मुख्य मंत्री जी के साथ वार्ता करनी चाहिए, न कि अधिकारियों को बुलाकर सीधे हस्तक्षेप करके निर्देश देना चाहिए।

हम लोगों की मांग थी कि अगर 18 हजार करोड़ रुपये का पैकेज उत्तर प्रदेश को दे दिया जाता तो उत्तर प्रदेश का समग्र विकास होता, लेकिन इधर एक वर्ा के अंदर सरकार ने हमारे अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा की जिससे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उनमें जागरूकता आई है। आज समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। लोगों को नैतिक रूप से सशक्त करने की ज़रूरत है। मैं इस देश के प्रबुद्ध और समृद्ध लोगों से कहना चाहूंगा कि गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों की तकलीफों में अपनी भागीदारी निभाएं। साथ ही पुलिस और सशस्त्र बलों पर भी इनका खासा असर पड़ा है। जहां तक पुलिसकर्मियों की बात है, आज सुनने में आया है कि पुलिसकर्मी भी अपराधियों के साथ मिलीभगत हैं जबकि एक घटना राज्य में ऐसी हुई कि एक महिला के साथ रेलवे सुरक्षा बल के लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। इसलिए आज आंतरिक सुरक्षा का मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है। आंतरिक सुरक्षा देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना होगा ताकि हम अपने कर्तव्य को समझें और उसका निर्वाह कर सकें।

दूसरी मुख्य बात यह है कि देश में दबे-कुचले लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। गरीबी निवारण का जो कार्यक्रम होता है, उसमें भ्रटाचार होता है। जब शिक्षित नौज वानों में बेरोज़गारी आती है तो वे हथियार उठाते हैं। आज देश के युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आंतरिक तौर पर उनके जज्बातों को उभाड़ा जा रहा है और इससे बेरोज़गारी की समस्या से पीड़ित नौजवानों ने हथियार उठाये हैं।

अभी शून्यकाल में मैंने माननीय गृह मंत्री जी का और सदन का ध्यान आकृट किया था कि तमाम जगहों पर मिसाइलें बरामद हो रही हैं। यह एक तरीके से देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठाता है। इसका भी कायदे से मूल्यांकन होना चाहिए, इसको भी रोकना चाहिए कि जो सेना के पास ग्रेनेड और मिसाइलें हैं, वे तमाम सार्वजनिक स्थलों पर कैसे मिल रही हैं। दूसरी तरफ जहां स्क्रैप के गोदाम हैं, वहां पर विस्फोट हुए हैं और दर्जनों लोगों की जानें गई हैं।

ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा और कहना चाहूँगा कि आज दिलों में जो असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, उसका कारण आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक समस्याएँ हैं। उन पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the situation on the front of the internal security has improved considerably after the present UPA Government has come to power. The sense of security among minorities has improved.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Owaisi, please conclude your speech within two to three minutes.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, make it five minutes, please.â€¦ (*Interruptions*)

The sense of security among minorities has increased. The atmosphere of oppression and suppression, by a vindictive official machinery led by the communally biased Government, has been removed to a large extent.

Due to paucity of time, I would be very, very brief. One very important point that I would like to bring to the notice of the Government is that yesterday in Rajasthan, still *Bajrang Dal* activities were distributing *Trishuls*. Though it is a State subject, but if these fascist and communal forces are not stopped, communal tension would increase.â€¦ (*Interruptions*) As far as I know, Rajasthan is becoming another laboratory for the fascist forces like Gujarat...(*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, it is not fair. He has used the word 'fascist' for *Bajrang Dal.* It is unparliamentary. It should be expunged from the records...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see.

...(*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : This is a Member's opinion. One hon. Member is speaking from the other side. ...(*Interruptions*) There is nothing to be expunged....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Swain, it is not unparliamentary.

...(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, my request to the hon. Home Minister is that such forces need to be stopped. It is the need of the hour.

It is a known fact that these communal and fascist forces are imparting training. If tomorrow, some emotional Muslims start distributing swords, how would they react to it?

They will immediately say that these people are ISI agents and that they are hell-bent on destroying the communal amity. Moreover, there is a need to discuss how it is that the RSS is imparting physical training though it is doing this for a long time. I am surprised that strange alibis are given. If RSS *Shakhas,* imparting training, are in the interest of nation and the country, then I will give a serious proposal. Let all these *Shakhas* be established by the Government of India and all the youths under 25 years of age should be made compulsorily to go to these *Shakhas.* Military training should be made compulsory so that this fear among a particular minority that this training is being imparted only to hurt them − it has been proven in Gujarat − is dispelled.

Secondly, I would like to speak about the *Madrasa.* For six years the NDA Government was in power. How many *Madrasas* have been closed! You name one *Madrasa* which is imparting anti-India training over there. In fact, these *Madrasas* are doing a good job by making these poor people literate, though in Urdu. They are imparting education. In six years of governance of NDA Government, how many *Madrasas* have been closed? History tells us that during freedom struggle, *Fatwa* on *Jehad,* was issued by these *Madrasas.*

*Not Recorded.

I would like to bring to the notice of my hon. friends − I cannot enlighten them but I can only tell − who was Allama Fazalhaq Khairbadi. These same *Madrasas* had issued a *Fatwa* on *Jehad* against the Britishers. Who was Ashfaq Ullah Khan Shaheed? When asked, in his last speech he told, 'bring soil from my village and put it in my grave'.

I would request that this blatant generalisation of the whole Muslim community that they are anti-nation - this Muslim bashing - should stop. A Muslim is not a whipping boy. We cannot become a cannon for your fodder. The biggest conspiracy of these fascists and communal forces is to create a fear of minority among the majority community. The Muslims of India hate ISI. At the same time, they hate *Sangh Parivar* forces also. So, there need to be a distinction over here.

Regarding this naxal problem, in our opinion, it is a socio-economic problem. It has to be dealt with talks only. From May end right up to now, there has been a ceasefire in Andhra Pradesh. Not a single death has taken place due to this problem. Otherwise, every month 30 to 40 deaths used to occur due to naxal problem. We could stop 200 deaths in a year. In nine years of Telugu Desam rule, 3000 people were killed on both sides. My request is that talks should continue. The Central Government should give as much support as they can to the State Government so that these talks are fruitful. We have to debate and talk to them. Faiz Ahmad Faiz has said a very important *sher:*

इतने नादां तो न थे जहां से गुजरने वाले

नासुरो तुम गुजरो, राहगुजर को देखो।

यहां इस चीज को देखना है कि क्या गलती हो रही है। गोली का जवाब गोली से देने या उनको मारने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। बल्कि जिस चीज से मसला हल हो सकता है, उसे करने की जरूरत है।

सर, मैं मदरसे के ताल्लुक से चेलेंज के साथ कह सकता हूं कि बी.जे.पी. के कोई भी लोग हिन्दुस्तान के किसी भी मदरसे में जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है और हमें बताएं, आप भी देखें। मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहूंगा कि मोहतरमा इंदिरा गांधी जी के जमाने में 15 पाइंट प्रोग्राम का ऐलान किया गया था, यह बात सच है कि मुसलमानों में, नौजवानों में, खासतौर से बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे-अच्छे आफीसर्स को मुकर्रर किया जाए। â€¦ (व्यवधान)

सर, मैं सिर्फ एक मिनट में खत्म करूंगा। आखिर में, मैं नक्सलाइट्स के बारे बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि करीम नगर जिले में ऐसी कई जमीनें हैं, जहां लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। नक्सलाइट्स के मसले को बातचीत से हल किया जा सकता है।

मदरसे के ताल्लुक से, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, यह बात ठीक नहीं है। यदि ऐसा है, तो मुसलमानों की आबादी साउथ में कैसे कम हो गई। अगर बार्डर एरियाज में आबादी बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है, यह आपको मालूम होना चाहिए। पांच साल तक आपकी हुकूमत रही, आपने कितने बी.एस.एफ. के लोगों को सस्पेंड किया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, आपकी मौजूदगी में जो हुआ, वह आपको मालूम है। यानी जब हम हुकूमत में थे, तो नक्सललाइट्स थे और अब जब हमारी हुकूमत आ गई तो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। आपको इन्हीं चीजों की वजह से बैठना पड़ा। वहां आपको मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिए, लेकिन हिन्दुओं ने भी आपको वोट नहीं दिए। इसीलिए वहां आपको बैठना पड़ा।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश के आन्तरिक आन्तरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा हो रही है।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नंबर तो पहले था, लेकिन आप बाहर चले गए थे।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, सुरक्षा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है।

â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी दो-दो, तीन-तीन मिनट बोले हैं। आप भी इससे ज्यादा समय न लें।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, यह विाय बहुत गम्भीर है। देश की सुरक्षा के बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए और चाहे अपोजीशन हो या सत्ताधारी पार्टी हो, सबको इस विाय पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। इसमें राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है।

सब को इस विाय पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा, इसमें कोई राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। यह जो जम्मू-काश्मीर का इश्यु है, इसके लिए आपकी सरकार ने भी प्रयत्न किया था, जब श्री अटल जी बस से वहां गए थे तो वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया था और हमने भी आपका स्वागत किया था। हमारे प्रधानमंत्री जो और गृह मंत्री जी भी जम्मू-काश्मीर जाकर आए हैं और वहां उन्होंने 24 हजार का पैकेज एनाउंस कर दिया है। जम्मू-काश्मीर में जो टेरेरिस्ट हैं, वे टेरेरिस्ट क्यों बने हैं, इस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। वहां के लोगों की भावना पर भी विचार करके, उन्हें थोड़ा कंविंस करने के संबंध में भी हमें विचार करना चाहिए।

महोदय, अब हमारी सरकार आई है, हमें जम्मू-काश्मीर के लोगों को समझाने में यश मिलने वाला है। वहां के टेरेरिज़्म को खत्म करने में हमारी सरकार को सफलता मिलने वाली है। अगर हम 2001 से लेकर 2004 तक के आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि कम से कम 17071 इंसीडेंट हुए और उसमें अभी तक कम से कम 13,210 लोगों की मौते हुई हैं। चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस या सिविलियन के लोग हों, चार सालों में इतने लोगों की मौते होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारा कहना इतना ही है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, अभी हमारी सरकार को आए हुए सिर्फ साढ़े सात महीने ही हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय पाटील जी एक बहुत ही नेक इंसान हैं और उन्हें बहुत अनुभव है, मंत्री पद का भी अनुभव है, इसलिए वे होम डिपार्टमेंट को बहुत शक्तिशाली रूप से बहुत अच्छा निभाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। यहां जाति और धर्म के नाम पर भी संर्घा होता है। कई लोग बेरोजगारी के माध्यम से टेरेरिस्ट बनते हैं। नार्थ-ईस्ट में भी टेरेरिज़्म बढ़ता जा रहा है, नक्सलाइट का भी टेरेरिज़्म बढ़ता जा रहा है। यह अच्छी बात है कि कुछ लोग अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आंध्र प्रदेश की सरकार बात कर रही है। अभी महाराट्र में भी असेम्बली चल रही है। महाराट्र की सरकार ने भी नक्सलाइट लोगों के साथ बातचीत करने के बारे में निर्णय ले लिया है। अगर उनमें कोई परिवर्तन होता है, उनकी इकोनोमिकल मांगें हैं कि जमीन उन्हें मिलनी चाहिए। अगर गरीबों के लिए नक्सलाइट लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि उन्हें सरकार जो कुछ दे सकती है, वह देने का प्रयत्न करेगी। आतंकवाद से कोई भला नहीं होने वाला है, युद्ध से भला नहीं होगा। यहां शांति की आवश्यकता है, चाहे जितने भी लोगों को मारने का प्रयत्न कराएं, उससे कोई हल निकलेगा, बातचीत से जरूर कोई न कोई रास्ता निकल सकता है। चाहे जम्मू-काश्मीर का इश्यु हो या जाति और धर्म के नाम पर चल रहा संर्घा हो, उसे भी खत्म करने की आवश्यकता है। अगर बाबासाहेब अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को सामने रख कर भारत को मजबूत करना चाहते हैं तो शांति के बिना कोई भला नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को आतंकवाद को खत्म करना चाहिए।

मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आपको भी सरकार को सहयोग देने की आवश्यकता है। हमने सिक्योरिटी में कभी राजनीति नहीं लाई, हम आपको पूरा सहयोग देते थे। यहां आपके केवल दो माननीय सदस्य मौजूद हैं। मैं भारत के गृह मंत्री, श्री शिवराज जी पाटील से इतना ही कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को खत्म करना है तुम्हे आज, उन शहीदों पर हमें है नाज़, बुलंद करो अब अपनी आवाज, उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम सब लोगों को काम करना है और आतंकवाद से हम नहीं डरेंगे, हम खत्म करेंगे, इस मिशन में हम नहीं हरेंगे और लोग यहां अब नहीं मरेंगे, इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहने वाली है।â€¦ (व्यवधान)

महोदय, अयोध्या का जो मसला है, इस मसले में भी काफी आतंकवाद हुआ है। गुजरात में भी श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार है।â€¦ (व्यवधान)

इस सरकार को रिजाइन देना चाहिए। स्मृति ईरानी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की ऑल इंडिया कमेटी की मैम्बर हैं, उन्होंने अपील की है कि नरेन्द्र मोदी जी को रिजाइन देना चाहिए। मैं नरेन्द्र मोदी जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी की जो मांग है, वह मांग पूरी होनी चाहिए और आपको रिजाइन देना चाहिए। क्योंकि वहां 3-4 हजार माइनोरिटी के लोगों को मारने का काम भी वहां के लोगों ने किया और उनका पूरा सपोर्ट आपने किया था। सुमित्रा महाजन जी बहुत अच्छी हैं, मराठी में बोलती हैं, वे भी बी.जे.पी. की इतने साल तक अधिकारी रहीं, लेकिन उनके ऊपर भी अन्याय करने का प्रयत्न हुआ था। मेरे कहने का मतलब यह है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम अपनी पार्टी आर.पी.आई. आपका पूरा सपोर्ट करते हैं और शिवराज पाटिल जी ने देश की सुरक्षा का जो भी काम अपने हाथ में लिया है, उनका हम आदर करते हैं और वे जरूर हमारे देश में अच्छी सुरक्षा लाने का प्रयत्न करेंगे।

आप तो उपाध्यक्ष जी हैं, हमें और भी ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन हमारी एक पार्टी है â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाहर चले गये तो मैं क्या करता।

श्री रामदास आठवले : 2-2 मैम्बरों की पार्टी वालों को एक पार्टी बनानी होगी, इसलिए कि बहुत कम टाइम मिलता है, फिर भी आपने हमें टाइम दे दिया, धन्यवाद।

शिवराज पाटिल जी बहुत अच्छा काम करें, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए, हमारी डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार है, सोनिया गांधी जी के प्रयत्न से हम सब लोग सत्ता में आये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(Interruptions) â€¦

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

*(Interruptions)**

*Not Recorded.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Respected Deputy-Speaker Sir, I would like to sincerely thank the Chair for giving me this great opportunity to speak for my country.

At the very beginning of India's Independence, the Hindu activist Nathurarm Godse killed Bapuji. The only reason behind this killing was that Bapuji worked tirelessly for the cause of communal harmony between the Hindus and the Muslims and to avoid division of the nation. Sir, many sections of the people called the Hindu activist, Nathuram Godse as a Hindu patriot, But a majority of the Indians called him a Hindu militant. According to me, this very incident of the killing of Bapuji is the first threat to Indian internal security. When Pakistan instigated the invaders, they invaded Jammu and Kashmir and it was our great leader Pandit Nehru who dealt with them with an iron hand to guard the interest of the nation. I would like to remember the heroic courage shown by our Armed, Air Forces at that time. This House is the proper place to remember their sacrifice in guarding our motherland.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have only one more minute to speak.

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH : No, Sir. I am requesting the Chair to give me some more time to speak. We are a minority in number. Women parliamentarians are a few in number. I am seeking your goodself to come to our rescue.

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हाउस चाहे तो दो स्पीकर और हैं, उनको भी 2-2 मिनट बुला लिया जाये?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRIMATI TEJASWINI SEE RAMESH : The threat continued its legacy by continuing the dialogue with Pakistan to resolve the issue bilaterally. Afterwards, our great leader, Shrimati Indira Gandhi, laid down her great life to Khalistani militants. Again, the Sikh militants committed this heinous crime in the name of the glory of their religion. Shri Rajiv Gandhi sacrificed his precious life to protect our motherland from the most dreaded terrorist outfit called the LTTE. Comrade Safdar Hashmi, a great artiste, became a martyr to guard the secular ideology in which he believed. Like that, many activists in the Left Parties as well as many martyrs in the Indian National Congress contributed through their martyrdom to guard the secular fabric of India.

Today, in our time, Shrimati Sonia Gandhi sacrificed the highest chair of Prime Minister of the greatest democracy to guard the hard-earned communal harmony and the secular fabric of our Constitution which was protected throughout our history by our forefathers of the National Freedom Movement.

I was saddened seeing the intolerance shown by our learned parliamentarians like Uma Bhartiji and Sushma Swarajji by not accepting Sonia Gandhiji as the Prime Minister.

20.00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They are not the Members of the House and they are not present here.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Once she was a Parliamentarian. I referred to her as "learned Parliamentarian".

They have not only insulted Shrimati Sonia Gandhi as a person but also the nation by rejecting the victorious verdict given to the UPA Government, particularly under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi. I am of the opinion that at least they will appreciate the stand taken by Shrimati Sonia Gandhiji for giving the leadership of the Nation into the hands of statesman like Dr. Manmohan Singhji and the Home Affairs to our learned Parliamentarian, Shri Shivraj V. Patilji.

Religious militancy or communal militancy, whether it is Hindu militancy or Islamic militancy, is equally endangering our internal security. For example, in Gujarat, whether it is the burning of a moving train in Godhra, killing innocent people, or the post-Godhra incidents, killing innocent people, they are equally shameful acts in a civilised society. That is what I feel. There is a severe threat to internal security from the external factors and internal factors. They should be analysed and identified properly. The United State of America"s arms supply to Pakistan will boost the morale of terrorists inside the country. Secret operations of the CIA, in the name of Operation Brahmaputra, to sever the Seven Sisters is of grave concern. According to me, North-East is the strategic point in the interest of national integrity. Jammu and Kashmir is also a strategic point. One should look into these matters. The activities in the PoK are of grave concern to India. Our Ministers and our leaders are aware of the 69 terrorist camps that exist in the PoK. I hope my leadership is very much aware of it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Conclude please.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : I would like to refer to the activities of ISI and LTTE because many of my colleagues have not given much importance to this aspect. We are getting a greater threat from the lower ocean. All of us emphasize the importance of North-Eastern borders. But from the lower ocean we are getting threat from the LTTE and the ISI, which has extended its operations all over India. For example, when the Veerappan episode happened in my State, it is known that they had extended their contact with LTTE in Sri Lanka. They have drawn a Tamil nation map, in which Karnataka and other States are included. It is a dangerous development taking place. I appeal to the Government to pay attention to this aspect.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much. I heard the speeches of many Members of Parliament. I would like to compliment them for the words or rather wishes here in the Parliament and for their sympathetic stand during our struggle in the recent Manipur agitation. We are very hopeful that we are in the state of finding a solution. We place on record our appreciation for the action taken by hon. Prime Minister, hon. Home Minister, and hon. Minister of State for Home.

While talking about Manipur"s problem, just now a Member said that he is from Manipur and is a Naga. We Manipuris are very much in the main land of the nation. We got merged into India in 1949. After that, we were a part C State for quite a long time and we were Union Territory for some time. At that time, Nagaland, which was a district of Assam, was given Statehood. Out of anger and discontent, when Madam Indira Gandhi came to Manipur, we revolted against her. We were given Statehood only in 1972, along with Tripura. By that time, Meghalaya, a district of Assam, was given Statehood along with us. With all these things, discontentment was there. We do not say anything about this now. I was one of the first victims of this particular treatment. I do not blame anybody for that because I am now in Parliament speaking for the Indian integrity. For that matter, the incident was very simple.

Here, I narrate this simple incident. When I was facing the interview of the Union Public Service Commission, there was a column like: "Are you a citizen of India by birth or by domicile?" I put the mark against the column "domicile". The respected Chairman of the Commission was asking me: "Mr. Meinya, you are saying that you are a citizen of India by domicile." I said: "Yes, Sir, I was born in 1945. At that time, Manipur was a sovereign, independent State. I was born there. So, we got merged into the Indian Union in 1949. I became a citizen of India by naturalisation and not by birth." That was the first and last question. I was not selected. But even then I was not perturbed. Because I come, sit and now stand before you. Whatever good things we are now doing at the moment under the UPA Government to safeguard the territorial integrity of Manipur and the territorial integrity of the State should continue. We are very much thankful to them. Please keep this up. Please try to conquer the emotions of the people of the hilly region. People are emotional and they are sentimental. Once you conquer the emotions of the people, perhaps, you can solve all the problems.

With these words, I conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The list of speakers on this issue is over. The hon. Minister will reply tomorrow.

The House stands adjourned to meet tomorrow, 14th December, 2004 at 11 a.m.

20.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday, December 14, 2004/Agrahayana 23, 1926 (Saka).